Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

10 फरवरी, 2009

खण्ड 1, अंक 2

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 10 फरवरी, 2009

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2)1
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(2)23
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2)29
निन्दा प्रस्ताव/उसका वापिस लेना	(2)73
कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट में संशोधन	(2)83
घोषणाएं :	
(क) अध्यक्ष द्वारा :	
(i) चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची	(2)84
(ii) अनुपस्थिति के सम्बन्ध में सूचना	(2)84
(iii) अनुपस्थिति की अनुमति	(2)85
(ख) सचिव द्वारा :	
कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट	(2)86

सदन के कार्यक्रम में परिवर्तन	(2)90
सदन की मेज पर रखे जाने वाले/पुनः रखे जाने वाले कागज-पत्र	(2)91
विशेषाधिकार मामलों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति का प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना।	(2)94
वर्ष 1999-2000 से 2004-2005 तक की अवधि के दौरान सार्वजनिक सम्पत्तियों के हस्तांतरण/नीलामी/आबंटन की विस्तृत जांच करने के लिए हरियाणा विधान सभा की समिति का प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना।	(2)95
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा	(2)96
बैठक का समय बढ़ाना	(2)137
राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)	(2)137

Haryana Vidhan Sabha Secretariat
LIBRARY
Chandigarh

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 10 फरवरी, 2009

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में 2.00 बजे (अपराह्न) हुई। अध्यक्ष (श्री रघुवीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : ऑनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे।

Grace Marks given by H.B.S.E.

***1048. Shri Karan Singh Dalal :** Will the Education Education Minister be pleased to state whether the Haryana Board of School Education gave grace marks to the students of 8th and 10th in the Annual Examination held in the year 2007-08; if so, the criteria and objective thereof ?

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : श्रीमान् जी, एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखा जाता है।

वक्तव्य

हाँ श्रीमान् जी, निम्नलिखित मानदण्ड अपनाये गए :

1. कक्षा आठवीं

हिन्दी	5 अंक
गणित	15 अंक
सामाजिक विज्ञान	18 अंक
अंग्रेजी	12 अंक

सामान्य कृपांक 2.5 प्रतिशत, यदि किसी विद्यार्थी को इसकी आवश्यकता हो।

2. कक्षा दसवीं

अंग्रेजी	9 अंक

[श्री मांगे राम गुप्ता]

गणित 9 अंक

विज्ञान एवं तकनीकी 9 अंक

सामान्य कृपांक 2 प्रतिशत, यदि किसी विद्यार्थी को इसकी आवश्यकता हो।

कृपांक देने का उद्देश्य

सरकारी स्कूलों में आमतौर पर समाज के गरीब तबके के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। कृपांक देने का उद्देश्य स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों की दर को कम करना है क्योंकि विशेषकर 8वीं व 10वीं में असफल होने पर बहुत से विद्यार्थी स्कूल छोड़ देते हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो स्टेटमैंट सदन के पटल पर रखी है उसमें इन्होंने बताया है कि क्लास 8वीं और 10वीं के लिए इन्होंने ये ग्रेस मार्क्स दिये हैं। अध्यक्ष महोदय, जब इन्होंने यह कार्यक्रम बनाया था उस समय उस पर हरियाणा के शिक्षाविदों ने काफी टिप्पणियाँ की थीं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या ये इस बात से सहमत नहीं होंगे कि इस तरीके से ग्रेस मार्क्स देना शिक्षा प्रणाली और खासतौर से हमारे बच्चों की ऐलिमैंटरी एजूकेशन के हिसाब से ठीक नीति नहीं थी। क्या मंत्री जी इस मामले में कोई कमेटी बनाकर इस पर दोबारा विचार करेंगे? क्या इसकी समीक्षा करेंगे कि इस प्रकार का फैसला क्यों लिया गया?

श्री मँगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, यह कोई परमानैन्ट पॉलिसी एडॉप्ट नहीं की गई है। पिछले साल सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर कुछ कारणों से नीचे आ गया था उसके कारण सरकारी स्कूलों के रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आ रहे थे। सरकारी स्कूलों में ज्यादातर गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। अगर बच्चे ज्यादा फेल हो जायेंगे तो उनके दिमाग में टैन्शन हो जाती है और स्कूल छोड़ने की, ड्रॉप आउट करने की सम्भावना बढ़ जाती है। अध्यक्ष महोदय, सरकार की कोशिश यह रही है कि सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट करने की बजाय ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। अध्यक्ष महोदय, पढ़ाई का स्तर नीचे जाने के दो-चार कारण रहे हैं। एक तो सरकारी स्कूलों में टीचर्ज की भारी कमी रही है। अध्यापकों की भर्ती के ऊपर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी जिससे सरकारी स्कूलों में लगभग 20 हजार टीचर्ज की कमी हो गई थी। अध्यक्ष महोदय, दूसरा कारण रहा सैमैस्टर सिस्टम। एक रिपोर्ट आई थी कि सैमैस्टर सिस्टम बहुत अच्छा है और इसके लागू होने से शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। उसको बोर्ड ने लागू कर दिया। अध्यक्ष महोदय, सैमैस्टर सिस्टम लागू होने के कारण पहले सैमैस्टर में बच्चों को इसको समझने में परेशानी आई। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बताया कि सरकारी स्कूलों में गरीब परिवारों के बच्चे ही पढ़ते हैं और उनके माता-पिता भी ज्यादातर अनपढ़ ही होते हैं। वे उनको समझाने में असमर्थ रहते हैं जिसका असर बच्चों की पढ़ाई के ऊपर पड़ा। जिन बच्चों के माता-पिता पढ़े लिखे हैं वे बच्चे प्राईवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। यही कारण रहा कि सरकारी स्कूलों का ऐलिमैंटरी एजूकेशन का रिजल्ट डाउन आया।

सरकार ने देखा कि इतनी तादाद में बच्चे फेल हो गये तो बहुत से बच्चे ड्रॉप कर जायेंगे जो ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने ड्रॉप को बचाने के लिए ग्रेस मार्क्स देने का यह अस्थाई फैसला लिया ताकि उनको कुछ ग्रेस मार्क्स देकर रिजल्ट को कुछ अप किया जाये। इस ग्रेस मार्क्स की बुराई को दूर करने के लिए हमने कुछ फैसले लिये हैं ताकि हमारे सरकारी स्कूलों में ऐजूकेशन इम्प्रूव हो सके। अगर अच्छे टीचर्ज होंगे, वैल क्वालिफाईड टीचर्ज होंगे तो पढ़ाई अच्छी होगी। अध्यक्ष महोदय, हमने पाठ्य पुस्तकों की कमी को दूर करने का फैसला लिया है। पहले पूरा साल बीत जाता था, इम्तिहान आ जाते थे लेकिन किताबें नहीं मिलती थीं। जब बच्चे के पास किताबें ही नहीं होंगी तो वह पढ़ेगा क्या। अब हमने यह फैसला लिया है कि सत्र शुरू होने के पहले दिन से ही किताबें उपलब्ध होंगी। इससे काफी इम्प्रूवमैंट होगी। इस मामले में सरकार काफी चिंतित है। सरकार नहीं चाहती कि शिक्षा के मामले में कोई कमी रहे। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा में सुधार करने के लिए सरकार ने और भी बहुत से फैसले लिये हैं। मैं माननीय साथी से कहना चाहता हूँ कि शिक्षा में सुधार के लिए सरकार हर सम्भव कदम उठायेगी। पूरी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी हुई है उसमें माननीय साथी देख सकते हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के प्रयासों की हम सराहना करते हैं लेकिन मैं इस बात से उनसे इत्तेफाक और राय नहीं रखता हूँ। मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब वे अपने जवाब में खुद मान रहे हैं कि गरीबों के ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको अच्छी पढ़ाई करवाना, उनके लिए शिक्षात्व का अच्छा इन्तजाम करना उनका काम है। अगर उनकी पढ़ाई कमजोर है तो उस व्यवस्था के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए थी क्योंकि व्यवस्था ठीक न होने के कारण ही उनकी पढ़ाई ठीक नहीं हो रही थी। बजाये इसके कि हम ग्रेस मार्क्स दे कर बच्चों को पास करें और कमजोर नींव को आगे बढ़ाएं, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री जी से फिर से यह जानना चाहता हूँ कि चलिये कि इन्होंने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिये लेकिन क्या उन शिक्षकों ने, जिन्होंने बच्चों को ठीक पढ़ाई नहीं करवाई और बच्चों की ऐसी हालत होने लगी है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे?

श्री मांगे राम गुप्ता : स्पीकर सर, माननीय सदस्य की चिन्ता बिल्कुल वाजिब है। महकमा सरकार की हिदायत के मुताबिक इस पर विचार कर रहा है। जैसा कि मैंने कहा है कि किन हालात में ऐसा फैसला लेने में मजबूर हो गये कि लड़कों को फेल न किया जाए। अगर गरीबों के लड़के फेल हो जाएंगे तो वे ड्रॉप आउट कर जाएंगे। बड़ी मुश्किल से उन बच्चों को स्कूलों में लाया जा रहा था और यदि वे फेल कर दिए जाएं तो वे स्कूल छोड़ कर चले जाएंगे। उन गरीब बच्चों को पढ़ाना हमारे लिए बहुत जरूरी था और उसके लिए प्रयास किये जा रहे हैं। हमने कहा कि टीचर्ज में कुछ कमी थी जो ज्यादा क्वालीफाईड नहीं थे या फिर सिफारिशी थे या और भी कुछ कारण रहे हों जिनके कारण वे पढ़ाई ठीक से नहीं करवा रहे थे उनके खिलाफ हमने ऐक्शन भी लिया है और सख्त से सख्त कार्यवाही हम उनके रिजल्टस देखकर कर रहे हैं। ऐसे टीचर्ज जो पढ़ाई में इन्ट्रस्ट नहीं रखते और जिनके कारण बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है उनके बारे में हमने रिपोर्ट मांग रखी है। ऐसे टीचर्ज में से कुछ टीचर्ज के खिलाफ हमने कार्यवाही की है और कुछ के खिलाफ

[श्री मांगे राम गुप्ता]
जल्दी ही कार्यवाही करेंगे। अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो चिन्ता आपने महसूस की है इससे हम सहमत हैं कि पढ़ाई का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा होना चाहिए, इसमें कई ऐसे प्रयास किये गये हैं जिनसे इस साल की पढ़ाई के रिजल्टस में बहुत ही इम्प्रूवमैंट हो जाएगी।

श्री एस०एस० सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से एक बात जानना चाहता हूँ। माननीय मन्त्री जी इस बात से सहमत होंगे कि हरियाणा में पढ़ाई का जो लैवल है यह शर्मनाक हद तक नीचे है और इस सरकार ने इसको इम्प्रूव करने के लिए कई फैसले लिये हैं जिनके दूरगामी रिजल्टस होंगे जिनका पता बहुत देर के बाद लगेगा। एक तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि आज से पता नहीं कितने साल पहले यह फैसला लिया गया होगा कि पास मार्क्स 33% और फस्ट डिवीजन 61% मार्क्स होंगे। मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है कि जब 50% मार्क्स पास के लिए और फस्ट डिवीजन 75% से शुरू करें। स्पीकर सर, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो यह कोई पढ़ाई-वढ़ाई नहीं है। जहां तक गरीब आदमी के बच्चों की बात है, यह सच बात है कि विशेषतौर से गांवों में और छोटे शहरों में भी पढ़ाई का लैवल बहुत नीचे है। सरकार ने एक बहुत अच्छी बात की है कि जे०बी०टी० का शैक्षणिक स्तर 10 जमा 2 के बजाए ग्रेजुऐशन कर दिया है। स्पीकर सर, मैं समझता हूँ कि अब 10 जमा 2 को जे०बी०टी० में दाखिल नहीं करेंगे। इसी प्रकार से साईंस, इंगलिश और टैक्नॉलोजी की पढ़ाई में वे बिल्कुल जीरो हैं। जब तक यह नहीं होगा हरियाणा के समूचे प्रदेश में हम तरक्की नहीं कर सकेंगे और गरीब आदमी की भी तरक्की नहीं होगी। स्पीकर सर, मैंने इसके लिए यह जो मार्क्स की बात कही है क्या सरकार इस बारे में कोई आश्वासन देगी?

श्री मांगे राम गुप्ता : स्पीकर साहब, 33% पास मार्क्स का सिस्टम होते हुए यह रिजल्ट इतना डाउन आया है। अभी तो हमने रिजल्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए यह किया है ताकि लड़के फेल न हों। 33% मार्क्स में इतने ज्यादा लड़के फेल हो गये अगर पास मार्क्स 50% कर देंगे फिर तो लड़कों का पास होना बहुत मुश्किल हो जाएगा और रिजल्टस और भी बहुत ज्यादा डाउन हो जाएंगे। हमने ऐजूकेशन को इम्प्रूव करने के लिए यह किया है कि टीचर्ज अच्छी क्वालिटी के होंगे। स्पीकर सर, जैसे कि आप खुद सहमत हुए हैं कि हमने सैट टैस्ट लागू किया है और इसमें बी०ए० की क्वालिफिकेशन कम से कम की है। रिजल्टस अच्छा न आने की और भी कई वजहें थीं। किताबें समय पर नहीं मिलती थीं। गरीब बच्चों को सरकार की तरफ से समय पर फ्री किताबें दी जाएंगी ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई पूरे जोर-शोर से कर सकें। रिजल्ट एकदम सामने नहीं आता है उसमें समय लगता है। हम अभी इसको देख रहे हैं। इस साल का रिजल्ट अभी सामने आएगा तो पता चलेगा कि इसमें कितनी इम्प्रूवमैंट हुई है। अगर इस बार हमारे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, हमारे बच्चे अच्छे मार्कस लेकर आते हैं तो हम पासिंग परसैंटेज को बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के बारे में विचार करेंगे। जहां तक सुरजेवाला साहब ने साईंस और अंग्रेजी मीडियम की बात कही है, हमने इस बारे में प्रयास किए हैं, अब की बार हमने हरियाणा में अंग्रेजी मीडियम के स्कूल भी शुरू किए हैं। हालांकि इसमें

शुरू में बहुत दिक्कत आ रही है। अंग्रेजी मीडियम में हर सब्जैक्ट को पढ़ाने में टीचर्ज भी दिक्कत महसूस कर रहें हैं लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा साईंस के लिए हमने बहुत से स्कूलों को सिलैक्ट किया है। इस स्कीम के तहत बहुत से साईंस और कामर्स स्ट्रीम के स्कूल चालू हो रहे हैं।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मेरी सप्लीमैंटरी सुरजेवाला जी ने पूछ ली है जो कि मैं पूछना चाहती थी। फिर भी मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहूँगी कि अगर अगले समैस्टर में भी बच्चे फेल हो गए तो क्या उनको दोबारा से ग्रेस मार्कस देकर पास किया जाएगा क्या इसके बारे में विचार किया गया है क्योंकि इतनी जल्दी मार्कस इम्प्रूव नहीं होंगे।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैंने पहले ही कहा है कि यह ग्रेस मार्कस देने की हमारी कोई परमानैंट पॉलिसी नहीं है। अब की बार के हालात के मुताबिक विचार करके यह टैम्परेरी फैसला किया गया था। हमें उम्मीद है कि इस बार जो फर्स्ट और सैकेंड समैस्टर के रिजल्ट आएंगे वे अच्छे आएंगे और शायद ग्रेस मार्कस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि सरकारी स्कूलों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया था और इन्होंने ड्रॉप आउट को रोकने के लिए सरकारी स्कूलों में ग्रेस मार्कस दिए हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा प्राईवेट स्कूल से अपीयर होता है तो क्या ये ग्रेस मार्कस उसको भी दिए जाते हैं? इन्होंने अपने जवाब में माना है कि गरीब लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और उनको ही ग्रेस मार्कस दिए गए हैं।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि ग्रेस मार्कस का जहां तक ताल्लुक है, वह चाहे प्राईवेट स्कूल का बच्चा हो या सरकारी स्कूल का बच्चा हो उन सबको दिए गए हैं। इसमें मैं एक बात और क्लीयर करना चाहूँगा कि जो बच्चा प्वायंट पर फेल हो रहा था उन्हीं को ग्रेस मार्कस दिए गए हैं। इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं है। हम यह मानकर चलते हैं कि प्राईवेट स्कूलों के रिजल्ट्स गवर्नमैंट स्कूलों से बहुत अच्छे हैं।

प्रो० छत्तर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में जो शिक्षा कि ढांचे पर चर्चा हो रही है यह बहुत अच्छा सवाल सदन में उठाया गया है। मंत्री जी ने इसके बारे में बहुत अच्छा जवाब दिया है। मंत्री जी ने जब ग्रेस मार्कस के सवाल का जवाब तैयार किया होगा तो उस वक्त इन्होंने महकमें से भी पूछा होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब से हरियाणा बना है.....

श्री अध्यक्ष : क्या आप यह सोचते हैं ये अपने आप जवाब दे रहे हैं? आपको भी पता है कि सवाल का जवाब देने से पहले महकमे से डिस्कशन होती है, कंसलटेशन ली जाती है। जब आपको सब कुछ पता है तो आप व्यवस्था का प्रश्न क्यों उठाते हैं। आप सिर्फ अपना सवाल पूछें।

प्रो० छत्तर पाल सिंह : स्पीकर सर, मेरा सवाल इस बात पर आधारित है कि आप और मंत्री जी यह न कह दें कि यह पोसिबल नहीं है। स्पीकर सर, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि वर्ष 2007-2008 के अलावा अब तक कितने सालों में 8वीं और 10वीं में ग्रेस मार्कस दिए गए हैं? मंत्री जी ने आज जवाब दिया है कि हमें इस पर लोट ऑफ इम्प्रूवमैंट करने की जरूरत है। प्रजातांत्रिक सिस्टम में अगर सच पूछें तो देहात के अन्दर मास्टर सबसे बड़ा राजनीतिक व्यक्ति है। वह सरकार के बस का मसला नहीं है। मैंने यह सवाल जो पूछा था वह पैदा होता है कि 8वीं और 10वीं तक कितने सालों तक ग्रेस मार्कस दिए गए हैं। प्राईवेट सिस्टम में और सरकारी सिस्टम में कम्पीटिशन नहीं हो पा रहा है। हम प्राईवेट सिस्टम से बहुत नीचे खड़े हैं। हमारे पास आई०ए०एस० अधिकारी हैं, एजुकेटिड आफिसर्ज हैं, मिनिस्टर्ज हैं, यहां तक कि सारा तामझाम है, इसके बावजूद हम स्कूलों में अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। क्या सरकार ने इस बारे में कोई परमानैंट सोल्यूशन निकाला है। जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा क्या उसकी सैलरी में डिडक्शन करके उसकी अकाउन्टेबीलिटी की जाएगी। इसके अलावा सरकार की ट्रांसफर पालिसी है कि अगर एक मास्टर 4-5 साल एक स्कूल में पढ़ाएगा और उसका रिजल्ट अच्छा आएगा तो उसको इन्सैंटिव देंगे। क्या ऐसा कोई परमानैंट सोल्यूशन है so that we may have a better system of education in the Village Government Schools. क्या सरकार ने ऐसा किया है और कितने ग्रेस मार्कस अब तक दिए गए हैं?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूँगा कि ग्रेस मार्कस की जहां तक बात है, यह कोई परमानैंट सिस्टम या पॉलिसी नहीं थी। यह तो जरूरत के मुताबिक किया गया फैसला था क्योंकि लड़के ज्यादा फेल हो गए थे। छत्तर पाल जी, आपको भी पता है कि सी०बी०एस०ई० में 10वीं की फाईनल परीक्षा से पहले इन्टरनल एग्जाम्ज होते हैं। हमारी कोशिश यह रही है कि बच्चे फेल न हों। हमने आठवीं कक्षा का भी इम्तिहान लिया है लेकिन जब यह महसूस किया गया कि गरीब बच्चे अगर फेल हो जाएंगे तो वह ड्रॉप कर जाएंगे इसलिए ग्रेस मार्कस देने की बात सोची गयी। स्पीकर साहब, मैंने शिक्षा के स्तर को इम्प्रूव करने के लिए दो तीन रीजंज दिए हैं। पहले तो सरकारी स्कूलों में टीचर्ज ही नहीं थे। हाई कोर्ट के बैन की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत आ गयी थी। ऐलीमैंट्री स्कूलों के टीचर्ज की तीस हजार पोस्टस खाली थीं। स्पीकर सर, अगर पढ़ाने वाले टीचर्ज ही न हों तो पढ़ाई की वीकनैस तो रहेगी ही। इसके अलावा किताबों की बहुत ज्यादा दिक्कत थी। पूरा साल निकल जाता था लेकिन किताबें भी समय पर छपकर नहीं आती थीं इसलिए हमने इसको भी इम्प्रूव किया है। स्पीकर साहब, हमने हार्ड फैसला किया है कि जब पढ़ाई का नया सैशन शुरू होगा तो उस समय ही बच्चों के हाथों में फ्री किताबें सरकार देगी। किताबों की कोई कीमत नहीं होगी और न ही ये बाजार से खरीदनी पड़ेंगी। जहां तक ग्रेस मार्क्स देने का प्रश्न है, मेरे पास सारी सूचना है इसलिए मैं इनको बता देता हूँ कि वर्ष 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 और 2008 में भी ग्रेस मार्क्स देकर कुछ बच्चे पास किए गए थे।

तारांकित प्रश्न संख्या 1081

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री रणबीर सिंह महेन्द्रा सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Maintenance of Existing By-Pass in Bhiwani by P.W.D. (B&R)

*1066. **Dr. Shiv Shankar Bhardwaj** : Will the P.W.D. (B&R) Minister be pleased to state whether it is a fact that half portion (Loharu road to Tosham road) of existing Bhiwani by pass is under the control of HSAMB and other half (Tosham road to Hansi road) is under the control of P.W.D. (B&R), Haryana; if so, whether there is any proposal to hand over the whole by pass to P.W.D. (B&R) for proper maintenance ?

Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : Yes Sir, but there is no such proposal.

डॉ० शिव शंकर भारद्वाज : स्पीकर साहब, एक ही शहर में एक ही सड़क आधी किसी एक विभाग के पास है और आधी किसी दूसरे विभाग के पास है। आधी सड़क का रंग रूप कुछ और है और आधी सड़क का रंग रूप कुछ और है। आधी सड़क में बहुत ज्यादा गढ्ढे हैं और आधी सड़क में रैगुलर मेंटीनैंस अगर हो तो यह बहुत बुरा लगता है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि अगर यह सड़क एक ही विभाग के पास दे दी जाए तो इसमें क्या बुराई है? यह व्यवस्था बुरी है इसलिए क्या इसको ठीक करने के लिए मंत्री जी कोई प्रयत्न करेंगे?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, माननीय मैम्बर ने जो अपना कंसर्न बताया है वह बिल्कुल सही है। जो यह बाईपास है इसका एक पोर्शन भिवानी-लोहारू से भिवानी-तोशाम तक तकरीबन साढ़े चार किलोमीटर खराब है। यह पोर्शन ऐग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के पास है। भिवानी-तोशाम रोड से भिवानी-हांसी रोड तक का जो पोर्शन है वह ढाई किलोमीटर है जोकि पी०डब्ल्यू०डी० (बी० एण्ड आर०) के पास है। इस सड़क का जो टुकड़ा मार्केटिंग बोर्ड के पास है उसकी हालत काफी खराब है। जो पोर्शन मार्केटिंग बोर्ड के पास है उसकी मेंटीनैंस के लिए 24 दिसम्बर को मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से टैंडर हो चुके हैं और इसका वर्क अलॉट कर दिया गया है। हमें उम्मीद है कि मई, 2009 तक यह रिपेयर हो जाएगा। स्पीकर साहब, इनकी बात बिल्कुल वाजिब है वहां पर पैसैंजर्स का थ्रूनिट तकरीबन 16-17 पी०सी०यू० है यानी दिन में उस रोड पर 6-7 हजार गाड़िया रोजाना निकलती हैं। मैं समझता हूँ कि मार्केटिंग बोर्ड उस सड़क के अपने पोर्शन की मेंटीनैंस नहीं कर पाएगा इसलिए मैंने सैक्रेटरी,पी०डब्ल्यू०डी० (बी० एण्ड आर०) को आदेश दिये हैं कि वे सैक्रेटरी ऐग्रीकल्चर से इस बारे में मीटिंग करें ताकि जो पोर्शन उस सड़क का मार्केटिंग बोर्ड के पास है उसको हमारा विभाग टेक ओवर कर ले। उस बाई-पास पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है इसलिए वह रोड हमारे विभाग के पास होनी चाहिए। स्पीकर सर, हमारे विभाग के सैक्रेटरी उनसे बातचीत कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप केवल एक सड़क के बारे में ही कह रहे हैं या फिर राज्य की दूसरी सड़कों के बारे में भी कह रहे हैं। मार्केटिंग बोर्ड की जो पुरानी सड़कें हैं उनकी मेंटीनैंस आपके विभाग के हाथ में है या मार्केटिंग बोर्ड के हाथ में है? सड़क का मतलब तो पी०डब्ल्यू०डी० (बी० एण्ड आर०) ही होता है। चट्ठा साहब को तो इस बारे में कोई याद नहीं करता।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, मैं केवल इस बाई-पास के बारे में ही कह रहा हूँ। जितनी भी सड़कें मार्केटिंग बोर्ड के पास हैं उन सबकी हम रिपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतने फंडज हमारे पास नहीं है। मार्केटिंग बोर्ड के पास फंडज हैं और जो रोडज वे बनाते हैं उनकी रिपेयर भी वे ही करते हैं। जो यह बाई-पास है इसको हम एज ए स्पेशल केस टेक अप कर लेंगे ताकि इसकी मेंटीनैंस ठीक तरह से हो सके। वर्ष 2009-10 का हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हम इस सड़क के अपने पोर्शन की जरूर रिपेयर करेंगे। मार्केटिंग बोर्ड वाले उस सड़क का अपना पोर्शन ठीक कर देंगे लेकिन इस पूरी सड़क को टेकओवर करने की प्रक्रिया हम शुरू कर देंगे।

डॉ० शिव शंकर भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, यह जो दादरी-लोहारू रोड से तोशाम रोड और तोशाम रोड से हांसी रोड तक बाई-पास है उस पर भारी तादाद में वाहन चलते हैं क्योंकि उस एरिया में रोड़ी की सप्लाई खानक से होती है, वह सारा माल इन रोड्ज से जाता है। मैं इस बात के लिए तो मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने यह बात स्वीकार कर ली है कि इस रोड की मेंटीनैंस लोक निर्माण विभाग से करवाएंगे लेकिन साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूँगा कि क्या इसको थोड़ा सा और स्ट्रैंथन करने का विचार है? दूसरे भिवानी में इसके अलावा और कोई बाई-पास नहीं है। रोहतक रोड से मेहम रोड तक और रोहतक रोड से दादरी रोड तक कई वर्षों से बाई-पास की सख्त जरूरत है, क्या मंत्री जी इस पर भी गौर करेंगे?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, सड़क की रिपेयर के बारे में मैं कह चुका हूँ कि उसमें हमारा जो ढाई किलोमीटर का पोर्शन है उसकी रिपेयर हम कराएंगे। जो पोर्शन मार्किटिंग बोर्ड के पास है उसके टैंडर कर दिये गए हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, क्या दादरी से मेहम, रोहतक से दादरी और रोहतक से मेहम तक बाई-पास बनवाएंगे?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, अभी जो ऐग्जिस्टिंग बाई-पास है मैंने उसकी रिपेयर की बात कही है। जो माननीय सदस्य की नये बाई-पास की मांग है उसके बारे में हम सर्वे कराएंगे उसके बाद ही मैं कुछ कह सकता हूँ।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सिरसा मिनी बाई-पास का निर्माण कार्य पी०डब्ल्यू०डी० (बी० एण्ड आर०) के पास है और चतरगढ़ पट्टी तक 200-300 गज का एरिया कई महीनों से अधूरा पड़ा है उसके बारे में क्या मंत्री जी कोई कार्यवाही करवाएंगे?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, सिरसा में एक बाई-पास हम प्रपोज कर

रहे हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, यह कह रहे हैं कि बाई-पास ऑलरेडी है उसके थोड़े से टुकड़े का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, उसके बारे में ये सैपरेट नोटिस दे दें।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, टुकड़ा अधूरा पड़ा है तो कह दें कि बनवा देंगे।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, नॉर्मली बाई-पास के निर्माण का कार्य पी०डब्ल्यू०डी० (बी० एण्ड आर०) के पास होता है। 15.69 किलो मीटर का बाई-पास सिरसा में प्रपोज्ड है उस पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 12 करोड़ रुपये आएगी। उसकी टोटल कॉस्ट 21.49 करोड़ रुपये है। वह हम प्रपोज कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कप्तान साहब, इन्दौरा जी किसी नये बाई-पास की बात नहीं कर रहे हैं। ये मिनी बाई-पास के बारे में कह रहे हैं और वह भी अप्रूव्ड है उसका टुकड़ा बाकी है क्या उसको पूरा करवाओगे या नहीं, यह बताएं?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में चैक करके ही कोई जवाब दे सकता हूँ। हमें फंड्ज देखने पड़ते हैं, बजट प्रोविज़न देखने पड़ते हैं। मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ। मुझे सारा मैटर देखना पड़ेगा। यह भी देखना पड़ेगा कि उस पर कितना ट्रैफिक है तभी इस बारे में मैं कुछ बता सकता हूँ।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, सिरसा में एक ओवर ब्रिज बन रहा है उससे काफी ट्रैफिक कंजैशन होगी और लोगों को बड़ी भारी दिक्कत होगी। वहां बाई-पास बन जाए और फाटक बन जाए तो काफी सुविधा हो जाएगी। क्या मंत्री जी इसको जल्दी करवाने की व्यवस्था करेंगे?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जो बाई-पास प्रपोज्ड है उसमें इनका यह बाई-पास भी कवर हो रहा है इसलिए इसके लिए ये सैपरेट नोटिस दे दें तभी देखूंगा।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, इन्दौरा जी मिनी बाई-पास की बात कर रहे हैं। उसका टैंडर भी हो चुका है और पैसे भी गए हुए हैं उसका कुछ पोर्शन बाकी है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, वह अभी प्रपोज्ड बाई-पास है।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, आप लिख कर भिजवा देना।

श्री रमेश गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, वैसे मेरे सवाल का भारद्वाज साहब के सवाल से कोई लिंक नहीं है लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि कुरुक्षेत्र से ढांड और लाडवा से मुस्तफाबाद तक सड़क की बहुत ही खस्ता हालत है। ये पी०डब्ल्यू०डी० की सड़कें हैं और इन पर व्हीकल चलना तो दूर की बात है पैदल चलना भी मुश्किल है। हम कई बार इस बारे में विभाग के नोटिस में लाए हैं लेकिन अभी तक रिपेयर का काम शुरू नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, आप इस बारे में नोटिस भिजवा देना।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 1996-97 में कुछ सड़कें पंचायती राज विभाग द्वारा बनाई गई थी। अब वह महकमा न तो सड़कों की मरम्मत कर रहा है और न ही निर्माण कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के की तीन सड़कें जो पंचायती राज के महकमे ने बनाई थीं वह बिल्कुल टूट गई हैं और वह महकमा उन सड़कों को ठीक नहीं कर रहा है। क्या मंत्री जी उन सड़कों को पी०डब्ल्यू०डी० महकमें के अधीन टेक ओवर करके उनकी रिपेयर करवायेंगे?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जो सड़कें पंचायती राज महकमें ने बनाई थीं हम उन सड़कों को टेक ओवर कर रहे हैं और उन सभी सड़कों की रिपेयर भी करवायेंगे।

श्री साहिदा खान : अध्यक्ष महोदय, तावडू शहर में एण्ट्री करते हैं तो कोई भी पी०डब्ल्यू०डी० महकमें की सड़क ठीक नहीं है। चाहे नूंह हैडक्वार्टर की सड़क हो, चाहे मोगीपुर रोड हो और चाहे बावला रोड, छारोड़ा रोड जाता है इन सभी रोड्ज में गड्ढे हो रहे हैं। नैशनल हाई-वे नं० 71-बी वाली सड़क का भी हाल बुरा है। आदमी यह सोचकर जाता है कि यह नेशनल हाई-वे की सड़क है परन्तु उस सड़क का भी हाल बुरा है। दूसरी सड़क मेरे गांव शिकारपुर वाली सड़क है उसका भी बुरा हाल है। मोहम्मदपुर अहीर से नौरंगपुर होते हुए जो सड़क गुड़गांव को जाती है और जो पटौदी को सड़क जाती है उसका भी बुरा हाल है। इस प्रकार से तावडू शहर में एक भी बढ़िया सड़क से एण्ट्री नहीं है। अढ़ाई साल हो गये हैं इन सभी सड़कों का बुरा हाल है जबकि मंत्री जी हमारी ग्रीवेन्सिज कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। मैंने पिछले सदन में भी इस बारे में बात की थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री जी इन सड़कों की मरम्मत करवाने का काम करेंगे? अगर मरम्मत नहीं तो कम-से-कम क्या वे इन सड़कों के गड्ढे भरवाने का काम करेंगे?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, तावडू और नूंह की सड़क के बारे में माननीय सदस्य ने जिक्र किया है। इस सड़क की हम वाईडनिंग और रिपेयर करवायेंगे। इन सड़कों को हमने एन०सी०आर० के तहत ले लिया है और इनकी रिपेयर का काम भी शुरू हो गया है। दूसरा जो इन्होंने नेशनल हाई-वे वाली सड़क का जिक्र किया है, इसके लिए टैण्डर इन्वाईट कर दिया है और इस सड़क की रिपेयर का काम हम करवायेंगे। गुड़गांव से नूंह वाली सड़क को भी हमने एन०सी०आर० के तहत ले लिया है और 450 करोड़ रुपये अकेले मेवात के एरिया की सड़कों को ठीक करने के लिए पास किये गये हैं और रिपेयर का काम भी शुरू कर दिया गया है।

आई०जी० शेर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पी०डब्ल्यू०डी० या मार्केटिंग बोर्ड द्वारा जो सड़कें बनाई जाती हैं क्या उन सड़कों की क्वालिटी के बारे में उन अधिकारियों की कोई एकाउंटेबिलिटी होती है जिनकी

देख-रेख में ये सड़कें बनाई जाती हैं? अगर क्वालिटी सही नहीं पाई गई तो क्या उन अधिकारियों के खिलाफ विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जाती है?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो पी०डब्ल्यू०डी० महकमे द्वारा जो सड़कें बनाई जाती हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होती है और विभाग ने एक क्वालिटी कन्ट्रोल विंग बनाया हुआ है जो बाकायदा इसके बारे में चैक करता है। अभी तक तो मेरे नोटिस में ऐसा कोई केस नहीं आया है। अगर माननीय सदस्य के पास इस बारे में कोई स्पैस्फिक कम्प्लेंट है तो वह मुझे बतायें उसके बारे में इंक्वायरी करवाकर जो दोषी पाये जायेंगे उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही जरूर की जायेगी।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : अध्यक्ष महोदय, जैसा की यह सड़कों के बारे में प्रश्न चल रहा है। मेरे हल्के के गांव ढाणी कुतुबपुर और खरकड़ा से हांसी की जो रोड है वे आधी पी०डब्ल्यू०डी० द्वारा बनाई गई थी और आधी मार्केटिंग बोर्ड द्वारा बनाई गई थी लेकिन वे सड़कें अब टूट गई हैं। कोई ऐसा प्रबन्ध किया जाए कि सारी सड़क एक ही विभाग द्वारा बनाई जाए ताकि उनको सही तरह बनाया जा सके। इसी प्रकार से हांसी-उमरा की सड़क पी०डब्ल्यू०डी० द्वारा बनाई गई थी और वह सड़क छः महीने से पहले ही टूट गई। क्या इस के बारे में मंत्री जी कोई इंक्वायरी करवायेंगे? ठेकेदार बीच में ही काम छोड़कर गलत काम करते हैं। क्या मंत्री जी इन सड़कों को दोबारा से बनवायेंगे?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि कुछ रोड्ज पी०डब्ल्यू०डी० ने बनाई थीं वह टूट गयी हैं। वैसे तो रूरल एरिया में कुछ सड़कें मार्केटिंग बोर्ड बनाता है और कुछ हमारा महकमा बनाता है। हांसी-उमरा सड़क का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है, इसके बारे में विभाग बाकायदा इंक्वायरी करवायेगा और जो अधिकारी दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही भी की जायेगी।

चौ० अर्जन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूँ कि मेरे हल्के में जो पी०डब्ल्यू०डी० की सड़कें हैं या मार्किटिंग बोर्ड की सड़कें हैं, ये सड़कें कागजों में ही रह रही हैं। हमारे यहां क्रशर जोन होने के कारण हजारों गाड़ियां रोज यहां से गुजरती हैं। कोई छोटी सी सड़क भी हमारे यहां नहीं जोड़ी गई है। किसी सड़क को बनाने में साल डेढ़ साल लग जाता है लेकिन टूटने में देर नहीं लगती। हमारे यहां की बी०के०डी० रोड ठीक नहीं हुई है। ट्रालियां भर भर कर इन सड़कों से गुजरती हैं और इन ट्रालियों की वजह से रोज कोई न कोई सड़क टूट जाती है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूँ कि बी०के०डी० रोड के लिए हमने बी०ओ०डी० बेसिज पर कोशिश की लेकिन कोई भी बिडर नहीं आया। अब हमने हुडको से लोन लेकर केस उनको भेज दिया है। बी०के०डी० रोड को जल्दी ठीक करवा देंगे। अध्यक्ष महोदय, इनके एरियाज में क्वैरीज रोड हैं इसलिए दिक्कत आ रही है। इनके यहां की सड़कों से ट्रक इतने ओवर लोडिड होकर गुजरते हैं कि कोई भी सड़क बना दो वह टूट जाती है इसलिए या तो आर०टी०ओ० के ऑफिसर्ज से चैक करवाया जाए कि इन सड़कों से गाड़ियां ओवर लोडिड न जाएं। ओवर लोडिड गाड़ियों की वजह से ही इन सड़कों की हालत खराब है।

[कैप्टन अजय सिंह यादव]
इनके एरियाज में ज्यादा क्वैरीज रोड हैं जिसकी वजह से हालत खराब है, अगर हम रिपेयर करवा भी देते हैं तब भी टूट जाती हैं।

श्री अध्यक्ष : कप्तान साहब, आप इसका स्पैसिफिकेशन बढ़ा दो।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इन सड़कों पर गाड़ियां 60-60 टन तक माल उठाकर चलती हैं जिसकी वजह से ये सड़कें टूट जाती हैं।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि न केवल कलायत में बल्कि पूरे हरियाणा में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। हमारे कलायत शहर में मेन रेलवे रोड है उसका काम 2006 के शुरू में शुरू हुआ था। आज भी उसमें कभी डिवाइडर बन जाता है, कभी सड़क बन जाती है कभी सड़क टूट जाती है। एस्टीमेट्स रिवाइज होने के बाद भी उसमें गड्ढे पड़े हुए हैं। हमने लिखित में भी मंत्री महोदय जी को शिकायतें की हैं क्योंकि वहां काफी पानी भरा रहता है जिसकी वजह से रोज एक्सीडैंट्स होते हैं और कई मौतें भी होती हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने कलायत हल्के की रेलवे रोड का जिक्र किया है, हम अधिकारियों से कहकर इस सड़क की रिपेयर करवा देंगे।

प्रो० छत्तरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिला हिसार में कैनाला गांव से दौलतपुर गांव तक 1990 में पी०डब्ल्यू०डी०, बी०एण्ड आर० विभाग द्वारा कुछ लाख रुपये से आधी सड़क को बनाया गया था लेकिन उस की कम्पलीशन के ऊपर कोई काम नहीं किया गया। पिछले सैशन में भी मैंने यह सवाल किया था। जो पैसा लगा हुआ है वह बेकार जा रहा है, विलेजिज का लिंक जब तक पूरा नहीं होता, तब तक बसें उस पर नहीं चल सकतीं और उसका लोग फायदा नहीं उठा सकते।

श्री अध्यक्ष : पिछले सैशन में आपने क्या सवाल किया था?

प्रो० छत्तरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, पिछले सैशन में मैंने सवाल किया था कि कैनाला से दौलतपुर जो सड़क है वह अनकम्पलीट है।

श्री अध्यक्ष : उस समय आपको क्या जवाब मिला था?

प्रो० छत्तरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने आश्वासन दिया था कि उसको कम्पलीट करवाएंगे लेकिन अभी तक कम्पलीशन का काम नहीं किया गया है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी बताएंगे कि यह सड़क नई है या पुरानी है।

प्रो० छत्तरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि यह नई सड़क है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सड़क अधूरी होने का सवाल है, मेरी नॉलेज में नहीं है कि इन्होंने पिछले सैशन में इस सड़क का जिक्र किया हो। हम इसको चैक करवा लेंगे और अगर यह सड़क अधूरी बनी हुई है तो इसको पूरा करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप कैपेबल मंत्री हैं और आपकी टीम बड़ी कम्पिटैंट है। ये जो चारों तरफ सड़कों की बात हो रही है। ऑनरेबल मैम्बर्ज के जो सुझाव हैं, उनकी जो प्रोब्लम्ज हैं वह आप देखें। कोई मैम्बर कह रहा है कि उनकी सड़क 6 महीने में टूट जाती है कोई कह रहा है कि उनके यहां की सड़क पूरी नहीं हुई और कोई बाई-पास के बारे में कह रहा है। आप पूरी तरह से मोनीटरिंग करके काइंडली पर्सनल अटैंशन लेकर इन सड़कों को ठीक करवाएं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हम मोनीटरिंग कर रहे हैं और हम पर्सनल अटैंशन लेकर इन सड़कों को ठीक करवाएंगे।

श्री उदय भान : स्पीकर सर, पलवल से हसनपुर वाया रसूलपुर-बड़ौली सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत किया गया था, यह सड़क 6 महीने के अन्दर ही टूट गई। मैंने यह बात पिछले सैशन के दौरान भी मंत्री जी के ध्यान में लाई थी और उस समय मंत्री जी ने अश्योर किया था कि प्रायरटी के आधार पर जल्दी ही इन सड़कों को ठीक करवा दिया जायेगा या दोबारा बनवा दिया जायेगा लेकिन अभी तक इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुई। दूसरा जो रसूलपुर से हसनपुर रोड है वह भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। पहले इस सड़क का निर्माण भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत करवाये जाने की बात कही गई थी लेकिन अभी तक इस बारे में भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इन सड़कों को कब तक ठीक करवा दिया जायेगा?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जिन सड़कों का निर्माण किया जाता है उनकी रिपेयर का पीरियड तीन साल का होता है। तीन साल के अन्दर अगर सड़क टूटती है तो उसकी रिपेयर सम्बन्धित कंट्रैक्टर को करनी होती है। जहां तक पलवल से हसनपुर सड़क की बात है, हम इसको एग्जामिन करवाकर इसकी रिपेयर करवायेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम इसको दोबारा भी बनवायेंगे। स्पीकर सर, उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है क्योंकि हमें पी०एम०जी०एस०वाई० कार्यालय या नाबार्ड, जिससे भी हमें नई सड़क बनवानी होती है, उनको कम्पलीट केस भेजना पड़ता है। जहां तक रिपेयर की बात है, रिपेयर भी एकदम नहीं हो सकती क्योंकि उसके लिए भी कुछ आरम्भिक कार्यवाही करनी अपेक्षित होती है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहूँगा कि हम इस सड़क को जल्दी से जल्दी रिपेयर करवायेंगे। दूसरा जो इन्होंने रसूलपुर-हसनपुर रोड का जिक्र किया है हम इसको भी एग्जामिन करवाकर रिपेयर करवायेंगे।

श्री रामकला चिड़ाना : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से गोहाना बाई-पास की लैटैस्ट पोजीशन के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि इसको कब तक बनवा दिया जायेगा?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि गोहाना बाई-पास का निर्माण नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ इण्डिया द्वारा किया जायेगा और इसका निर्माण कार्य वर्ष 2011 के अंत तक पूरा हो जायेगा।

श्री रामफल चिड़ाना : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूँ कि ड्रेन नम्बर 8 बाई-पास के ऊपर पुल कब तक बनवा दिया जायेगा?

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, इस प्रकार से मेरे लिए सभी माननीय सदस्यों को जवाब देना मुश्किल हो जायेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे इसके लिए मुझे अलग से लिख कर दे दें तो मैं उनको वास्तविक स्थिति से अवगत करवा दूंगा। जहां तक ड्रेन नम्बर 8 पर बनने वाले पुल का सम्बन्ध है, उसका निर्माण मार्केटिंग बोर्ड द्वारा किया जायेगा।

श्री राम कुमार गौतम : स्पीकर सर, एक सड़क बड़ छप्पर से पुठी तक है जिस पर पिछले लगभग सात साल से काम अधूरा पड़ा है। इस सड़क का सवाल मैंने कई बार उठाया है लेकिन अभी तक भी उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। वह सड़क काफी समय से ऐसी की ऐसी पड़ी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस सड़क का निर्माण कार्य कब तक पूरा करवा दिया जायेगा?

श्री अध्यक्ष : गौतम जी, क्या आपने पहले भी इस बारे में सवाल पूछा था?

श्री राम कुमार गौतम : जी सर, मैंने पहले भी इस बारे में सवाल पूछा था?

श्री अध्यक्ष : उस समय आपको क्या जवाब दिया गया था?

श्री राम कुमार गौतम : स्पीकर सर, उस समय मुझे यह बताया गया था कि जिस ठेकेदार को उक्त सड़क का काम सौंपा गया था वह भाग गया है और सरकार द्वारा उसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। स्पीकर सर, मैं तो यही चाहता हूँ कि उस सड़क का निर्माण जल्दी से जल्दी करवा दिया जाये क्योंकि उसके अण्डर कंस्ट्रक्शन होने से लोगों को बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि हम एग्जामिन करवाकर शीघ्र ही इस सड़क को कम्पलीट करवा देंगे।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह सवाल ख़ास था लेकिन अब यह सड़कों का सवाल आम हो गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कुछ जानना चाहूँगा और एक सुझाव भी देना चाहूँगा। जब से यह सरकार बनी है तब से हर विभाग के बजट में बेतहाशा वृद्धि हुई है। पी०डब्ल्यू०डी० विभाग का बजट भी बहुत बढ़ा है और सरकार द्वारा बहुत सी सड़कें बनाने का प्रयास भी किया गया है। हाउस में इस सवाल के ऊपर ख़ास चिन्ता जाहिर की गई है कि इतना बजट होने के बावजूद भी बहुत सी सड़कें

अधूरी पड़ी हैं और जो बनी हुई हैं उनकी भी यही शिकायत है कि वे भी टूटी पड़ी हैं। सभी सदस्यों की यही शिकायत है कि सड़कें टुटी पड़ी हैं, उनमें गड्ढे हो गये हैं। मैं अपने हल्के के बारे में तो इसलिए नहीं कहना चाहूँगा कि यह सवाल ही दूसरा था लेकिन स्थिति मेरे हल्के में भी ऐसी ही है। सड़कें बनने के कुछ ही दिन बाद टूट गई हैं चाहे वे प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़कें हों या नाबार्ड की सड़कें हों। अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि इसके लिए हाउस की या उच्च अधिकारियों की कमेटी बनाएं जो इस मामले की जाँच कर सकें या सर्वे करके रिपोर्ट सौंप सकें?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हाउस की चिन्ता वाजिब है। पिछले साल बारिश बहुत हुई थी इसलिए सड़कें ज्यादा टूट गई हैं। जहाँ तक कमेटी की बात है, इस मामले में हम हाउस कमेटी की बजाय अधिकारी स्तर पर चैक करवा लेंगे। जहाँ-जहाँ ऐसी सड़कें हैं जिनकी हालत बहुत खराब है उनको हम चैक करवा लेंगे। अगर सैन्स ऑफ हाउस होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हाउस कमेटी भी बना दें और वह चैक कर ले लेकिन मैं समझता हूँ कि उसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 2009-10 में हमने तकरीबन 750 करोड़ रुपये सरकार से मांगे हैं, बजट में प्रोविजन किया जाये ताकि हम सड़कों की रिपेयर कर सकें लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारे पास कुछ फण्ड्ज की कमी थी जिस कारण इस साल में हम सारी सड़कों की रिपेयर नहीं कर सके। जितना काम इस योजना में सड़कों के ऊपर हुआ है उतना आज से पहले कभी नहीं हुआ चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हो चाहे नाबार्ड के तहत हो। जहाँ तक सवाल है सड़कों के टूटने का, तो जहाँ-जहाँ ऐसी शिकायतें आयेंगी उनको हम चैक करवायेंगे और जाँच भी करवा लेंगे और जहाँ भी कमी होगी हम उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही भी करेंगे।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की सड़कों के बारे में प्रश्न उठाये और माननीय मंत्री जी ने सभी क्षेत्रों की जो जानकारी इस समय उपलब्ध थी वह सदन के सामने रखी है। माननीय साथी चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह ने भी यह प्रश्न उठाया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पिछले 4 साल में बी० एण्ड आर० की 551 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण करवाया है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूँगा कि वर्ष 2008-09 में जैसा कि मंत्री जी ने बताया जो इस समय चालू साल है, केवल कंस्ट्रक्शन और रिपेयर पर तकरीबन 800 करोड़ रुपये सरकार खर्च कर रही है। हमारे विपक्ष और पक्ष के साथियों ने जो प्रश्न उठाये हैं उनकी बात वाजिब है। इस समय हमारे पास 734 नई सड़कों की माँग है जिनकी लम्बाई 2464 किलोमीटर है। अगर सरकार इन सारी माँगों को मानती है तो उसके लिए कम से कम 600 या 700 करोड़ रुपये का खर्च केवल रिपेयर और इम्प्रूवमैंट पर आयेगा। हमारे पास सीमित साधन हैं उसके बावजूद भी पी०डब्ल्यू०डी०, बी० एण्ड आर० जिस प्रकार से पिछले चार साल से काम कर रहा है वह सराहनीय है। चाहे सड़कों की बात हो या रेलवे ब्रिजिज की बात हो मुझे नहीं लगता कि हाउस कमेटी के गठन की कोई जरूरत है।

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]
ओवरलोड की वजह से या क्वालिटी की कमी की वजह से सड़कें टूट जाती हैं तो इस मामले में जिस भी साथी की कोई शिकायत है वह लिखकर माननीय मंत्री जी को भेज दें हम जाँच करवायेंगे और जाँच रिपोर्ट की एक कॉपी माननीय साथी को भी भेज दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, इसमें जनरली जो बात आई है उसमें पूवर क्वालिटी की बात है, मैम्बर्ज की तरफ से कहा गया है कि बनने के साथ ही साथ सड़कें टूट जाती हैं। इसके साथ ही रोडज को कम्पलीट करने की बात भी आई है। इसमें दूसरा प्वायंट यह है कि जिन ठेकेदारों ने काम कम्पलीट नहीं किया उन ठेकेदारों के खिलाफ क्या ऐक्शन लिया गया है और सरकार के जो ऑफिसर्ज या कर्मचारी दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ क्या ऐक्शन लिया गया है। हाउस के मैम्बर्ज की चिन्ता बड़ी वाजिब है क्योंकि पूरा प्रदेश सड़कों के ऊपर रोजाना निकलता है। मंत्री जी, आप अपने डिपार्टमैंट से रिपोर्ट मांगें या डी०सीज० से रिपोर्ट मांगें कि कहां पर क्या-क्या कमी है। 15 फरवरी से तारकोल बिछाने का काम शुरू हो जाएगा और अब दो या अढ़ाई महीने का समय इसमें रह गया है। मन्त्री जी, इसमें ऐसा है कि ऑनरेबल मैम्बर्ज की जो चिन्ता है वह दूर की जानी चाहिए। आप अपने सोर्स से यह रिपोर्ट मंगवाएं कि कहां-कहां सड़कों की कम्पलीशन बाकी है और कहां-कहां सड़कों की मेंटीमैंस बाकी है। नई सड़कों को बनाने की बजाये अगर आप रिपेयर करवाएं तो it would be more better. नई सड़कों का काम बन्द करके जो सड़कें बनी हुई हैं उनकी रिपेयर पर आप खर्च करें, यह काम आपके डिपार्टमैंट का है।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस में पहले ही यह बता चुका हूँ कि वर्ष 2009-10 के लिए हमने सरकार से 750 करोड़ रुपये सड़कों की रिपेयर करने के लिए मांगे हैं। स्पीकर सर, मैं मैम्बर्ज की मांग से सहमत हूँ कि नई सड़कें न बनाई जाएं हम इस समय कोई नई सड़क नहीं बना रहे हैं उनका काम बन्द करके एक ही काम कर रहे हैं कि जो सड़कें टूटी हुई हैं उनकी रिपेयर की जाए। कुछ सड़कें ऐसी हैं जो ज्यादा टूटी हुई हैं लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सब जगह सड़कें टूट रही हों। कुछ ऐसे स्थान हैं जहां ऐसा हो रहा है हम उनकी जांच करवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी, आप अपने ऐडमिनिस्ट्रेशन से पता करें और जहां रिपेयर की जरूरत है वह करवाएं। (विघ्न)

Lining of Ditch Drain Safidon

***1083. Shri Bachan Singh Arya :** Will the Irrigation Minister be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the Hon'ble Chief Minister had accepted the demand for lining the ditch drain of Safidon City in the public meeting held on 11th June, 2006; and

(b) whether it is also a fact that the amount of Rs. 2 crore 80 lacs has been sanctioned in meeting of flood control Board; if so, the time by which the said amount is likely to be released ?

Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) :

(a) Sir, the ditch drain in Safidon City has been already lined.

(b) No Sir. The funds are to be allocated by the Flood Control Board, the next meeting of which is to be held shortly.

श्री बचन सिंह आर्य : अध्यक्ष महोदय, यह जो सफीदों ड्रेन है इसको गन्दा नाला भी कहते हैं। मेरा यह सवाल इरिगेशन डिपार्टमैंट से नहीं बल्कि पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट से सम्बन्धित है। सफीदों शहर के अन्दर से यह नाला जाता है जिसे गन्दा नाला कहते हैं। यह नाला सारे शहर के बीच से जाता है। मेरा यह सवाल सिंचाई विभाग से सम्बन्धित नहीं है पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर जी को मैंने इसके बारे में लिख कर भेजा था और इसके लिए 2 करोड़ 80 लाख रुपये सीवरेज को पक्का करने के लिए रिलीज करने थे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी 11 जून, 2006 को इसे मन्जूर करके आये थे। मुझे विदित हुआ था कि 2 करोड़ 80 लाख रुपये फल्ड कण्ट्रोल बोर्ड से मन्जूर हो चुके थे लेकिन बाद में रेट्स बढ़ गए और 3 करोड़ 10 लाख रुपये के ऐस्टिमेट्स बनाकर पब्लिक हैल्थ ने भेजे थे। मैंने इसके बारे में पता किया था। क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह पैसा स्वीकृत हो चुका है और यदि स्वीकृत हो चुका है तो यह पैसा कब तक रिलीज हो जाएगा ?

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह प्रश्न इरिगेशन मिनिस्टर जी के पास फल्ड कण्ट्रोल प्रोग्राम के तहत भेजा गया था। फल्ड कण्ट्रोल प्रोग्राम के चेयरमैन माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और इनका विभाग इस काम को देखता है। इस पैसे के बारे में मन्त्रणा हो चुकी है और माननीय इरिगेशन मन्त्री जी से भी बात हुई है। फल्ड कण्ट्रोल बोर्ड की मीटिंग फरवरी में होगी और मुझे अनुमान है कि इसी मीटिंग में यह पैसा मन्जूर हो जाएगा। बहुत जल्दी ही इसका काम शुरू हो जाएगा।

श्री बचन सिंह आर्य : स्पीकर सर, मेरा निवेदन है कि पहले भी फल्ड कण्ट्रोल बोर्ड की मीटिंग में पैसा मन्जूर हो चुका था। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि यह पैसा कब तक रिलीज हो पाएगा ?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि बजट का प्रोविजन फल्ड कण्ट्रोल बोर्ड नहीं कर पाया था। फल्ड कण्ट्रोल बोर्ड की अगली मीटिंग होने वाली है उसमें हम इसको ले लेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या 1042

(इस समय माननीय सदस्य श्री राधे श्याम शर्मा अमर सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया।)

तारांकित प्रश्न संख्या 1110

(इस समय माननीय सदस्य श्री धर्मबीर गाबा सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया।)

तारांकित प्रश्न संख्या 1109

(इस समय माननीय सदस्य श्री नरेश यादव सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया।)

Bridge on Yamuna River

*1122. **Shri Udai Bhan :** Will the P.W.D. (B & R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a bridge on the Yamuna river near Hassanpur; if so, the details thereof ?

Irrigation Minister (Capt. Ajay Singh Yadav) : No, Sir.

श्री उदय भान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि 18 दिसम्बर, 2005 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने होडल के अन्दर इस पुल की घोषणा की थी और इसका सर्वे हुआ था। हसनपुर ऊंटासानी घाट और मालनघाट है। पहले ऊंटासानी घाट में सर्वे हुआ था तो इन्होंने नॉट फिज़िबल की रिपोर्ट दे दी थी। फिर इस बारे में कहा गया कि मालन घाट में उसको बनाया जाएगा। मंत्री जी ने भी कहा था कि इस बारे में विचार कर रहे हैं और इसको बनवाएंगे। इन्होंने यह भी बताया था कि इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से इस बारे में लिखा पढ़ी की हुई है लेकिन अब इन्होंने एकदम इस बारे में न में जवाब दे दिया है। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बारे में इनके द्वारा क्या कार्यवाही हुई है और अब इसकी लेटस्ट पोजीशन क्या है?

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, उदय भान जी का जो प्रश्न है इस बारे में मैं इनको बताना चाहूँगा कि हम वहां पर पनटून टैम्परेरी ब्रिज लगाते हैं जिसको हम 15 जून से 15 अक्तूबर तक हटा लेते हैं क्योंकि वहां पर पानी बहुत आ जाता है। अध्यक्ष महोदय, जहां की ये बात कर रहे हैं वहां से 24 किलोमीटर दूर अलीगढ़ नियर पलवल है और वहां पर एक ब्रिज है। दूसरे 63 किलोमीटर की दूरी पर यू०पी० के एरिया में मथुरा के पास भी ब्रिज है। इनकी यह बात सही है कि इनके वहां पर बड़ी भारी दिक्कत है और इस ब्रिज को बनाने में तकरीबन 32.65 करोड़ रुपये लगेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमारे सैक्रेटरी ने 31.1.2009 को यू०पी० गवर्नमैंट को चिट्ठी लिखी थी। इसमें दिक्कत यह है कि हरियाणा में अढ़ाई किलोमीटर की अप्रोच रोड नहीं बनी हुई है और दूसरी तरफ भी उनके एरिया में 2.40 किलोमीटर में भी अप्रोच रोड नहीं बनी हुई है। हम बाकायदा इसकी फिजिबल रिपोर्ट ले रहे हैं और हमने बाकायदा यू०पी० गवर्नमैंट को भी चिट्ठी लिखी हुई है कि वे बी०ओ०डी० बेसिज पर 50-50 शेयर के हिसाब से कर लें। अगर

उनकी तरफ से स्वीकृति मिल जाती है तो हम इस बारे में आगे की कार्यवाही करेंगे।

श्री उदय भान : अध्यक्ष महोदय, 18 दिसम्बर, 2005 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पुल को बनाने के बारे में घोषणा की थी और यह बहुत ही जरूरी पुल है। मथुरा वहां से 60 किलोमीटर दूर पड़ता है। अगर दूसरी साईड से जाएं तो सैंकड़ों किलोमीटर का चक्कर काट कर जाना पड़ता है। इसके अलावा पलवल साईड से 50-60 किलोमीटर का चक्कर पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, यह हसनपुर से सीधा अलीगढ़ का रोड है। अगर यह पुल बन जाता है तो इससे दोनों प्रदेशों को हर तरफ से बहुत लाभ होगा। अध्यक्ष महोदय, जब मेरा यह प्रश्न आया तो उसके बाद इन्होंने 31.1.2009 को यू०पी० गवर्नमैंट को खानापूर्ति करने के लिए चिट्ठी लिखी है। इन्होंने पिछले तीन सालों में कुछ नहीं किया आगे ये किस तरह से इस पर कुछ कर पाएंगे? इस पुल को बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। इस बारे में लापरवाही क्यों बरती गई है और इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेवार है?

श्री अध्यक्ष : यह लापरवाही की बात नहीं है, आप स्पैसिफिक प्रश्न पूछें।

श्री उदय भान : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह बहुत ही आवश्यक पुल है। इस बारे में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी और उन्होंने इसको बनाने के बारे में आश्वासन भी दिया था।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी बताया है कि हम वहां पर पनटूम टैम्परेरी ब्रिज लगाते हैं और 15 जून से 15 अक्तूबर के बीच में इसको उठा लेते हैं। इनकी जो मांग है वह बिल्कुल वाजिब है कि वहां पर ब्रिज होना चाहिए। इनकी इस जरूरत को देखते हुए स्टेट गवर्नमैंट ने यू०पी० गवर्नमैंट को बाकायदा चिट्ठी लिखी है कि इसकी बी०ओ०टी० लैवल पर फिजिब्लिटी स्टडी और डी०पी०आर० रिक्वायर्ड है। हमने यू०पी० गवर्नमैंट को कहा है कि वे इसके लिए अपनी कन्क्रैंस दें कि इसकी जो टोटल कॉस्ट है उसका 50 प्रतिशत शेयर वे देंगे और 50 प्रतिशत शेयर हम देंगे। जैसे ही इस बारे में उनकी स्वीकृति आ जाएगी तो इस बारे में हम कार्यवाही करेंगे।

Up-gradation of 132 KV Power Station with 25 MVA Transformer

***1101. Maj. Nirpender Singh Sangwan :** Will the Power Minister be pleased to state :—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade 132 KV Power Station with 25 MVA transformer at village Atela in Charkhi Dadri; and

(b) the time by which the 33 KV Power Station at village Chappar will start functioning ?

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) :

(a) Augmentation of 132 KV Sub Station Atela Kalan with 1x20/25 MVA, 132/33 KV transformer is an approved work at an estimated cost of Rs. 200 lac. I will tell the Hon'ble Member that as on today it stands commissioned. Although, the reply is that it will be commissioned by 20th February, 2009 but we have already commissioned it.

(b) 33 KV Sub Station Chappar with 10 MVA, 33/11 KV transformer stands commissioned since 3/2008 at no load. Speaker Sir, load now will be put by the end of this month as the earlier from where the connectivity had to come.

Maj. Nirpender Singh Sangwan : Speaker Sir, though the transformer has been upgraded but the problem remained the same. It needs to be uplifted and a control room to be made there for it. Until the control room is not made it remains idle standing there. The upgradation is made only 16 M.V.A. to 25 M.V.A. rather than from 16 M.V.A. plus 25 M.V.A.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैं पहले फैक्चुअल जानकारी अपने अधिकारियों से ले लूंगा और उसके बाद मैं माननीय सदस्य को भी सूचित कर दूंगा। हम कई जगह होट ट्रांसफोर्मर रखते हैं, जरूरी नहीं कि ये इस्तेमाल करते ही हों। यह इसलिए रखते हैं कि अगर कहीं पर ट्रांसफोर्मर जल जाए तो एकदम से उसको बदला जा सके क्योंकि उतनी जल्दी ट्रांसपोर्टेशन संभव नहीं होती। चूंकि हमने यह सब स्टेशन 25 एम०वी०ए० का करना था इसलिए वह हमने कर दिया। हम छप्पड़ सब स्टेशन को भी उससे इस महीने के आखिर तक जोड़ देंगे। इस तरह से इनके दोनों स्पैसिफिक क्वैश्चन्ज के स्पैसिफिक जवाब हैं। जहां तक उस सब स्टेशन को और बड़ा करने की और उस होट ट्रांसफोर्मर को भी ऑपरेशनल ट्रांसफोर्मर बनाने की बात है, मैं अपने अधिकारियों से पता करके इनको सूचित कर दूंगा।

तारांकित प्रश्न संख्या 1173

(इस समय माननीय सदस्य श्री सोमवीर सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया।)

Installation of Tubewells

***1040. Shri Nirmal Singh :** Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state the districtwise number of tubewells installed in Haryana State during the last three years togetherwith the number of tubewells which have failed during the said period ?

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, a statement is placed on the table of the House.

Statement

S.No.	Name of district	No. of tubewells drilled during 2005-2008	No. of tubewells drilled and failed within the period 2005-2008
1.	Ambala	276	8
2.	Bhiwani	57	0
3.	Faridabad	65	0
4.	Fatehabad	16	0
5.	Gurgaon	167	0
6.	Hisar	0	0
7.	Jhajjar	36	1
8.	Jind	63	0
9.	Kaithal	210	0
10.	Karnal	194	0
11.	Kurukshetra	117	0
12.	Mewat	200	15
13.	Mohindergarh	296	20
14.	Palwal	160	27
15.	Panchkula	51	0
16.	Panipat	175	1
17.	Rewari	140	23
18.	Rohtak	0	0
19.	Sirsa	76	0
20.	Sonipat	103	0
21.	Yamuna Nagar	244	5
	Total	**2646**	**100**

श्री निर्मल सिंह : स्पीकर साहब, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि अम्बाला में 8 ट्यूबवैल्ज अभी खराब हैं। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इनको दोबारा से चालू करने में कितना समय लग जाता है? जल्दी ही इनकी रिपेयर करवानी चाहिए क्योंकि पीने का पानी बहुत जरूरत की चीज है तो क्या मंत्री जी इस बारे में ध्यान देंगे?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, माननीय सदस्य की चिंता ठीक है इनके विधान सभा क्षेत्र नग्गल में तीन ट्यूबवैल्ज ऐसे हैं जो वाटर लेवल नीचे जाने की वजह से खराब हैं। एक तो बीटा में ट्यूबवैल है इसका पानी नीचे चला गया है जिसकी वजह से यह ड्राई हो गया है। एक मंछौड़ा में जिसे चन्द्रपुरी भी कहते हैं, ट्यूबवैल है, इसमें भी वाटर लेवल नीचे जाने के कारण पानी का डिस्चार्ज कम हो गया था। इसी तरह से एक मुनहेड़ी में ट्यूबवैल था यह भी ड्राई हो गया था। स्पीकर साहब, इस बैल्ट के अंदर वाटर लेवल जरूर नीचे जा रहा है। इनकी कांस्टीच्यूएंसी में पुराने करीब 14-15 ट्यूबवैल्ज हमारे नोटिस में ऐसे आए थे जो धीरे-धीरे सात-आठ-दस साल चलकर वाटर लेवल नीचे जाने की वजह से खराब हो गये थे। हमने इनके लिए आल्टरनेटिव प्रावधान करने का निर्णय लिया है। जब माननीय वित्त मंत्री जी अपना बजट पेश करेंगे तो उससे पहले माननीय सदस्य से इस बारे में हम राय ले लेंगे और इनके मुताबिक जहां पर पानी ठीक होगा वहां पर हम ट्यूबवैल मंजूर कर देंगे। वैसे हम अपनी तरफ से भी सर्वे करवा लेंगे और टैस्ट करवा लेंगे। जहां पर वाटर लेवल ठीक होगा वहां पर हम इनके क्षेत्र में ऐडीशनल ट्यूबवैल मंजूर कर देंगे।

श्री निर्मल सिंह : स्पीकर साहब, आठ ट्यूबवैल्ज का जिक्र किया गया है इनमें से कई ट्यूबवैल्ज ऐसे हैं जो लगते ही खराब हो गए हैं। वाटर लेवल नीचे जाने की वजह से या बहुत पुराने ट्यूबवैल्ज होने की वजह से तो खराब हैं ही लेकिन कई ट्यूबवैल्ज ऐसे भी हैं जो लगते ही खराब हो गए हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, इस प्रश्न आने के बाद मैंने इस बारे में जांच करवायी थी। हमें पता चला है कि वहां पर पानी का स्तर नीचे चला गया है। फिर भी माननीय सदस्य के नोटिस में यदि कोई और विषय है तो वे हमें लिखकर दे दें, हम उसकी जांच करवा लेंगे।

श्री फूल चन्द मुलाना : स्पीकर साहब, तीन साल में 2646 ट्यूबवैल्ज इस सरकार ने लगवाए हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि 2000 से लेकर 2004-05 तक इस सरकार के बनने से पहले तक कितने ट्यूबवैल्ज लगे थे?

श्री अध्यक्ष : मुलाना साहब, इस बारे में जानकारी लेकर क्या करेंगे?

श्री फूलचन्द मुलाना : ठीक है सर।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, Questions Hour is over.

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Payment of Outstanding Electricity Bills

*1088. **Dr. Sushil Indora** : Will the Power Minister be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that the electricity bills are issued by adding the outstanding amount of electricity bills already deposited; and

(b) whether any fee is deposited to get the said bills rectified ?

बिजली मन्त्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

(ए) नहीं, श्रीमान् ।

(बी) नहीं, श्रीमान् ।

Construction of PHC at Bir-Pipli

*1099. **Shri Ramesh Gupta** : Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Primary Health Centre on the land of Panchayat of Bir-Pipli at Pipli; if so, the time by which the work will be started thereon ?

स्वास्थ्य मंत्री (बहिन करतार देवी) : हाँ, श्रीमान् जी । ग्राम पंचायत द्वारा उपयुक्त भूमि उपलब्ध करवाए जाने पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा ।

Proper Drainage of Flood/Storm Water in Kalayat Town

*1126. **Smt. Geeta Bhukal** : Will the Public Health Engineering Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government for proper drainage of flood/storm water in Kalayat town ?

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : नहीं, श्रीमान् जी ।

Number of Government Higher Secondary Schools

*1131. **I.G. Sher Singh** : Will the Education Minister be pleased to state the number of Government Higher Secondary Schools functioning in Jind District togetherwith with number of schools which have Science and Commerce streams ?

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : श्रीमान् जी, जीन्द जिले में 85 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें से 12 विद्यालय विज्ञान संकाय के तथा 10 विद्यालय वाणिज्य संकाय के हैं।

अनुबन्ध "ए"

जीन्द जिले के विज्ञान संकाय के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के नाम :

विज्ञान संकाय के विद्यालय	वाणिज्य संकाय के विद्यालय
रा० मॉडल संस्कृति व०मा०वि०, बेलरखां	रा० मॉडल संस्कृति व०मा०वि०, बेलरखां
रा०व०मा०वि०, ईक्कस	रा०व०मा०वि०, ईक्कस
रा०क०व०मा०वि०, जीन्द	रा०क०व०मा०वि०, जीन्द
रा०व०मा०वि०, जुलाना	रा०व०मा०वि०, जुलाना
रा०व०मा०वि०, नरवाना	रा०व०मा०वि०, नरवाना
रा०व०मा०वि०, पिल्लू खेड़ा	रा०व०मा०वि०, पिल्लू खेड़ा
रा०व०मा०वि०, सफीदों	रा०व०मा०वि०, सफीदों
रा०क०व०मा०वि०, उचाना मण्डी	रा०क०व०मा०वि०, उचाना मण्डी
रा०क०व०मा०वि०, दनौदा	रा०क०व०मा०वि०, सफीदों
रा०व०मा०वि०, हाट	
रा०क०व०मा०वि०, नरवाना	

अनुबन्ध "बी"

शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

(i) छठी से बारहवीं तक सभी कक्षाओं में सैमेस्टर प्रणाली का लागू होना, जिसके परिणामस्वरूप पढ़ाई का बोझ कम हुआ है व सारा वर्ष पढ़ाई में निरन्तरता बन पाई है। अनुभव के आधार पर सैमेस्टर प्रणाली में सुधार करने के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा को समाप्त कर दिया गया है। अब प्रथम सैमेस्टर की परीक्षा में भी संक्षिप्त वर्णनात्मक प्रश्न शामिल किए गए हैं।

(ii) अध्यापकों के सभी रिक्त पदों पर अतिथि अध्यापक लगाए गए हैं।

(iii) राज्य में लगभग 10,000 विद्यालयों और महाविद्यालयों में एजूसैट की स्थापना की गई है।

(iv) कार्यपुस्तिकाओं की सहायता से अध्यापन की आधुनिक प्रणालियों को आरम्भ किया गया है।

(v) सरकारी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों की सहायता के लिए मौलिक स्तर पर लगभग 22 लाख विद्यार्थियों को पुस्तकें व कार्यपुस्तिकाएँ मुफ़्त प्रदान की गई हैं।

(vi) शैक्षणिक सत्र 2008-09 के दूसरे सैमेस्टर से परियोजना आधारित शिक्षा आरम्भ की गयी है।

(vii) आगामी शैक्षणिक सत्र से "सामान्य ज्ञान" विषय लागू किया गया है।

(viii) अध्यापकों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा आरम्भ की गई है। इस परीक्षा का सफल आयोजन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा किया गया था जिसमें 1.60 लाख उम्मीदवार बैठे और 32,000 उम्मीदवारों को उत्तीर्ण घोषित किया गया।

(ix) विद्यालयों की मूलभूत सुविधाओं के लिए पर्याप्त राशि प्रदान की गई।

(x) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मासिक वजीफे व एकमुश्त भत्ते की योजना आरम्भ की गई है। इससे लगभग 8.5 लाख विद्यार्थी लाभ उठा रहे हैं।

(xi) बाह्य एजेंसियों की सहायता से लगभग 1100 विद्यालयों में विद्यार्थियों को कम्प्यूटर शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है।

(xii) आगामी शैक्षणिक सत्र से 213 विद्यालयों में व्यापक कम्प्यूटर शिक्षा को चरणबद्ध तरीके से आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

(xiii) अध्यापकों की स्थानान्तरण नीति में सुधार किया गया है। अब अध्यापकों का न्यूनतम ठहराव का समय 3 वर्ष की अपेक्षा 5 वर्ष कर दिया गया है।

अनुबन्ध "सी"

राज्य सरकार द्वारा विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण

1. "एजूसैट" के माध्यम से ग्यारहवीं तथा बारहवीं कक्षा के विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों के विद्यार्थियों के लिए प्रतिदिन व्याख्यान प्रसारित किए जा रहे हैं।

2. "एजूसैट" के माध्यम से विज्ञान विषय के ग्यारहवीं तथा बारहवीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को अखिल भारतीय इंजिनियरिंग प्रवेश परीक्षा के लिए प्रतिदिन गहन कोचिंग प्रदान की जाती है। यह कोचिंग कार्यक्रम "उत्कर्ष सोसाईटी" द्वारा एक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्था के सहयोग से विकसित किया गया है तथा बड़े उत्साह से विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण किया जा रहा है।

3. विशेष रूप से सुविधाओं की चरणबद्ध स्तरोन्नति के लिए चयनित 213 विद्यालयों को 11.86 करोड़ रुपये विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए सरकार द्वारा वितरित किए गए हैं।

[श्री मांगे राम गुप्ता]

4. प्रयोगशालाओं के उपकरणों की खरीद के लिए 40,000 रुपये प्रति विज्ञान संकाय वरिष्ठ माध्यमिक तथा 17,397 रुपये प्रति गैर विज्ञान संकाय वरिष्ठ माध्यमिक व उच्च विद्यालय की दर से कुल 6.15 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

Adulteration of Milk

*1137. **Dr. Sita Ram :** Will the Health Minister be pleased to state :—

(a) the district wise and year wise number of cases of adulteration in milk registered in the State since April, 2006 till date, togetherwith the fate of the registered cases; and

(b) the steps taken by the Health Department to check the adulteration in milk togetherwith the total number of samples taken in this regard ?

स्वास्थ्य मंत्री (बहिन करतार देवी) : श्रीमान् जी, सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है :

(क) स्वास्थ्य विभाग द्वारा अप्रैल, 2006 से दिसम्बर, 2008 तक दूध के कुल 683 नमूने लिए गए, 224 नमूने अपमिश्रित पाए गए तथा इन केसों बारे मुकदमा दायर किया हुआ है। यह सभी केस न्यायालय के विचाराधीन है।

जिलावार तथा वर्षवार ब्यौरा निम्न प्रकार से है :

क्रम संख्या	जिले का नाम	वर्षवार लिए गए सैम्पलों की संख्या			अपमिश्रित पाए गए नमूनों की संख्या		
		2006	2007	2008	2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अम्बाला	12	14	6	--	02	02
2	भिवानी	06	23	38	02	05	12
3	फतेहाबाद	02	02	02	02	02	02
4	फरीदाबाद	17	02	07	04	01	01
5	गुड़गावां	26	30	18	09	12	08
6	हिसार	23	10	38	02	01	04
7	झज्जर	02	02	02	02	02	02
8	जीन्द	02	04	07	--	03	03
9	करनाल	02	04	07	02	04	07

1	2	3	4	5	6	7	8
10	कैथल	44	23	32	05	06	06
11	कुरुक्षेत्र	5	13	12	05	05	0
12	मेवात	--	--	02	--	--	01
13	नारनौल	01	01	02	01	01	02
14	पानीपत	19	25	15	03	03	02
15	पंचकूला	15	13	18	02	09	03
16	रिवाड़ी	02	07	01	02	07	01
17	रोहतक	01	11	02	01	11	02
18	सोनीपत	02	15	02	02	15	02
19	सिरसा	08	15	25	03	04	07
20	यमुनानगर	13	14	17	05	03	09
	कुल		683			224	

(ख) विभाग ने अधिक से अधिक सैम्पलिंग तथा चैकिंग के लिए कदम उठाए हैं। प्रत्येक जिले में आठ उपसिविल सर्जन के पद स्वीकृत किए गए हैं। सभी उपसिविल सर्जन को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के तहत लोकल हैल्थ अथारिटी अधिसूचित किया गया है। इससे पहले केवल एक प्रोग्राम अधिकारी यानि जिला स्वास्थ्य अधिकारी इस कार्य को करता था।

Free Technical Education for Orphan Children

*1192. **Smt Sumita Singh :** Will the Technical Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide free Technical Education to the 10th class passed orphan children; if so, the details thereof ?

शहरी विकास मंत्री (श्री ए०सी० चौधरी) : श्रीमान् जी, नहीं।

Unauthorised Colonies in M.C. Faridabad

*1150. **Shri Mahendra Partap Singh :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state :—

(a) the number of unauthorized colonies in the area of Faridabad Municipal Corporation; and

[Shri Mahendra Partap Singh]

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to regularize the above said colonies; if so, the time by which these colonies will be regularized ?

शहरी विकास मंत्री (श्री ए०सी० चौधरी) :

(क) नगर निगम फरीदाबाद क्षेत्र में 51 अनाधिकृत कालोनियाँ चिन्हित की गयी हैं ।

(ख) वर्ष 2006 में 51 अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था । परन्तु माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा के CWP No. 1006 of 2007 व 17002/2006 में पारित निर्देशानुसार, अब से कोई भी कालोनी नियमित नहीं की जाएगी यदि वह सक्षम प्राधिकारी की वांछित स्वीकृति एवम् माननीय उच्च न्यायालय का अनुमोदन प्राप्त किये बिना बनाई गई हो । मामला अभी तक न्यायालय के विचाराधीन है ।

Opening an I.T.I. at Madlaudha

***1159. Smt. Raj Rani Poonam :** Will the Industrial Training & Vocational Education Minister be pleased to state :—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open an I.T.I. at Madlaudha; and

(b) if so, the time by which it is likely to be opened ?

शहरी विकास मंत्री (श्री ए०सी० चौधरी) : हाँ, श्रीमान् जी ।

(क) मडलौडा में आई०टी०आई० खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) इस समय आई०टी०आई० खोलने की सीमा दी जानी सम्भव नहीं है ।

Construction of Roads

***1185. Shri Dinesh Kaushik :** Will the Agriculture Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following roads :—

(i) from Sanch-Sirsal road to purchase centre via Dera Baldev Singh Habri;

(ii) from Habri Canal Rest House to Dera Sisha Singh Nishoria; and

(iii) from village Ahun to Sangroli and Sangroli to village Pharal ?

कृषि मंत्री (सरदार एच०एस० चट्ठा) : नहीं, श्रीमान् जी ।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

142. Shri Naresh Yadav : : Will the Agriculture Minister be pleased to state :—

(a) the number of roads constructed by the Haryana State Agricultural Marketing Board in Haryana during the period from 2005 to 2008.

(b) the number of roads for which sanction has been accorded which were under construction togetherwith the criteria for construction of roads; and

(c) the number of roads repaired by the marketing board during the year 2005 to 2008 togetherwith the details of the expenditure incurred thereon ?

कृषि मंत्री (सरदार एच०एस० चट्ठा) : श्रीमान् जी ।

(क) हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वर्ष 2005 से 2008 के दौरान 551 सड़कों का निर्माण किया गया है, तथा

(ख) वर्ष 2005 से 2008 तक 702 नई सड़कें स्वीकृत की गई हैं । सड़कों के निर्माण बारे मापदण्ड अनुलग्नक "क" पर उपलब्ध है ।

(ग) वर्ष 2005 से 2008 के दौरान 1097 सड़कों की मरम्मत की गई है और इन सड़कों पर 149.10 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई हैं । जिलावार संक्षिप्त विवरण अनुलग्नक "ख" पर उपलब्ध है ।

अनुलग्नक "क"

सड़कों की नीति निम्नलिखित है :—

1. बोर्ड क्षेत्र की आवश्यकतानुसार ग्रामीण पहुँच सड़कों का निर्माण कृषि मन्त्री/मुख्यमंत्री महोदय की स्वीकृति उपरान्त करेगा ।

2. बोर्ड माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा घोषित सड़कों का निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ करेगा तथा इसकी सूचना सरकार को भेज देगा ।

3. बोर्ड उन्हीं सड़कों का निर्माण करेगा जहां कम से कम 5 करम चौड़ा रास्ता उपलब्ध हो । जहां रास्ता 5 करम से कम हो और सड़क बनानी जरूरी हो, वहां भूमि साथ लगती भूमि मालिकों से मुफ्त प्राप्त की जायेगी । यद्यपि विशेष परिस्थितियों में सरकार से इस मामले में ढील प्राप्त की जा सकती है ।

[सरदार एच०एस० चट्ठा]

4. सड़कों के निर्माण पर मिट्टी के कार्य बोर्ड द्वारा अपने फण्ड से करवाया जायेगा।

5. बोर्ड द्वारा स्कूल, मन्दिर, मस्जिद तथा धर्मशाला को जाने वाली सड़कों का निर्माण नहीं करवाया जायेगा।

6. बोर्ड द्वारा श्मशान घाट की ओर जाने वाली सड़कों का निर्माण नहीं करवाया जायेगा।

7. गांव की आन्तरिक सड़कें, फिरनी सड़कों और रिंग बांधों का निर्माण विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा करवाया जायेगा।

8. तालाब के साथ लगती पहुँच/ग्रामीण सड़कों के लिए रिटेनिंग वाल विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा बनवाई जायेगी।

9. अन्तर्राज्जीय सड़कों का निर्माण लोक निर्माण विभाग (भवन व सड़कें) द्वारा करवाया जायेगा।

10. बोर्ड/मार्किट कमेटियों द्वारा निर्मित सड़कों की समयबद्ध मुरम्मत का कार्य बोर्ड द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार किया जायेगा।

अनुलग्नक "ख"

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वर्ष 2005 से 2008 के दौरान पूर्ण की गई सड़कों की विशेष मुरम्मत।

क्रम संख्या	जिला	सड़कों की संख्या	लम्बाई किलोमीटरों में	खर्चा लाखों में
1	2	3	4	5
1	अम्बाला	47	107.54	335.36
2	भिवानी	61	146.73	829.86
3	फरीदाबाद तथा पलवल	58	89.80	1047.07
4	फतेहाबाद	127	287.45	1468.65
5	गुड़गांव	18	43.94	430.64
6	हिसार	47	135.02	777.35
7	झज्जर	19	47.14	464.68
8	जीन्द	66	177.10	1169.28
9	कैथल	107	195.77	975.21

1	2	3	4	5
10	करनाल	85	193.96	1456.25
11	कुरुक्षेत्र	137	222.19	1593.87
12	महेन्द्रगढ़	12	26.17	153.96
13	मेवात	11	23.39	126.10
14	पानीपत	28	62.68	573.70
15	पंचकूला	16	20.01	69.82
16	रिवाड़ी	27	52.63	340.79
17	रोहतक	32	78.71	736.60
18	सिरसा	115	253.75	1397.47
19	सोनीपत	50	127.03	607.64
20	यमुनानगर	34	55.70	355.68
	कुल	1097	2346.71	14909.98

Buses Remained off the Roads

144. Shri Karan Singh Dalal : Will the Transport Minister be pleased to state the depotwise and monthwise number of Haryana Roadways Buses alongwith the number of days for which they remained off the roads during the year 2008-09 till date due to non-availability of staff or non-availability of tyre-tubes separately ?

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : निम्नलिखित अनुसूचियाँ विधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत है :--

(क) वर्ष 2008-09 (अब तक) में हरियाणा रोडवेज बसों की डिपोवार तथा मासवार संख्या ।

(ख) अप्रैल, 08 से जनवरी, 09 (अब तक) अमले की कमी के कारण मार्ग पर नहीं भेजी गई बसों का ब्यौरा ।

(ग) अप्रैल, 08 से जनवरी, 09 (अब तक) टायर ट्यूब की कमी के कारण मार्ग पर नहीं भेजी गई बसों का ब्यौरा ।

(घ) हरियाणा राज्य परिवहन के आगारों में मार्ग पर नहीं भेजे गये औसत वाहनों का ब्यौरा ।

[श्री मांगे राम गुप्ता]

अनुसूची - "क"

वर्ष 2008-09 (अब तक) में हरियाणा रोडवेज बसों की डिपोवार तथा मासवार संख्या

क्र.सं.	आगार का नाम	अप्रैल,08	मई, 08	जून, 08	जुलाई, 08	अगस्त,08	सितम्बर, 08	अक्तु, 08	नवम्बर, 08	दिसम्बर, 08
1	चण्डीगढ़	232	230	219	219	223	229	229	229	229
2	अम्बाला	187	187.	187	179	179	179	179	179	181
3	यमुनानगर	152	146	146	143	146	146	146	146	146
4	करनाल	160	161	162	162	162	162	162	162	162
5	कुरुक्षेत्र	154	154	156	156	155	155	155	155	155
6	सिरसा	156	155	154	153	154	155	155	155	155
7	पानीपत	113	107	109	109	110	110	112	112	112
8	फतेहाबाद	149	149	151	144	142	142	142	142	143
9	रेवाड़ी	117	117	115	116	118	114	118	122	122
10	सोनीपत	195	199	199	183	173	177	180	181	186
11	फरीदाबाद	202	203	203	204	200	210	214	215	219
12	दिल्ली	105	104	102	93	93	93	93	92	93
13	कैथल	132	130	130	130	131	131	131	131	131
14	रोहतक	147	150	150	146	146	152	156	160	162
15	जीन्द	150	150	146	148	147	148	148	148	148
16	गुड़गांव	169	169	169	171	179	179	159	160	160
17	भिवानी	161	161	161	161	161	160	178	160	160
18	हिसार	181	181	177	176	176	177	177	177	179
19	झज्जर	115	115	112	117	117	120	119	120	120
20	नारनौल	103	103	103	102	104	104	103	103	104
	कुल जोड़	3080	3071	3051	3012	3016	3043	3056	3049	3067

अनुसूची - "ख"

अप्रैल, 08 से जनवरी, 09 (अब तक) अमले की कमी के कारण मार्ग पर नहीं भेजी गई बसों का ब्यौरा।

क्र.सं.	आगार का नाम	अप्रैल,08	मई, 08	जून, 08	जुलाई, 08	अगस्त,08	सित., 08	अक्तू, 08	नव., 08	दिस., 08	जन., 09
1	चण्डीगढ़	11	11	11	18	18	18	18	18	18	18
	दिनों की संख्या	30	31	30	31	31	30	31	30	31	27
2	अम्बाला	8	8	8	6	6	5	3	शून्य	शून्य	शून्य
	दिनों की संख्या	30	31	30	31	31	30	31	-	-	
3	यमुनानगर	4	4	4	2	6	5	3	शून्य	शून्य	शून्य
	दिनों की संख्या	30	31	30	31,21	31	30	31			
4	करनाल	11	7	9,1	2	6	5	3	शून्य	शून्य	शून्य
	दिनों की संख्या	30	30	30,27	31,21	31	30	31			
5	कुरुक्षेत्र	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दिनों की संख्या										
6	सिरसा	3	4	4	4	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दिनों की संख्या										
7	पानीपत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दिनों की संख्या										
8	फतेहाबाद	9	7	7	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दिनों की संख्या	30	31	30							
9	रेवाड़ी	11	11	11	9	9	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दिनों की संख्या	30	30	30	31	31					
10	सोनीपत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दिनों की संख्या										

[श्री मांगे राम गुप्ता]

क्र.सं.	आगार का नाम	अप्रैल,08	मई, 08	जून, 08	जुलाई, 08	अगस्त,08	सित., 08	अक्तू, 08	नव., 08	दिस., 08	जन., 09
11	फरीदाबाद दिनों की संख्या	12	12	11	10	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12	दिल्ली दिनों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13	कैथल दिनों की संख्या	4	4	5	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
14	रोहतक दिनों की संख्या	3,1 30,22	4,2 31,10	6,1 30,26	1 20	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15	जीन्द दिनों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16	गुड़गांव दिनों की संख्या	10 30	10 31	10 30	10 31	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17	भिवानी दिनों की संख्या	6 30,15,20,12 12,23,10	5 31	6 31	3,1 31,27	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18	हिसार दिनों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19	झज्जर दिनों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
20	नारनौल दिनों की संख्या	6	6	6	4	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

अनुसूची - "ग"

अप्रैल, 08 से जनवरी, 09 (अब तक) टायर ट्यूब की कमी के कारण मार्ग पर नहीं भेजी गई बसों का ब्यौरा।

क्र.सं.	आगार का नाम	अप्रैल,08	मई, 08	जून, 08	जुलाई, 08	अगस्त,08	सित., 08	अक्तू, 08	नव., 08	दिस., 08	जन., 09
1	चण्डीगढ़ दिनों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	अम्बाला दिनों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	यमुनानगर दिनों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	करनाल दिनों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	कुरुक्षेत्र दिनों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6	सिरसा दिनों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7	पानीपत दिनों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8	फतेहाबाद दिनों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9	रेवाड़ी दिनों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10	सोनीपत दिनों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

[श्री मांगे राम गुप्ता]

क्र.सं.	आगार का नाम	अप्रैल,08	मई, 08	जून, 08	जुलाई, 08	अगस्त,08	सित., 08	अक्तू, 08	नव., 08	दिस., 08	जन., 09
11	फरीदाबाद	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दिनों की संख्या										
12	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दिनों की संख्या										
13	कैथल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दिनों की संख्या										
14	रोहतक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दिनों की संख्या										
15	जीन्द	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दिनों की संख्या										
16	गुड़गांव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दिनों की संख्या										
17	भिवानी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दिनों की संख्या										
18	हिसार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दिनों की संख्या										
19	झज्जर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2	4	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दिनों की संख्या					6,6	25,1,23,27				
20	नारनौल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3	3	3	4	शून्य	शून्य
	दिनों की संख्या										

अनुसूची "घ"

हरियाणा राज्य परिवहन के आगारों में मार्ग पर नहीं भेजे गये औसत वाहनों का ब्यौरा।

क्र०सं०	आगार का नाम	मार्ग पर नहीं भेजे गये औसत वाहनों का ब्यौरा	महीनों की संख्या
1.	चण्डीगढ़	16	12
2.	अम्बाला	6	7
3.	यमुनानगर	4	7
4.	कैथल	6	7
5.	सिरसा	4	4
6.	फतेहाबाद	8	3
7.	रेवाड़ी	10	5
8.	फरीदाबाद	11	4
9.	रोहतक	4	4
10.	गुड़गांव	10	4
11.	भिवानी	5	4
12.	नारनौल	6	4
	कुल जोड़	90	65
	औसत	8	6

Adulteration in Food Articles

137. Dr. Sita Ram : Will the Health Minister be pleased to state the district-wise details of samples taken by the Health Department for adulteration in the food articles in the State since April, 2006 together with fate thereof ?

स्वास्थ्य मंत्री (बहिन करतार देवी) : श्रीमान जी, स्वास्थ्य विभाग द्वारा अप्रैल, 2006 से दिसम्बर, 2008 तक कुल 7503 खाद्य नमूने लिए गए, 971 नमूने अपमिश्रित पाए गए तथा इन केसों जारे मुकदमा दायर किया हुआ है। ये सभी केस न्यायालय के विचाराधीन हैं। जिलावार ब्यौरा निम्न प्रकार से है :--

[बहिन करतार देवी]

क्र०सं०	जिले का नाम	अप्रैल 2006 से दिसम्बर 2008 तक लिये गए सैम्पलों की संख्या	अपमिश्रित पाए गए नमूनों की संख्या
1.	अम्बाला	477	27
2.	भिवानी	393	50
3.	फतेहाबाद	206	35
4.	फरीदाबाद	467	77
5.	गुड़गांव	582	114
6.	हिसार	563	66
7.	जीन्द	333	31
8.	झज्जर	146	27
9.	कुरुक्षेत्र	258	46
10.	कैथल	449	62
11.	करनाल	617	40
12.	मेवात	8	4
13.	नारनौल	100	17
14.	पंचकूला	397	76
15.	पानीपत	440	62
16.	पलवल	25	2
17.	रिवाड़ी	252	38
18.	रोहतक	420	21
19.	सोनीपत	288	61
20.	सिरसा	438	38
21.	यमुनानगर	644	77
	कुल	7503	971

---

145. Shri Karan Singh Dalal : Will the Education Minister be pleased to state the districtwise number of Government and aided private degree and post graduate colleges in Rural and Urban area separately in the state alongwith the number in which Science faculty Medical or both is being run during the academic session 2008-09 ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : श्रीमान् जी, सूचना निम्न प्रकार से है :—

सूचना

जिला	राजकीय महाविद्यालय कुल संख्या			सहायता प्राप्त महाविद्यालय कुल संख्या			राजकीय महाविद्यालय में चलाये जा रहे कोर्स			सहायता प्राप्त महाविद्यालय में चलाये जा रहे कोर्स		
	शहरी	ग्रामीण	कुल	शहरी	ग्रामीण	कुल	स्नातकोत्तर	मैडीकल कोर्स	नॉन-मैडीकल कोर्स	स्नातकोत्तर	मैडीकल कोर्स	नॉन-मैडीकल कोर्स
अम्बाला	2	1	3	6	3	9	1	1	1	6	3	4
पंचकूला	3	1	4	-	-	-	2	3	3	-	-	-
भिवानी	4	3	7	4	2	6	2	2	2	2	3	3
फरीदाबाद	3	1	4	5	-	5	1	1	2	3	2	3
गुड़गांव	3	2	5	1	-	1	2	2	2	-	-	-
मेवात	0	2	2	1	-	1	-	-	-	-	1	1
हिसार	3	3	6	4	-	4	2	2	2	3	3	3
फतेहाबाद	2	2	4	1	-	1	1	-	1	1	-	-
कैथल	1	-	1	5	2	7	-	-	1	3	1	1
यमुनानगर	0	1	1	7	1	8	-	-	-	7	5	5
जीन्द	4	1	5	3	-	3	4	3	3	1	-	-
करनाल	2	2	4	4	-	4	3	1	1	4	2	2
पानीपत	1	1	2	5	-	5	-	-	-	3	3	3
महेन्द्रगढ़	5	3	8	-	-	-	3	3	3	-	-	-
रिवाड़ी	1	3	4	3	1	4	3	-	1	1	2	2
रोहतक	3	2	5	7	-	7	1	1	1	5	2	2
झज्जर	2	4	6	2	-	2	1	2	2	5	4	4
सोनीपत	1	1	2	6	-	6	-	1	1	5	4	4
सिरसा	2	-	2	2	1	3	1	1	1	2	-	-
कुरुक्षेत्र	-	-	-	6	-	6	-	-	-	4	2	4

Cases of Murder, Rape etc.

138. Dr. Sita Ram : Will the Chief Minister be pleased to state the district-wise and monthwise total number of cases of murder, rape, dacoity and ransom registered since April 1st, 2008 till date together with the Status thereof ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है ।

सूचना

हत्या

जिला	अप्रैल,08	मई, 08	जून, 08	जुलाई, 08	अगस्त,08	सित., 08	अक्तु, 08	नव., 08	दिस., 08	जन., 09
पंचकूला	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1
अम्बाला	4	0	1	2	3	5	4	5	4	1
यमुनानगर	4	3	3	5	3	3	4	4	3	1
कुरुक्षेत्र	4	0	2	0	2	0	2	4	1	2
कैथल	3	4	3	1	3	1	4	2	0	2
हिसार	5	4	16	7	3	4	1	4	0	1
सिरसा	2	3	7	2	4	5	4	5	6	1
भिवानी	2	7	4	7	4	9	4	4	5	3
जीन्द	3	4	3	2	3	5	4	1	7	3
फतेहाबाद	2	2	0	1	5	1	2	4	0	1
गुड़गांव	1	10	3	6	12	2	10	7	6	3
फरीदाबाद	4	4	4	12	6	5	8	3	1	3
पलवल	3	4	3	2	5	3	3	5	0	1
नारनौल	3	2	1	3	5	2	2	2	3	0
रेवाड़ी	2	1	4	2	1	2	4	2	3	1
मेवात	0	1	3	1	1	3	2	2	2	3
रोहतक	4	5	4	3	4	8	5	5	11	5
सोनीपत	4	10	10	9	2	4	12	7	10	2
करनाल	4	2	1	8	4	6	3	3	4	1
पानीपत	4	4	5	2	5	6	3	5	5	3
झज्जर	6	5	7	8	9	9	4	5	2	5
रेलवे	1	3	4	1	3	2	2	3	0	1
कुल	67	80	89	86	88	86	88	83	74	44

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

बलात्कार

जिला	अप्रैल,08	मई, 08	जून, 08	जुलाई, 08	अगस्त,08	सित., 08	अक्तू. 08	नव., 08	दिस., 08	जन., 09
पंचकूला	1	0	1	0	0	1	2	3	0	1
अम्बाला	0	4	6	3	4	4	4	3	2	0
यमुनानगर	1	1	6	4	1	3	6	3	0	1
कुरुक्षेत्र	3	5	5	6	4	4	6	3	0	2
कैथल	0	1	2	0	2	2	3	2	0	0
हिसार	1	4	2	3	3	3	1	0	1	1
सिरसा	1	2	2	4	6	3	2	3	2	1
भिवानी	2	3	5	6	4	4	1	1	1	6
जीन्द	2	3	4	6	5	2	5	2	0	3
फतेहाबाद	2	0	1	1	2	0	2	0	0	1
गुड़गांव	6	0	4	3	7	6	3	1	2	2
फरीदाबाद	7	1	6	4	5	1	5	6	2	2
पलवल	1	2	3	1	6	4	2	3	0	1
नारनौल	2	2	1	2	3	0	3	3	0	1
रेवाड़ी	0	1	3	3	2	4	6	0	3	0
मेवात	8	2	2	1	2	5	4	1	2	1
रोहतक	3	2	3	7	1	3	3	3	2	3
सोनीपत	4	4	6	1	1	3	2	3	5	0
करनाल	0	3	8	9	6	3	4	2	5	1
पानीपत	1	2	3	2	1	4	6	0	5	3
झज्जर	1	3	5	1	2	1	2	3	3	0
रेलवे	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
कुल	46	46	78	67	67	60	73	45	35	30

डकैती

जिला	अप्रैल,08	मई, 08	जून, 08	जुलाई, 08	अगस्त,08	सित., 08	अक्तू, 08	नव., 08	दिस., 08	जन., 09
पंचकूला	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1
अम्बाला	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
यमुनानगर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
कुरुक्षेत्र	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
कैथल	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0
हिसार	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
सिरसा	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
भिवानी	4	1	2	1	0	0	0	1	2	0
जीन्द	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
फतेहाबाद	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
गुड़गांव	3	3	4	2	2	5	1	1	2	1
फरीदाबाद	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
पलवल	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0
नारनौल	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
रेवाड़ी	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1
मेवात	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
रोहतक	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0
सोनीपत	0	0	1	1	0	0	2	3	0	2
करनाल	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
पानीपत	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
झज्जर	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
रेलवे	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
कुल	13	7	9	9	11	8	9	10	6	9

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

फिरौती

जिला	अप्रैल,08	मई, 08	जून, 08	जुलाई, 08	अगस्त,08	सित., 08	अक्टू, 08	नव., 08	दिस., 08	जन., 09
पंचकूला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अम्बाला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
यमुनानगर	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
कुरुक्षेत्र	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कैथल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
हिसार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सिरसा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
भिवानी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जीन्द	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
फतेहाबाद	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
गुड़गांव	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
फरीदाबाद	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
पलवल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
नारनौल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
रेवाड़ी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मेवात	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
रोहतक	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
सोनीपत	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
करनाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पानीपत	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
झज्जर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
रेलवे	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	0	0	2	3	0	1	1	1	2	0

हत्या के केसों की वर्तमान स्थिति (अम्बाला मण्डल)

माह	पंचकूला	अम्बाला	यमुनानगर	कुरुक्षेत्र	कैथल
अप्रैल, 2008	अनुसंधाना-धीन=1 न्यायालय में लम्बित=1	अदमपता=1 न्यायालय में लम्बित=2 अनुसंधाना-धीन=1	न्यायालय में लम्बित=2 अनुसंधाना-धीन=2	न्यायालय में लम्बित=4	न्यायालय में लम्बित=2 अदमपता=1
मई, 2008	न्यायालय में लम्बित=1 अनुसंधाना-धीन=1	शून्य	न्यायालय में लम्बित=3	शून्य	न्यायालय में लम्बित=4
जून, 2008	न्यायालय में लम्बित=1	न्यायालय में लम्बित=1	न्यायालय में लम्बित=2 अनुसंधाना-धीन=1	रद्द=1 चालान=1	न्यायालय में लम्बित=2 रद्द=1
जुलाई, 2008	न्यायालय में लम्बित=2	न्यायालय में लम्बित=1 अनुसंधाना-धीन=1	न्यायालय में लम्बित=3 अनुसंधाना-धीन=2	शून्य	अनुसंधाना-धीन=1
अगस्त, 2008	न्यायालय में लम्बित=1	न्यायालय में लम्बित=1 अनुसंधाना-धीन=1 रद्द=1	न्यायालय में लम्बित=1 अनुसंधाना-धीन=1	चालान=1 अनुसंधाना-धीन=1	न्यायालय में लम्बित=3
सितम्बर, 2008	न्यायालय में लम्बित=1	न्यायालय में लम्बित=2 अनुसंधाना-धीन=3	अनुसंधाना-धीन=3	शून्य	न्यायालय में लम्बित=1
अक्तूबर, 2008	अनुसंधाना-धीन=1	रद्द=1 न्यायालय में लम्बित=1 अनुसंधाना-धीन=2	न्यायालय में लम्बित=2 अनुसंधाना-धीन=2	अनुसंधाना-धीन=2	न्यायालय में लम्बित=2 अनुसंधाना-धीन=2
नवम्बर, 2008	न्यायालय में लम्बित=1	न्यायालय में लम्बित=1 अनुसंधाना-धीन=4	न्यायालय में लम्बित=2 अनुसंधाना-धीन=2	अनुसंधाना-धीन=4	न्यायालय में लम्बित=1 अनुसंधाना-धीन=1

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

माह	पंचकूला	अम्बाला	यमुनानगर	कुरुक्षेत्र	कैथल
दिसम्बर, 2008	अनुसंधाना-धीन=1	अनुसंधाना-धीन=4	अनुसंधाना-धीन=3	अनुसंधाना-धीन=1	शून्य
जनवरी, 2009	अनुसंधाना-धीन=1	अनुसंधाना-धीन=1	अनुसंधाना-धीन=1	अनुसंधाना-धीन=2	अनुसंधाना-धीन=2
बलात्कार					
अप्रैल, 2008	न्यायालय में लम्बित=1	शून्य	न्यायालय में लम्बित=1 बरी=1	न्यायालय में लम्बित=2	शून्य
मई, 2008	शून्य	न्यायालय में लम्बित=3 बरी=1	न्यायालय में लम्बित=1	न्यायालय में लम्बित=3 अनुसंधाना-धीन=2	न्यायालय में लम्बित=1
जून, 2008	न्यायालय में लम्बित=1	रद्द=1 न्यायालय में लम्बित=5	न्यायालय में लम्बित=6	रद्द=1 बरी=1 न्यायालय में लम्बित=3	न्यायालय में लम्बित=2
जुलाई, 2008	शून्य	न्यायालय में लम्बित=3	रद्द=1 न्यायालय में लम्बित=3	न्यायालय में लम्बित=4 बरी=2	शून्य
अगस्त, 2008	शून्य	रद्द=1 न्यायालय में लम्बित=3	न्यायालय में लम्बित=1	न्यायालय में लम्बित=2 अनुसंधाना-धीन=1 बरी=1	न्यायालय में लम्बित=1 अनुसंधाना-धीन=1
सितम्बर, 2008	अनुसंधाना-धीन=1	रद्द=1 न्यायालय में लम्बित=3	न्यायालय में लम्बित=2 अनुसंधाना-धीन=1	रद्द=2 न्यायालय में लम्बित=2	न्यायालय में लम्बित=2
अक्तूबर, 2008	रद्द=1 न्यायालय में लम्बित=1	अनुसंधाना-धीन=2 रद्द=1 न्यायालय में लम्बित=1	न्यायालय में लम्बित=5 अनुसंधाना-धीन=1	न्यायालय में लम्बित=3 अनुसंधाना-धीन=3	न्यायालय में लम्बित=3
नवम्बर, 2008	अनुसंधाना-धीन=3	अनुसंधाना-धीन=2	न्यायालय में लम्बित=3	न्यायालय में लम्बित=1	न्यायालय में लम्बित=2

माह	पंचकूला	अम्बाला	यमुनानगर	कुरुक्षेत्र	कैथल
		न्यायालय में लम्बित=1		अनुसंधाना-धीन=2	
दिसम्बर, 2008	शून्य	रद्द=1 अनुसंधाना-धीन=1	शून्य	शून्य	शून्य
जनवरी, 2009	अनुसंधाना-धीन=1	शून्य	अनुसंधाना-धीन=1	अनुसंधाना-धीन=2	शून्य
डकैती					
अप्रैल, 2008	शून्य	शून्य	शून्य	न्यायालय में लम्बित=1	शून्य
मई, 2008	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	न्यायालय में लम्बित=1
जून, 2008	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जुलाई, 2008	शून्य	शून्य	शून्य	अनुसंधाना-धीन=1	शून्य
अगस्त, 2008	न्यायालय में लम्बित=2 अनुसंधाना-धीन=1	अनुसंधाना-धीन=1	शून्य	शून्य	शून्य
सितम्बर, 2008	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अक्तूबर, 2008	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	न्यायालय में लम्बित=2
नवम्बर, 2008	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	न्यायालय में लम्बित=1
दिसम्बर, 2008	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जनवरी, 2009	अनुसंधाना-धीन=1	शून्य	अनुसंधाना-धीन=1	शून्य	शून्य
फिरौती					
जुलाई, 2008	शून्य	शून्य	न्यायालय में लम्बित=1	शून्य	शून्य

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

हत्या के केसों की वर्तमान स्थिति (हिसार मण्डल)

माह	हिसार	सिरसा	भिवानी	जींद	फतेहाबाद
अप्रैल, 2008	न्यायालय में लम्बित=5	न्यायालय में लम्बित=1 रद्द=1	न्यायालय में लम्बित=1 अनुसंधाना-धीन=1	न्यायालय में लम्बित=3	न्यायालय में लम्बित=2
मई, 2008	न्यायालय में लम्बित=1 अनुसंधाना-धीन=3	न्यायालय में लम्बित=3	न्यायालय में लम्बित=6	अदमपता=2 न्यायालय में लम्बित=2	न्यायालय में लम्बित=2
जून, 2008	न्यायालय में लम्बित=12 अनुसंधाना-धीन=3 रद्द=1	न्यायालय में लम्बित=7	न्यायालय में लम्बित=2 अनुसंधाना-धीन=1 रद्द=1	न्यायालय में लम्बित=2 अनुसंधाना-धीन=1	शून्य
जुलाई, 2008	न्यायालय में लम्बित=6 अनुसंधाना-धीन=1	न्यायालय में लम्बित=2	न्यायालय में लम्बित=5 अनुसंधाना-धीन=2	न्यायालय में लम्बित=2	न्यायालय में लम्बित=1
अगस्त, 2008	न्यायालय में लम्बित=2 अनुसंधाना-धीन=1	न्यायालय में लम्बित=2 अनुसंधाना-धीन=2	न्यायालय में लम्बित=2 अनुसंधाना-धीन=2	न्यायालय में लम्बित=2 अनुसंधाना-धीन=1	न्यायालय में लम्बित=5
सितम्बर, 2008	न्यायालय में लम्बित=2 अनुसंधाना-धीन=2	न्यायालय में लम्बित=4 अनुसंधाना-धीन=1	न्यायालय में लम्बित=5 अनुसंधाना-धीन=2 रद्द=2	न्यायालय में लम्बित=3 अदमपता=2	न्यायालय में लम्बित=1
अक्तूबर, 2008	न्यायालय में लम्बित=1	न्यायालय में लम्बित=3 अनुसंधाना-धीन=1	न्यायालय में लम्बित=3 रद्द=1	न्यायालय में लम्बित=3 अनुसंधाना-धीन=1	न्यायालय में लम्बित=2
नवम्बर, 2008	न्यायालय में लम्बित=4	न्यायालय में लम्बित=2 अनुसंधाना-धीन=3	न्यायालय में लम्बित=1 अनुसंधाना-धीन=3	न्यायालय में लम्बित=1 अनुसंधाना-धीन=1	न्यायालय में लम्बित=3 अनुसंधाना-धीन=1

माह	हिसार	सिरसा	भिवानी	जींद	फतेहाबाद
दिसम्बर, 2008	शून्य	न्यायालय में लम्बित=1 अनुसंधाना-धीन=5	रद्द=1 अनुसंधाना-धीन=4	अनुसंधाना-धीन=7	शून्य
जनवरी, 2009	अनुसंधाना-धीन=1	अनुसंधाना-धीन=1	अनुसंधाना-धीन=3	अनुसंधाना-धीन=3	अनुसंधाना-धीन=1
बलात्कार					
अप्रैल, 2008	रद्द=1	न्यायालय में लम्बित=1	न्यायालय में लम्बित=1 बरी=1	रद्द=2	बरी=1 न्यायालय में लम्बित=1
मई, 2008	न्यायालय में लम्बित=3 रद्द=1	न्यायालय में लम्बित=2	न्यायालय में लम्बित=2 बरी=1	न्यायालय में लम्बित=2 रद्द=1	शून्य
जून, 2008	न्यायालय में लम्बित=2	न्यायालय में लम्बित=2	रद्द=1 न्यायालय में लम्बित=3 बरी=1	रद्द=3 अनुसंधाना-धीन=2	न्यायालय में लम्बित=1
जुलाई, 2008	न्यायालय में लम्बित=3	न्यायालय में लम्बित=2 अनुसंधाना-धीन=1 रद्द=1	न्यायालय में लम्बित=5 अनुसंधाना-धीन=1	न्यायालय में लम्बित=5 रद्द=1	न्यायालय में लम्बित=1
अगस्त, 2008	न्यायालय में लम्बित=3	न्यायालय में लम्बित=4 अनुसंधाना-धीन=1 रद्द=1	न्यायालय में लम्बित=3 अदम्पता=1	न्यायालय में लम्बित=4 रद्द=1	न्यायालय में लम्बित=1 रद्द=1
सितम्बर, 2008	न्यायालय में लम्बित=1 रद्द=1	न्यायालय में लम्बित=3	न्यायालय में लम्बित=2 अनुसंधाना-धीन=1 रद्द=1	न्यायालय में लम्बित=2	शून्य
अक्तूबर, 2008	न्यायालय में लम्बित=1	न्यायालय में लम्बित=2	न्यायालय में लम्बित=1	न्यायालय में लम्बित=4 रद्द=1	न्यायालय में लम्बित=2

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

माह	हिसार	सिरसा	भिवानी	जीन्द	फतेहाबाद
नवम्बर, 2008	शून्य	अनुसंधाना-धीन=8	न्यायालय में लम्बित=1	न्यायालय में लम्बित=1	शून्य
दिसम्बर, 2008	अनुसंधाना-धीन=1	अनुसंधाना-धीन=2	अनुसंधाना-धीन=1	शून्य	शून्य
जनवरी, 2009	अनुसंधाना-धीन=1	अनुसंधाना-धीन=1	अनुसंधाना-धीन=6	अनुसंधाना-धीन=3	अनुसंधाना-धीन=1
डकैती					
अप्रैल, 2008	शून्य	शून्य	न्यायालय में लम्बित=3 अनुसंधाना-धीन=1	शून्य	शून्य
मई, 2008	शून्य	शून्य	न्यायालय में लम्बित=1	शून्य	शून्य
जून, 2008	शून्य	शून्य	न्यायालय में लम्बित=1 रद्द=1	शून्य	शून्य
जुलाई, 2008	शून्य	न्यायालय में लम्बित=1	न्यायालय में लम्बित=1	शून्य	न्यायालय में लम्बित=1
अगस्त, 2008	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सितम्बर, 2008	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अक्तूबर, 2008	न्यायालय में लम्बित=1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
नवम्बर, 2008	शून्य	शून्य	न्यायालय में लम्बित=1	शून्य	शून्य
दिसम्बर, 2008	शून्य	शून्य	न्यायालय में लम्बित=2	शून्य	शून्य
जनवरी, 2009	शून्य	शून्य	शून्य	अनुसंधाना-धीन=1	शून्य
फिरौती					
जुलाई, 2008	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	न्यायालय में लम्बित=2

हत्या के केसों की वर्तमान स्थिति (फरीदाबाद मण्डल)

माह	फरीदाबाद	पलवल	नारनौल	रेवाड़ी	मेवात
अप्रैल, 2008	रद्द=1 न्यायालय में लम्बित=3	न्यायालय में लम्बित=1 अनुसंधाना-धीन=1 अदमपता=1	न्यायालय में लम्बित=1 अनुसंधाना-धीन=1 रद्द=1	न्यायालय में लम्बित=2	शून्य
मई, 2008	न्यायालय में लम्बित=2 अनुसंधाना-धीन=2	न्यायालय में लम्बित=2 अनुसंधाना-धीन=2	न्यायालय में लम्बित=2	न्यायालय में लम्बित=1	न्यायालय में लम्बित=1
जून, 2008	न्यायालय में लम्बित=4	न्यायालय में लम्बित=2 अनुसंधाना-धीन=1	अनुसंधाना-धीन=1	न्यायालय में लम्बित=1 अनुसंधाना-धीन=3	न्यायालय में लम्बित=2 बरी=1
जुलाई, 2008	न्यायालय में लम्बित=11 अनुसंधाना-धीन=1	न्यायालय में लम्बित=1 रद्द=1	न्यायालय में लम्बित=1 रद्द=2	न्यायालय में लम्बित=1	न्यायालय में लम्बित=1
अगस्त, 2008	न्यायालय में लम्बित=2 अनुसंधाना-धीन=3 अदमपता=1	न्यायालय में लम्बित=4 अनुसंधाना-धीन=1	न्यायालय में लम्बित=3 अनुसंधाना-धीन=2	अनुसंधाना-धीन=1	रद्द=1
सितम्बर, 2008	न्यायालय में लम्बित=2 अनुसंधाना-धीन=3	न्यायालय में लम्बित=3	न्यायालय में लम्बित=2	न्यायालय में लम्बित=1 अनुसंधाना-धीन=1	न्यायालय में लम्बित=3
अक्तूबर, 2008	न्यायालय में लम्बित=4 अनुसंधाना-धीन=3 अदमपता=1	न्यायालय में लम्बित=3	न्यायालय में लम्बित=2	अनुसंधाना-धीन=2	न्यायालय में लम्बित=1 अनुसंधाना-धीन=1
नवम्बर, 2008	न्यायालय में लम्बित=1 अनुसंधाना-धीन=2	न्यायालय में लम्बित=2 अनुसंधाना-धीन=3	न्यायालय में लम्बित=2	अनुसंधाना-धीन=1 रद्द=1	अनुसंधाना-धीन=2

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

माह	फरीदाबाद	पलवल	नारनौल	रेवाड़ी	मेवात
दिसम्बर, 2008	अनुसंधाना-धीन=1	शून्य	न्यायालय में लम्बित=1 अनुसंधाना-धीन=2	न्यायालय में लम्बित=1 अनुसंधाना-धीन=2	अनुसंधाना-धीन=2
जनवरी, 2009	अनुसंधाना-धीन=3	अनुसंधाना-धीन=1	शून्य	अनुसंधाना-धीन=1	अनुसंधाना-धीन=3
बलात्कार					
अप्रैल, 2008	न्यायालय में लम्बित=7	न्यायालय में लम्बित=1	न्यायालय में लम्बित=1 रद्द=1	शून्य	न्यायालय में लम्बित=5 रद्द=2 बरी=1
मई, 2008	न्यायालय में लम्बित=1	न्यायालय में लम्बित=1 रद्द=1	न्यायालय में लम्बित=2	रद्द=1	रद्द=2
जून, 2008	न्यायालय में लम्बित=4 अनुसंधाना-धीन=1 रद्द=1	न्यायालय में लम्बित=3	अनुसंधाना-धीन=1	न्यायालय में लम्बित=2 बरी=1	न्यायालय में लम्बित=1 रद्द=1
जुलाई, 2008	न्यायालय में लम्बित=1 अनुसंधाना-धीन=2 रद्द=1	न्यायालय में लम्बित=1	न्यायालय में लम्बित=2	न्यायालय में लम्बित=3	न्यायालय में लम्बित=1
अगस्त, 2008	न्यायालय में लम्बित=4 अनुसंधाना-धीन=1	न्यायालय में लम्बित=6	न्यायालय में लम्बित=3	न्यायालय में लम्बित=2	न्यायालय में लम्बित=2
सितम्बर, 2008	न्यायालय में लम्बित=1	न्यायालय में लम्बित=1 अनुसंधाना-धीन=2 रद्द=1	शून्य	रद्द=3 न्यायालय में लम्बित=2	न्यायालय में लम्बित=2 अनुसंधाना-धीन=2 रद्द=1
अक्तूबर, 2008	न्यायालय में लम्बित=1	न्यायालय में लम्बित=2	न्यायालय में लम्बित=1	न्यायालय में लम्बित=4	न्यायालय में लम्बित=4

माह	फरीदाबाद	पलवल	नारनौल	रेवाड़ी	नेवात
	अनुसंधाना-धीन=4		अनुसंधाना-धीन=2	अनुसंधाना-धीन=1 रद्द=1	
नवम्बर, 2008	न्यायालय में लम्बित=5 अनुसंधाना-धीन=1	रद्द=2 न्यायालय में लम्बित=1	न्यायालय में लम्बित=2 अनुसंधाना-धीन=1	शून्य	अनुसंधाना-धीन=1
दिसम्बर, 2008	अनुसंधाना-धीन=2	शून्य	शून्य	न्यायालय में लम्बित=1 अनुसंधाना-धीन=2	न्यायालय में लम्बित=1 अनुसंधाना-धीन=1
जनवरी, 2009	अनुसंधाना-धीन=2	अनुसंधाना-धीन=1	अनुसंधाना-धीन=1	शून्य	अनुसंधाना-धीन=1
डकैती					
अप्रैल, 2008	न्यायालय में लम्बित=1	शून्य	न्यायालय में लम्बित=2	शून्य	न्यायालय में लम्बित=1
मई, 2008	शून्य	न्यायालय में लम्बित=1	शून्य	न्यायालय में लम्बित=1	शून्य
जून, 2008	शून्य	न्यायालय में लम्बित=1	शून्य	शून्य	शून्य
जुलाई, 2008	शून्य	शून्य	शून्य	न्यायालय में लम्बित=1	शून्य
अगस्त, 2008	न्यायालय में लम्बित=1	शून्य	शून्य	रद्द=1	न्यायालय में लम्बित=1
सितम्बर, 2008	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अक्तूबर, 2008	अनुसंधाना-धीन=1	शून्य	शून्य	न्यायालय में लम्बित=1	शून्य
नवम्बर, 2008	शून्य	अनुसंधाना-धीन=1	शून्य	शून्य	शून्य
दिसम्बर, 2008	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जनवरी, 2009	अनुसंधाना-धीन=1	शून्य	अनुसंधाना-धीन=1	अनुसंधाना-धीन=1	शून्य

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

माह	फरीदाबाद	पलवल	नारनौल	रेवाड़ी	मेवात
फिरौती					
दिसम्बर, 2008	अनुसंधाना-धीन=1	शून्य	शून्य	शून्य	रद्द=1 (जून-2003)

हत्या के केसों की वर्तमान स्थिति (रोहतक मण्डल)

माह	रोहतक	सोनीपत	करनाल	पानीपत	झज्जर
अप्रैल, 2008	न्यायालय में लम्बित=3 अदम्पता=1	न्यायालय में लम्बित=3 अनुसंधाना-धीन=1	न्यायालय में लम्बित=2 अनुसंधाना-धीन=2	न्यायालय में लम्बित=3 अनुसंधाना-धीन=1	न्यायालय में लम्बित=3 अदम्पता=1 रद्द=2
मई, 2008	न्यायालय में लम्बित=4 अनुसंधाना-धीन=1	न्यायालय में लम्बित=8 अनुसंधाना-धीन=1 अदम्पता=1	न्यायालय में लम्बित=1 अनुसंधाना-धीन=1	न्यायालय में लम्बित=3 रद्द=1	न्यायालय में लम्बित=3 अनुसंधाना-धीन=1 रद्द=1
जून, 2008	न्यायालय में लम्बित=4	न्यायालय में लम्बित=4 अनुसंधाना-धीन=3 रद्द=3	न्यायालय में लम्बित=1	न्यायालय में लम्बित=3 अनुसंधाना-धीन=1 रद्द=1	न्यायालय में लम्बित=4 अनुसंधाना-धीन=3
जुलाई, 2008	न्यायालय में लम्बित=2 अदम्पता=1	न्यायालय में लम्बित=7 अनुसंधाना-धीन=1 रद्द=1	न्यायालय में लम्बित=7 अनुसंधाना-धीन=1	न्यायालय में लम्बित=2	न्यायालय में लम्बित=5 अनुसंधाना-धीन=2 अदम्पता=1
अगस्त, 2008	न्यायालय में लम्बित=4	न्यायालय में लम्बित=1 अनुसंधाना-धीन=1	न्यायालय में लम्बित=2 अदम्पता=1 रद्द=1	न्यायालय में लम्बित=4 अनुसंधाना-धीन=1	न्यायालय में लम्बित=8 रद्द=1
सितम्बर, 2008	न्यायालय में लम्बित=8	न्यायालय में लम्बित=3 अनुसंधाना-धीन=1	न्यायालय में लम्बित=2 अनुसंधाना-धीन=4	न्यायालय में लम्बित=5 अनुसंधाना-धीन=1	न्यायालय में लम्बित=3 अनुसंधाना-धीन=1 अदम्पता=1
अक्तूबर, 2008	न्यायालय में लम्बित=4	न्यायालय में लम्बित=8	न्यायालय में लम्बित=1	न्यायालय में लम्बित=1	न्यायालय में लम्बित=1

माह	रोहतक	सोनीपत	करनाल	पानीपत	झज्जर
	अनुसंधाना-धीन=1	अनुसंधाना-धीन=4	अनुसंधाना-धीन=2	अनुसंधाना-धीन=2	अनुसंधाना-धीन=3
नवम्बर, 2008	न्यायालय में लम्बित=4 अनुसंधाना-धीन=1	न्यायालय में लम्बित=3 अनुसंधाना-धीन=4	न्यायालय में लम्बित=1 अनुसंधाना-धीन=2	न्यायालय में लम्बित=3 अनुसंधाना-धीन=2	न्यायालय में लम्बित=1 अनुसंधाना-धीन=2
दिसम्बर, 2008	न्यायालय में लम्बित=9 अनुसंधाना-धीन=2	न्यायालय में लम्बित=5 अनुसंधाना-धीन=5	न्यायालय में लम्बित=1 अनुसंधाना-धीन=3	न्यायालय में लम्बित=4 अनुसंधाना-धीन=1	अनुसंधाना-धीन=2
जनवरी, 2009	अनुसंधाना-धीन=5	अनुसंधाना-धीन=2	अनुसंधाना-धीन=1	न्यायालय में लम्बित=2 अनुसंधाना-धीन=1	अनुसंधाना-धीन=5

बलात्कार

अप्रैल, 2008	न्यायालय में लम्बित=3	न्यायालय में लम्बित=2 रद्द=2	शून्य	न्यायालय में लम्बित=1	न्यायालय में लम्बित=1
मई, 2008	अनुसंधाना-धीन=1	न्यायालय में लम्बित=4	न्यायालय में लम्बित=3	न्यायालय में लम्बित=2	न्यायालय में लम्बित=3
जून, 2008	न्यायालय में लम्बित=2 रद्द=1	न्यायालय में लम्बित=6	न्यायालय में लम्बित=8	न्यायालय में लम्बित=1 अनुसंधाना-धीन=2	न्यायालय में लम्बित=4 अनुसंधाना-धीन=1
जुलाई, 2008	न्यायालय में लम्बित=6 रद्द=1	अनुसंधाना-धीन=1	रद्द=1 न्यायालय में लम्बित=7 अनुसंधाना-धीन=1	न्यायालय में लम्बित=2	न्यायालय में लम्बित=1
अगस्त, 2008	न्यायालय में लम्बित=1	न्यायालय में लम्बित=1	न्यायालय में लम्बित=5 अनुसंधाना-धीन=1	न्यायालय में लम्बित=1	न्यायालय में लम्बित=1 अनुसंधाना-धीन=1
सितम्बर, 2008	न्यायालय में लम्बित=1	न्यायालय में लम्बित=3 अनुसंधाना-धीन=1	न्यायालय में लम्बित=2 अनुसंधाना-धीन=1	रद्द=2 न्यायालय में लम्बित=2	रद्द=1

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

माह	रोहतक	सोनीपत	करनाल	पानीपत	झज्जर
अक्तूबर, 2008	न्यायालय में लम्बित=2 अनुसंधाना-धीन=1	न्यायालय में लम्बित=2	न्यायालय में लम्बित=3 अनुसंधाना-धीन=1	न्यायालय में लम्बित=3 अनुसंधाना-धीन=3	न्यायालय में लम्बित=1 रद्द=1
नवम्बर, 2008	अनुसंधाना-धीन=3	अनुसंधाना-धीन=1 न्यायालय में लम्बित=2	न्यायालय में लम्बित=1 रद्द=1	शून्य	न्यायालय में लम्बित=2 अनुसंधाना-धीन=1
दिसम्बर, 2008	अनुसंधाना-धीन=2	न्यायालय में लम्बित=4 अनुसंधाना-धीन=2	न्यायालय में लम्बित=2 अनुसंधाना-धीन=3	न्यायालय में लम्बित=4 अनुसंधाना-धीन=1	न्यायालय में लम्बित=3
जनवरी, 2009	अनुसंधाना-धीन=3	शून्य	अनुसंधाना-धीन=2	अनुसंधाना-धीन=3	शून्य
डकैती					
अप्रैल, 2008	शून्य	शून्य	रद्द=1	न्यायालय में लम्बित=1	शून्य
मई, 2008	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जून, 2008	शून्य	न्यायालय में लम्बित=1	शून्य	न्यायालय में लम्बित=1	शून्य
जुलाई, 2008	न्यायालय में लम्बित=1	न्यायालय में लम्बित=1	शून्य	शून्य	शून्य
अगस्त, 2008	शून्य	शून्य	न्यायालय में लम्बित=1	शून्य	न्यायालय में लम्बित=1
सितम्बर, 2008	न्यायालय में लम्बित=1	शून्य	अनुसंधाना-धीन=1	शून्य	न्यायालय में लम्बित=1
अक्तूबर, 2008	शून्य	न्यायालय में लम्बित=1 रद्द=1	शून्य	शून्य	न्यायालय में लम्बित=1
नवम्बर, 2008	न्यायालय में लम्बित=1	न्यायालय में लम्बित=1 अनुसंधाना-धीन=2	शून्य	शून्य	अनुसंधाना-धीन=1
दिसम्बर, 2008	अनुसंधाना-धीन=1	शून्य	अनुसंधाना-धीन=1	शून्य	शून्य

माह	रोहतक	सोनीपत	करनाल	पानीपत	झज्जर
जनवरी, 2009	शून्य	अनुसंधाना-धीन=2	अनुसंधाना-धीन=1	शून्य	शून्य
फिरौती					
जून, 2008	न्यायालय में लम्बित=1	न्यायालय में लम्बित=1 (सितम्बर-2008)	शून्य	अनुसंधाना-धीन=1 (दिसम्बर-2008)	शून्य

हत्या के केसों की वर्तमान स्थिति (पुलिस आयुक्त, गुड़गांव तथा रेलवे)

माह	पुलिस आयुक्त, गुड़गांवा	रेलवे
अप्रैल, 2008	न्यायालय में लम्बित=1	न्यायालय में लम्बित=1
मई, 2008	न्यायालय में लम्बित=4 अनुसंधानाधीन=4 अदमपता=2	न्यायालय में लम्बित=2 रद्द=1
जून, 2008	न्यायालय में लम्बित=2 अनुसंधानाधीन=1	न्यायालय में लम्बित=2 अनुसंधानाधीन=1 रद्द=1
जुलाई, 2008	न्यायालय में लम्बित=3 अनुसंधानाधीन=3	रद्द=1
अगस्त, 2008	न्यायालय में लम्बित=8 अनुसंधानाधीन=4	अदमपता=3 रद्द=1
सितम्बर, 2008	न्यायालय में लम्बित=2	अदमपता=2
अक्तूबर, 2008	न्यायालय में लम्बित=2 अनुसंधानाधीन=7 रद्द=1	अदमपता=3
नवम्बर, 2008	न्यायालय में लम्बित=1 अनुसंधानाधीन=6	अदमपता=3 अनुसंधानाधीन=1
दिसम्बर, 2008	अनुसंधानाधीन=6	शून्य
जनवरी, 2009	अनुसंधानाधीन=3	अनुसंधानाधीन=2
बलात्कार		
अप्रैल, 2008	न्यायालय में लम्बित=6	शून्य
मई, 2008	शून्य	न्यायालय में लम्बित=1
जून, 2008	न्यायालय में लम्बित=3 अनुसंधानाधीन=1	शून्य
जुलाई, 2008	न्यायालय में लम्बित=2 अनुसंधानाधीन=1	शून्य
अगस्त, 2008	न्यायालय में लम्बित=7	शून्य

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

माह	पुलिस आयुक्त, गुड़गांव	रेलवे
सितम्बर, 2008	न्यायालय में लम्बित=5 अनुसंधानाधीन=1	शून्य
अक्तूबर, 2008	न्यायालय में लम्बित=2 अनुसंधानाधीन=1	न्यायालय में लम्बित=1
नवम्बर, 2008	अनुसंधानाधीन=1	शून्य
दिसम्बर, 2008	अनुसंधानाधीन=2	शून्य
जनवरी, 2009	अनुसंधानाधीन=2	शून्य
डकैती		
अप्रैल, 2008	न्यायालय में लम्बित=1 अनुसंधानाधीन=1 अदमपता=1	शून्य
मई, 2008	न्यायालय में लम्बित=1 अनुसंधानाधीन=1 रद्द=1	शून्य
जून, 2008	न्यायालय में लम्बित=1 अनुसंधानाधीन=2 अदमपता=1	शून्य
जुलाई, 2008	अनुसंधानाधीन=2	शून्य
अगस्त, 2008	न्यायालय में लम्बित=1 अनुसंधानाधीन=1	शून्य
सितम्बर, 2008	न्यायालय में लम्बित=3 अनुसंधानाधीन=1 रद्द=1	शून्य
अक्तूबर, 2008	न्यायालय में लम्बित=1	शून्य
नवम्बर, 2008	अनुसंधानाधीन=1	अदमपता=1 अनुसंधानाधीन=2
दिसम्बर, 2008	अनुसंधानाधीन=2	शून्य
जनवरी, 2009	अनुसंधानाधीन=1	शून्य
फिरौती		
अक्तूबर, 2008	अनुसंधानाधीन=1	शून्य
नवम्बर, 2008	रद्द=1	

Posting of Doctors

150. **Shri Naresh Yadav :** Will the Health Minister be pleased to state whether it is a fact that no doctor has been posted in the Community Health Centre Nangal Chaudhary ?

स्वास्थ्य मंत्री (बहिन करतार देवी) : श्रीमान् जी,

जी नहीं । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नांगल चौधरी में 3 डॉक्टर नियुक्त हैं ।

Junior Lecturers and Masters Working in SSA

146. **Shri Karan Singh Dalal :** Will the Education Minister be pleased to state the district-wise number of Junior Lecturers of Science faculty subject wise and the number of Science and Mathematic Masters working in SSA during the current academic session of 2008-09 ?

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : इस प्रश्न का उत्तर निम्न प्रकार से है :–

(क) राज्य में वर्तमान शैक्षिक सत्र 2008-09 में 31.5.08 की स्थिति अनुसार तक 82 विज्ञान स्कूल प्राध्यापक सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत पूर्णकालीन कार्यरत थे, जिनका जिलावार ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

क्रम संख्या	मुख्यालय/जिला	संख्या	विषय		
			भौतिक विज्ञान	रसायन विज्ञान	जीव विज्ञान
1	2	3	4	5	6
1.	मुख्यालय चण्डीगढ़	1	1	–	–
2.	अम्बाला	7	–	1	6
3.	भिवानी	2	–	1	1
4.	फरीदाबाद	7	3	3	1
5.	फतेहाबाद	1	–	–	1
6.	गुड़गांव	1	–	–	1
7.	हिसार	8	–	2	6
8.	झज्जर	4	1	–	3
9.	जींद	1	–	–	1
10.	करनाल	9	–	1	8
11.	कुरुक्षेत्र	6	–	1	5

[श्री मांगे राम गुप्ता]

1	2	3	4	5	6
12.	कैथल	–	–	–	–
13.	मेवात	–	–	–	–
14.	महेन्द्रगढ़	2	–	–	2
15.	पंचकूला	3	2	–	1
16.	पानीपत	–	–	–	–
17.	रिवाड़ी	2	–	–	2
18.	रोहतक	17	2	4	11
19.	सोनीपत	6	1	1	4
20.	सिरसा	5	–	1	4
21.	यमुनानगर	–	–	–	–
	कुल	82	10	15	57

(ख) वर्तमान शैक्षिक सत्र 2008-09 में 31.5.08 की स्थिति अनुसार तक सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 35 विज्ञान अध्यापक तथा 65 गणित अध्यापक पूर्णकालीन कार्यरत थे/हैं, जिनका जिलावार ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

क्रम संख्या	मुख्यालय/जिला	विषय	
		साईंस	गणित
1.	मुख्यालय चण्डीगढ़	–	1
2.	अम्बाला	–	3
3.	भिवानी	5	14
4.	फरीदाबाद	2	1
5.	फतेहाबाद	–	–
6.	गुड़गांव	–	1
7.	हिसार	5	5
8.	झज्जर	1	5
9.	जींद	6	3
10.	करनाल	–	–
11.	कुरुक्षेत्र	–	4
12.	कैथल	2	3

1	2	3	4	5	6
13.	मेवात		—	3	
14.	महेन्द्रगढ़		5	6	
15.	पंचकूला		—	3	
16.	पानीपत		—	—	
17.	रिवाड़ी		—	5	
18.	रोहतक		4	5	
19.	सोनीपत		1	—	
20.	सिरसा		4	3	
21.	यमुनानगर		—	—	
	कुल		35	65	

(ग) राज्य सरकार के निर्णय अनुसार ए०बी०आर०सी० के रूप में कार्यरत सभी प्राध्यापकों, अध्यापकों को उनके मूल संवर्ग में नियुक्ति के लिए आयुक्त एवं महानिदेशक, शिक्षा हरियाणा को लिखा गया है।

Opening of PHC's

151. Shri Naresh Yadav : Will the Health Minister be pleased to state :—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Primary Health Centre in the villages Bachhod and Kanti in district Mahendragarh; and

(b) if so, the time by which the above said Primay Health Centres are likely to be opened ?

स्वास्थ्य मंत्री (बहिन करतार देवी) :

(क) जी श्रीमान जी, उप स्वास्थ्य केन्द्र कांटी का दर्जा बढ़ा कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र करना प्रस्तावित है। बाछौद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहले से कार्यरत है।

(ख) समय सीमा नहीं दी जा सकती।

Posts Lying Vacant in DHBVN

139. Dr. Sita Ram : Will the Power Minister be pleased to state :—

(a) the total number of posts of technical staff like JE's, Linemen etc. and non technical staff like clerks, sweepers, chowkidar etc. in DHBVN;

[Dr. Sita Ram]

Haryana together with the number of posts lying vacant and since when; and

(b) the total number of posts lying vacant in the said Nigam in Sirsa District; together with the time by which the such vacant posts are likely to be filled up ?

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) :

श्रीमान, विवरण माननीय सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(ए) कुल स्वीकृत पद तथा द०ह०बि०वि०नि० के अन्तर्गत खाली पदों को दर्शाने वाला विवरण :-

द०ह०बि०वि०नि० के अन्तर्गत तकनीकी स्टाफ जैसे जे०ई०, ए०एफ०एम०, एल०एम०, ए०एल०एम० तथा नॉन-टैक्नीकल स्टाफ जैसे लिपिक, सफाई कर्मचारी, चौकीदार के कुल स्वीकृत पदों की संख्या तथा खाली पड़े पदों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

क्रम संख्या	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	31.12.2008 को कार्यरत	खाली पद
	(तकनीकी श्रेणी-III)			
1	2	3	4	5
1.	सहायक भण्डार अधिकारी	5	1	4
2.	एच०एस०के०	4	3	1
3.	स्टोर कीपर	10	12	2
4.	स्टोर मुंशी	15	8	7
5.	स्टोर वैरीफायर	1	—	1
6.	सी०डी०एम०	3	3	—
7.	सी०एच०डी०	8	8	—
8.	एच०डी०एम०	37	36	1
9.	ड्राफ्टस मैन	88	48	40
10.	जे०ई०/सिविल	24	21	3
11.	जे०ई०-I	118	83	35
12.	जे०ई०	371	262	109
13.	फोरमैन	3	—	3
14.	ए०एफ०एम०	645	386	259

1	2	3	4	5
15.	लाइनमैन	2504	2287	217
16.	ए०एल०एम०	6042	2676	3366
17.	केबल जवाईन्टर	1	–	1
18.	एस०एस०ए०	232	212	20
19.	ए०एस०एस०ए०	472	405	67
20.	एस०ए०	448	191	257
21.	उपकरण मिस्त्री	1	–	1
22.	वरिष्ठ लैब अटेन्डैंट	16	15	1
23.	वरिष्ठ टेक्निशियन	1	–	1
24.	इलैक्ट्रिशियन	2	1	1
25.	टेक्निशियन ग्रेड-I	10	–	10
26.	टेक्निशियन ग्रेड-II	4	–	4
27.	हैल्पर ग्रेड-II	42	–	42
28.	लैब सहायक	6	6	–
29.	मेसन	1	–	1
30.	कारपेन्टर	4	2	2
31.	लैब अटेन्डैंट (एम० एवं पी०)	25	22	3
	योग	11143	6688	4455
	(तकनीकी श्रेणी–iv)			
1.	स्टोर अटेन्डैंट	94	30	64
2.	वर्क मेट/टी-मेट	50	44	6
3.	हैल्पर ग्रेड-I	23	–	23
4.	कुशल हैल्पर	7	5	2
5.	पलम्बर/पाईप फिटर	2	2	–
	योग	176	81	95
	(गैर-तकनीकी श्रेणी–III)			
1.	अनुभाग अधिकारी	25	10	15
2.	डिवीजनल अकाऊंटैंट/ रैवन्यु ऑडिटर	103	48	55
3.	सर्कल अधीक्षक	8	8	–

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

1	2	3	4	5
4.	उप-अधीक्षक	5	5	—
5.	सहायक/मुख्यालय	63	62	1
6.	हैड क्लर्क	34	22	12
7.	सर्कल सहायक	15	13	2
8.	वाणिज्यिक सहायक/सहायक लेखापाल	119	115	4
9.	उच्च श्रेणी लिपिक (मुख्यालय)	59	47	12
10.	उच्च श्रेणी लिपिक (फील्ड)	577	253	324
11.	निम्न श्रेणी लिपिक (मुख्यालय)	67	49	18
12.	उच्च श्रेणी लिपिक (फील्ड)/ कैशियर	1144	810	334
13.	मीटर रीडर	530	381	149
14.	हैड मिस्ट्रेस	1	1	—
15.	बी०एड० अध्यापक	6	1	5
16.	जे०बी०टी० अध्यापक	13	9	4
17.	पी०टी०आई०	1	—	1
18.	मेट्रन/नर्स	1	1	—
19.	डी०एम०ए०	1	1	—
20.	पम्प ड्राईवर	8	6	2
21.	क्रेन ड्राईवर	6	—	6
22.	ड्राईवर (मुख्यालय)	18	18	—
23.	ड्राईवर (फील्ड)	264	181	83
24.	वर्क सुपरवाईजर	3	2	1
25.	निजि सहायक	13	13	—
26.	वरिष्ठ आशुलिपिक	19	19	—
27.	कनिष्ठ आशुलिपिक	73	32	41
28.	आशुटंकक	21	6	15
29.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	18	—	18
30.	हिन्दी अनुवादक	2	2	—
31.	कनिष्ठ फोटोग्राफर	1	—	1

1	2	3	4	5
32.	सुरक्षा अधिकारी	3	1	2
33.	सुरक्षा हवलदार	13	6	7
34.	चौकसी निरीक्षक	6	1	5
35.	उप निरीक्षक	7	1	6
36.	ए०एस०आई०	3	7	4
37.	मुख्य सिपाही	9	11	2
38.	सिपाही	15	10	5
39.	फार्मसिस्ट	12	7	5
40.	रेस्टोरर	—	3	3
41.	कलचर सहायक	—	—	—
42.	पब्लिसिटी कोआर्डिनेटर	—	—	—
43.	लेब टेक्निशियन (स्वास्थ्य)	3	1	2
44.	वरिष्ठ फार्मसिस्ट	—	—	—
	योग	3289	2163	1126
	(गैर-तकनीकी श्रेणी–IV)			
1.	बिल वितरक	367	145	222
2.	हवलदार (मुख्यालय)	13	13	—
3.	हवलदार (फील्ड)	8	5	3
4.	दफतरी (फील्ड)	7	2	5
5.	मुख्य सफाई कर्मचारी (एफ)	1	1	—
6.	सफाई कर्मचारी	57	54	3
7.	संदेशवाहक (मुख्यालय)	118	115	3
8.	संदेशवाहक (फील्ड)	346	303	43
9.	संदेशवाहक-कम-सेड	4	4	
10.	सफाई कर्मचारी-कम-चौकीदार	2	—	2
11.	चौकीदार	208	127	81
12.	स्विवर मैन	14	4	10
13.	सहायक पम्प ड्राईवर	11	3	8
14.	माली	48	42	6
15.	वाशर मैन	1	1	—

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

1	2	3	4	5
16.	क्लीनर	15	7	8
17.	कूक	2	2	—
18.	चौकीदार-कम-कूक	6	3	3
19.	सुरक्षा गार्ड	94	11	83
20.	अटेंडेन्ट	1	1	—
	योग	1323	843	480

(मुख्य सारांश)

1.	तकनीकी (श्रेणी-III)	11143	6688	4455
2.	तकनीकी (श्रेणी-IV)	176	81	95
3.	गैर-तकनीकी (श्रेणी-III)	3289	2163	1126
4.	गैर-तकनीकी (श्रेणी-IV)	1323	843	480
	योग	15931	9775	6156

Haryana Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY Chandigarh

कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों की पदोन्नति/सेवानिवृति/मृत्यु के कारण खाली हुए पदों को सीधी भर्ती या निम्न पदों से पदोन्नति द्वारा भरा जा रहा है। यह एक लगातार प्रक्रिया है।

(बी) उक्त निगम के जिला सिरसा में पड़े खाली पदों की संख्या निम्न प्रकार है :—

क्रम संख्या	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	खाली पद
1	2	3	4
1.	सहायक कार्यकारी अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता	14	9
2.	जे०ई०/जे०ई०-I (विद्युत)	40	0
3.	जे०ई०/सिविल	2	1
4.	ए०एफ०एम०	64	5
5.	एस०एस०ए०	38	4
6.	ए०एस०एस०ए०	41	1
7.	एस०ए०	60	39
8.	लाइन मैन	279	27
9.	ए०एल०एम०	681	460

1	2	3	4
10.	सर्कल सहायक	2	1
11.	वाणिज्यिक सहायक	14	5
12.	कनिष्ठ आशुलिपिक	4	2
13.	उच्च श्रेणी लिपिक	56	39
14.	निम्न श्रेणी लिपिक (कैश)	44	34
15.	निम्न श्रेणी लिपिक	87	26
16.	मीटर रीडर	51	23
17.	झाप्टमैन	8	2
18.	ड्राईवर	34	12
19.	ए०पी०डी०	4	3
20.	चौकीदार	32	9
21.	दफ्तरी	1	1
22.	बिल वितरक	45	26
23.	सफाई कर्मचारी	12	6
24.	सिथरमैन	3	1
	योग	1616	736

उपरोक्त खाली पदों को अगले वित्तीय वर्ष के दौरान अर्थात् वित्तीय वर्ष 2009-10 के अन्त तक खाली पदों को भरने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

निम्नलिखित पदों को भरने के लिए मांग हरियाणा स्टाफ सलेक्शन कमीशन को भेज दी गई है जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है।

क्र०सं०	पद का नाम	मांगे गए पदों की संख्या
1.	ए०एल०एम०	1000
2.	एस०ए०	100
3.	वू०डी०सी०	66
4.	एल०डी०सी०	142
5.	लेखापाल	20
6.	ऐ०ई० (ई०)	100
7.	ए०ई० (ई०)	63
8.	कम्पनी सचिव	1

Number of Recognized Private Senior Secondary Schools

147. Shri Karan Singh Dalal : Will the Education Minister be pleased to state the districtwise number of recognized private Senior Secondary Schools in the state in Rural and Urban area separately in which Science faculty Medical and Non-Medical or both is being run during the current academic session 2008-09 alongwith the number of students enrolled in +1 and +2 in the above faculties ?

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : श्रीमान जी, अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है :–

जिला	निजी मान्यता प्राप्त ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में पृथक पृथक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की संख्या जिनमें वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2008-09 में विज्ञान संकाय चल रहा है।		वर्ष 2008-09 के दौरान चलाई जा रही संकाय की वर्तमान स्थिति			वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2008-09 में पंजीकृत/दाखिल छात्रों की संख्या	
	ग्रामीण	शहरी	मेडिकल	नॉन-मेडिकल	दोनों	10+1	10+2
1	2	3	4	5	6	7	8
अम्बाला	शून्य	11	शून्य	8	3	651	556
भिवानी	23	5	2	13	13	940	746
फरीदाबाद	2	22	शून्य	15	9	1777	1682
फतेहाबाद	1	3	शून्य	शून्य	4	204	137
गुड़गांव	7	4	शून्य	10	1	605	500
हिसार	शून्य	9	शून्य	4	5	471	294
जीन्द	4	14	शून्य	2	16	1850	1493
झज्जर	3	8	शून्य	8	3	236	185
करनाल	7	4	शून्य	10	1	288	193
कुरुक्षेत्र	2	6	शून्य	6	2	413	303
कैथल	2	13	6	4	5	1011	1083
मेवात	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
नारनौल	5	7	शून्य	6	6	614	458
पानीपत	9	5	शून्य	6	8	1012	885

1	2	3	4	5	6	7	8
पंचकूला	शून्य	2	शून्य	शून्य	2	30	41
रोहतक	7	10	शून्य	7	10	872	932
रेवाड़ी	22	2	शून्य	14	10	981	771
सोनीपत	10	18	शून्य	15	13	1311	1216
सिरसा	5	10	शून्य	4	11	570	262
यमुनानगर	2	11	शून्य	7	6	1069	909

Persons who got Benefit under Ladli Yojana

143. Shri Naresh Yadav : Will the Women & Child Development Minister be pleased to state the number of persons who got benefit under Ladli Yojana during the period from 2005 to 2008 togetherwith the number of girls who have been provided the amount of marriage Shagun at the time of their marriage alongwith the date-wise details thereof ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमति करतार देवी) : श्रीमान जी, वर्ष 2005 से 2008 तक की समय अवधि के दौरान लाडली योजना के अन्तर्गत 66423 व्यक्तियों/लड़कियों को लाभ प्रदान किया गया। लाडली योजना के अन्तर्गत विवाह-शगुन का प्रावधान नहीं है।

Upgradation of Schools

140. Dr. Sita Ram : Will the Education Minister be pleased to state the constituency-wise total number of schools upgraded from Middle to High School and High School to Senior Secondary School in the financial year 2008-09 ?

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : श्रीमान जी, वित्तीय वर्ष 2008-09 में माध्यमिक विद्यालय से उच्च विद्यालय एवं उच्च विद्यालय से वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत किए गए कुल सरकारी विद्यालयों की निर्वाचन क्षेत्रवार स्थिति निम्नलिखित है :–

क्रम संख्या	विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र	स्तरोन्नत किए गए स्कूल		
		माध्यमिक से उच्च	उच्च से वरिष्ठ माध्यमिक	कुल
1	2	3	4	5
1.	अम्बाला शहर	–	–	–
2.	मुलाना	–	1	1

[श्री मांगे राम गुप्ता]

1	2	3	4	5
3.	नारायणगढ़	—	—	—
4.	नग्गल	—	4	4
5.	अम्बाला छावनी	—	—	—
6.	दादरी	1	—	1
7.	लोहारू	—	—	—
8.	मुंढ़ाल खुर्द	—	2	2
9.	बवानी खेड़ा	—	—	—
10.	तोशाम	—	1	1
11.	भिवानी	—	—	—
12.	बाढड़ा	—	—	—
13.	बल्लभगढ़	—	—	—
14.	नेवला महाराजपुर	—	—	—
15.	फरीदाबाद	—	—	—
16.	पलवल	—	1	1
17.	हसनपुर	—	—	—
18.	हथीन	—	—	—
19.	फतेहाबाद	2	2	4
20.	रतिया	—	1	1
21.	टोहाना	—	1	1
22.	भट्टूकलां	1	—	1
23.	नूंह	—	—	—
24.	तावडू	—	—	—
25.	फिरोजपुर झिरका	—	—	—
26.	गुड़गांव	—	—	—
27.	सोहना	—	—	—
28.	पटौदी	1	—	1
29.	हिसार	—	—	—
30.	आदमपुर	—	—	—
31.	घिराय	1	—	1
32.	नारनौंद	—	2	2

1	2	3	4	5
33.	हांसी	—	1	1
34.	बरवाला	—	—	—
35.	बादली	—	1	1
36.	सालहावास	2	1	3
37.	बेरी	—	4	4
38.	झज्जर	—	2	2
39.	बहादुरगढ़	—	1	1
40.	जुलाना	2	3	5
41.	उचाना कलां	—	—	—
42.	सफीदों	1	1	2
43.	जीन्द	—	2	2
44.	नरवाना	—	—	—
45.	कलायत	—	—	—
46.	राजौंद	2	1	3
47.	गुहला	2	2	4
48.	पुंडरी	—	—	—
49.	कैथल	—	1	1
50.	पाई	—	3	3
51.	असन्ध	1	—	1
52.	नीलोखेड़ी	—	1	1
53.	इन्द्री	1	2	3
54.	घरौंडा	—	—	—
55.	करनाल	—	—	—
56.	जुंडला	—	2	2
57.	पेहवा	1	2	3
58.	शाहबाद	2	2	4
59.	थानेसर	—	—	—
60.	अटेली	—	—	—
61.	नारनौल	—	—	—
62.	महेन्द्रगढ़	—	1	1
63.	कालका	—	—	—

[श्री मांगे राम गुप्ता]

1	2	3	4	5
64.	समालखा	4	2	6
65.	पानीपत	—	—	—
66.	गौलधा	2	4	6
67.	जादूसाना	—	—	—
68.	रेवाड़ी	—	1	1
69.	बावल	—	1	1
70.	हसनगढ़	3	3	6
71.	रोहतक	—	—	—
72.	कलानौर	1	—	1
73.	महम	4	5	9
74.	किलोई	—	3	3
75.	ऐलनाबाद	—	—	—
76.	सिरसा	—	—	—
77.	डबवाली	—	—	—
78.	दड़बाकलां	—	1	1
79.	रोड़ी	—	—	—
80.	बरौदा	—	—	—
81.	सोनीपत	—	—	—
82.	राई	—	—	—
83.	गोहाना	1	—	1
84.	कैलाना	1	1	2
85.	रोहट	—	3	3
86.	यमुनानगर	—	—	—
87.	रादौर	—	—	—
88.	सढौरा	—	1	1
89.	छछरौली	1	1	2
90.	जगाधरी	—	1	1
	कुल	37	75	112

निन्दा प्रस्ताव/उसका वापिस लेना

15.00 बजे

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने और हमारे कई साथियों ने एक निंदा प्रस्ताव आपकी सेवा में भेजा है। (विघ्न)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, please maintain the silence.

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, इस सदन की मर्यादा होती है कि पहले दिन जब सदन बैठता है तो उस दिन सदन के अन्दर देश और हमारे प्रदेश की जो बड़ी हस्तियां दुर्घटनाओं में या आकस्मिक निधन से हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती हैं उनके बारे में शोक प्रस्ताव इस सदन में पारित किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख की बात है कि पहली मर्तबा इस हरियाणा की विधानसभा में इस मर्यादा से हटकर इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने जानबूझ कर एक ऐसा बर्ताव किया जिसकी हमें निंदा करनी चाहिए। जब छः तारीख को यह सदन इस देश की महान विभूतियों को श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा था जिसमें हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री आर० वैंकटरमन, पूर्व प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह और हमारे ही अपने प्रदेश के बहुत बड़े महान सपूत जो संविधान सभा के आखिरी जीवित सदस्य बचे थे वे भी हमें छोड़कर चले गए हैं। उस वक्त हमारे कई माननीय सदस्यों ने लिखित प्रस्ताव भेजा। मुम्बई के अन्दर जो निर्दोष लोगों की हत्या हुई और असम इत्यादि में कई बम विस्फोट की घटनाएं हुईं, मर्यादा के मुताबिक यह सदन हमेशा दिवंगतों को श्रद्धासुमन अर्पित करता है। अध्यक्ष महोदय, यकीन नहीं आता कि छः फरवरी को किस तरीके से इस सदन के अन्दर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी व दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी आए और उन्होंने रजिस्टर में दस्तखत किए और चौधरी भजन लाल जी वापस चले गए। इससे जाहिर होता है कि या तो वे मात्र टी.ए.डी.ए. के बारे में सोचकर यहां आए और ओम प्रकाश चौटाला जी और उनकी पार्टी के सभी माननीय सदस्य जो कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के वक्त यहां मौजूद थे और जब उसके बाद अध्यक्ष महोदय आपने सदन को आधे घण्टे के बाद दोबारा से इकट्ठा होने की इजाजत दी क्योंकि शोक प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी। उस मौके पर हमारे विपक्ष के ये साथी यहां सदन में मौजूद नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, यह हम सबके लिए शर्म की बात है और हरियाणा प्रदेश की जनता ने भी इस बात का बहुत बुरा माना है कि चौटाला जी और उनकी पार्टी के सदस्यों को व भजन लाल जी को ऐसा क्या हो गया था कि एक तरफ चौधरी रणबीर सिंह जी जैसी बड़ी हस्ती जो संयुक्त पंजाब में मंत्री रहे, हरियाणा में भी मंत्री रहे, भाखड़ा जैसे महत्वपूर्ण डैम का जिनकी निगरानी में निर्माण हुआ, जिनके समय में गुड़गांव कैनाल बनी, जो संविधान सभा के सदस्य रहे। अध्यक्ष महोदय, वे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रहे और वे इस सदन के नेता चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के पिता भी थे। अध्यक्ष महोदय, यह हमारी सभ्यता है कि बुजुर्गों में और देश की सभ्यता में सबका सांझा अधिकार होता है। बुजुर्ग के प्रति हर किसी की इज्जत का सवाल होता है। श्री ओमप्रकाश चौटाला जी और इनकी पार्टी के सदस्यों ने एक दुर्भावना से बीमार मानसिकता का परिचय दिया है और इस तरह की दुर्भावना के कारण ये जान-बूझकर सदन में नहीं आये। उस दिन देश की महान विभूतियों को ये

[श्री कर्ण सिंह दलाल]
श्रद्धांजलि नहीं देना चाहते थे। अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने इन माननीय सदस्यों को चुनकर भेजा है उन लोगों का इन्होंने अपमान किया है। विधान सभा में ये सदस्य जिन क्षेत्रों से चुनकर आये हैं उन क्षेत्रों के लोगों को यह उम्मीद होती है कि उनके चुनायंदे देश की महान विभूतियों को उनके इलाके के लोगों की तरफ से सदन में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, श्री वी०पी० सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए तो श्री ओमप्रकाश चौटाला जी को सदन में आना चाहिए था क्योंकि जब वे देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने उनकी पार्टी के छः संसद सदस्यों को केन्द्र में मंत्री बनाया था। उन्होंने उस समय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को उप प्रधान मंत्री बनाया था और श्री ओमप्रकाश चौधरी जैसे इन्सान को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया था इसलिए उनको तो श्री वी०पी० सिंह जी के शोक प्रस्ताव में शामिल होना चाहिए था।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कम से कम शब्दों का इस्तेमाल तो ठीक रूप में करें। आखिर यह सदन है इसमें ठीक शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, डॉक्टर इन्दौरा जी, अब आप बैठ जाइये। बात तो हो गई है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के जो पिताश्री थे वे हरियाणा के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए एक बहुत बड़ी हस्ती थे जो हमें छोड़कर चले गये। उनके शोक प्रस्ताव पर इस सदन में चर्चा हुई। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो यह भी याद नहीं रखा कि जब स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का निधन हुआ तब अध्यक्ष महोदय, आप, मैं और हमारे मुख्यमंत्री जी इस सदन के सदस्य हुआ करते थे और चौटाला जी की सरकार हुआ करती थी। हमारी पार्टी के तमाम नेताओं और मुख्यमंत्री जी ने यहां खड़े होकर उनको श्रद्धांजलि दी थी। उनको अपना बुजुर्ग मानकर उनके अच्छे कामों को याद किया था और हर तरीके से हमने उनको श्रद्धासुमन अर्पित किये थे। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, अगर आपको याद हो तो कांग्रेस पार्टी ने चौटाला जी के कुशासन के खिलाफ चौधरी देवीलाल जी के निधन से पहले पानीपत में एक बहुत बड़ी ललकार रैली रखी हुई थी। जब चौधरी देवीलाल जी का निधन हुआ तब हमारे जो आज मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बड़प्पन दिखाते हुए उस ललकार रैली को पोस्टपौन कर दिया था और कहा था कि हमारे बुजुर्ग हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गये। उनको बुजुर्ग मानकर उन्होंने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किये थे। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी हमारे मुख्यमंत्री जी के खिलाफ रोहतक से चुनाव लड़ा करते थे, चुनाव जीतने के लिए सारे हथकण्डे अपनाया करते थे और हर तरीके का उत्पीड़न किया करते थे। इस अवसर पर हमारे विपक्ष के साथी अपनी छोटी मानसिकता को छिपा नहीं सके। अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब, खुद तो चले गये साथ में अपनी पार्टी के सदस्यों को भी डरा-धमकाकर अपने साथ ले गये। इनमें से किसी सदस्य की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि शोक प्रस्ताव में हिस्सा लें। अध्यक्ष महोदय, मैं 18 साल से इस सदन का विधायक बन कर आ रहा हूँ कई सरकारें मैंने देखी हैं लेकिन इस विधान सभा में इस प्रकार की घटना शायद इस सदन में पहले कभी नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, इस मामले को सही मायने में प्रिविलेज कमेटी

को दिया जाना चाहिए कि किस तरीके से दुर्भावना दिखाकर इन माननीय सदस्यों ने गैर जिम्मेदारी का परिचय दिया है और इस सदन की अवमानना की है। राजनीति में विधायक आते हैं और चले जाते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जिन्होंने इस देश की सेवा की, जिन्होंने इस देश के अन्दर इतने बड़े ओहदे प्राप्त करके लाखों करोड़ों लोगों का भला किया अगर उनके बारे में इस तरह की बात होती है तो ऐसे सदस्यों के खिलाफ अवमानना का एक मामला अलग से बनता है। ऐसे लोगों की तो सदस्यता तक समाप्त कर देनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इनको सामने बुलाकर एडमोनिश करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : *********

श्री अध्यक्ष : सीता राम जी, जो भी बोल रहे हैं वह रिकॉर्ड न किया जाए।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक बीमार मानसिकता का परिचय दिया है, अपाहिज मानसिकता का परिचय दिया है। अध्यक्ष महोदय, अगर सदन में आप इनके प्रति कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होगा क्योंकि हरियाणा के लोगों के मन में इनके रवैये के प्रति दुःख आया है और लोगों में इनकी साख गिरी है। लोगों ने देखा है कि सदन के अन्दर ऐसे लोग पहुँच गए हैं जो हमारे बुजुर्गों और हमारे पूर्वजों के प्रति इस तरीके का अशोभनीय व्यवहार कर रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप अशोभनीय या निंदनीय क्या कहना चाहते हैं?

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, यह एक निंदा प्रस्ताव है इसलिए इसको निंदा प्रस्ताव ही मानना चाहिए। अगर आप इजाजत दें तो इनके व्यवहार के बेसिज पर इनके खिलाफ प्रिवीलेज मोशन भी आना चाहिए और आपको इनके खिलाफ सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए और इनको एडमोनिश करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) इनको सिखाया जाए कि सदन में किस तरीके से मर्यादा का पालन करना चाहिए। इन लोगों को हरियाणा के बुजुर्गों के प्रति और देश के बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने चाहिएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामकुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय.....(शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय.....(शोर एवं व्यवधान)

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : डॉ० साहब, राम कुमार गौतम जी आपकी एलायंज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। बी०जे०पी० आपकी एलायंज पार्टी है इसलिए इनको बोलने दीजिए। आप किस तरह का धर्म निर्वहन कर रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सीता राम जी, राम कुमार गौतम जी ने पहले हाथ खड़ा किया था। (शोर एवं व्यवधान)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, दोनों ने इकट्ठे हाथ खड़ा किया था।

श्री अध्यक्ष : अगर आपने इकट्ठे जवाब देना है तो इकट्ठे बोल लो।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, इनको तो वाक आउट करना है और कुछ नहीं करना।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, अगर राजनीति करनी है तो इनकी सुनो और अगर रणबीर सिंह हुड्डा जी का सम्मान करना है तो हमारी भी बात सुनी जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, आप एक मिनट बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, किसी व्यक्ति का कद किसी के कहने से छोटा या बड़ा नहीं हो सकता।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, रणबीर सिंह हुड्डा जी सबके लिए सम्मानित थे, वे केवल कांग्रेस पार्टी के ही नेता नहीं थे इसलिए आप हमारी भी बात सुनें। हमारे बारे में जो ये रैजोल्यूशन लेकर आए हैं उसके बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, आप बैठें। यह कोई राजनीति की बात नहीं है। It is people democracy. यह सदन है और आप सब लोग इस सदन के ऑनरेबल मैम्बर्ज हैं। यहां हर मैम्बर को बोलने का बराबर अधिकार है। It is not the parental property of anybody. It is the property of the people, it is the property of the people of the State. आप बताओ कि दलाल साहब ने कहा कि यह अशोभनीय है या निंदनीय है। (शोर) इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है मेरी भी तो अपनी लिमिटेशंज हैं। अगर कोई मैम्बर बोलने के लिए हाथ खड़ा करता है तो सीरीज से ही मैं सबको बुलवाऊंगा।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कर्ण सिंह दलाल जी यहां एक प्रस्ताव लेकर आए हैं। (विघ्न) वह प्रस्ताव निंदा का है या********पर है इस******** की।

श्री अध्यक्ष : इसमें सरकार की क्या बात है। मैम्बर ने अपनी बात कही है। Where is the Government ? It is not the official resolution, it is non-official resolution by the private member.

डॉ० सुशील इन्दौरा : चलो किसी की भी मानसिकता है। वह माननीय सदस्य की अपनी मानसिकता है।

श्री फूल चन्द मुलाना : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इन्होंने जो ********कहा है यह शब्द कार्यवाही से निकलवा दिया जाए। (शोर एवं व्यवधान)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : ठीक है यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाए। एक आदमी ने अपने हिसाब से बात कही है ; न पार्टी जोड़ी है और न सरकार जोड़ा है। एज ए मैम्बर ऑफ दि हाउस उन्होंने अपनी बात उठाई है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : जो बात कही है वह*****और******का प्रतीक है। अध्यक्ष महोदय, यह क्यों है, यह इसलिए है कि पहले आपने खुद कहा है कि हाउस किसी की बापौती नहीं है। आपके शब्दों द्वारा देखा जाए तो यह हाउस जनता का हाउस है और यहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं।

श्री अध्यक्ष : ******ये शब्द रिकॉर्ड न किए जाएं।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि कोई यहां नहीं आ सकता तो ऐसी स्थिति में यहां पर कोई नहीं पूछता।

श्री अध्यक्ष : डॉ० इन्दौरा, ऑनरेबल मैम्बर ने केवल एक ही बात पूछी है कि Was it a wilful absence, or it was absence by per-chance ? आप यह बता दो यह हाउस इस बात को जानना चाहता है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर हम यहां चर्चा करें चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी की जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के पिता जी भी हैं, मैं बात खुलकर कहना चाहूँगा कि चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी का जो व्यक्तित्व था जिसे उन्होंने संवारा और सजाया वह उनकी खुद की देन थी। निःसंदेह वे एक महापुरुष थे, संविधान सभा के सदस्य भी थे, संयुक्त पंजाब के समय वे विधान सभा के सदस्य और मंत्री भी रहे, लोक सभा के सदस्य भी रहे। वे एक उच्च राजनेता होने के साथ-साथ एक चिन्तक और समाज सुधारक भी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि वे कांग्रेसी थे लेकिन कांग्रेस में रहते हुए भी वे सामाजिक चिन्तन में गहरी आस्था रखते थे। अगर मानसिकता की बात की जाये तो जब चौधरी रणबीर सिंह जी बीमार थे तो स्वयं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी उनका हाल चाल जानने के लिए गये थे जो कि सामाजिक सभ्यता की बात है। अगर आप दूसरी बात करें तो निधन के बाद जब चौधरी रणबीर सिंह जी का संस्कार हुआ उस वक्त भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी पहले पहुंच गये थे और सबसे आखिर तक वहां रहे। इसलिए यहां पर यह कैसे मान लिया गया कि वे हाउस से विलफुली अबसैंट थे। आज भी हमारे लिए चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी माननीय व्यक्तित्व हैं।

श्री अध्यक्ष : मिस्टर इन्दौरा, यह हाउस यह जानना चाहता है कि आपकी पार्टी के नौ के नौ मैम्बर गवर्नर एड्रैस के समय हाजिर थे उसके बाद भी मैम्बर्ज यहां पर हाउस में प्रेजैंट रहे हैं लेकिन after half an hour as and when the obituary references started members of the Indian National Lok Dal was not present in the house. यह हाउस यह

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[श्री अध्यक्ष]

बात जानना चाहता है। इसमें और कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं है। चाहे कोई किसी भी पार्टी का सदस्य रहा हो, चाहे कोई किसी का दुश्मन भी रहा हो अगर उसका स्वर्गवास हो जाता है तो हम सभी को उसकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। यह हमारी व्यवहार कुशलता का प्रतीक है और हमारा यह सामाजिक दायित्व भी बनता है। यहां ओबीचुअरी रैफ्रैंसिज़ के दौरान आप अपनी पार्टी के सदस्यों के उपस्थित न रहने का कारण बता दें।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, जो माननीय सदस्य ओछी मानसिकता की बात कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है। मैं यही बात कर रहा हूँ कि अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की मानसिकता ओछी होती तो वे संस्कार पर भी नहीं जाते। इसके साथ ही मैं सरकार और कांग्रेस पार्टी की मानसिकता की बात भी करना चाहता हूँ। ये जो शोक प्रस्ताव हैं उसके पहले महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण की शुरुआत की थी वह कहां से की थी, यह सभी को पता है, आप देख लीजिए। हमें भी खुशी है कि चौधरी रणबीर सिंह जी जो इस प्रदेश के बहुत ही बड़े समाज सुधारक थे उनका ज़िक्र किया गया लेकिन जो देश के राष्ट्रपति थे जो कि प्रथम व्यक्ति होते हैं डॉ० आर० वेंकटरमन उनके बारे में अभिभाषण में कहीं भी ज़िक्र नहीं किया गया। उनके बारे में भी दो शब्द राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहे जा सकते थे। देश का दूसरा आदमी होता है प्रधानमंत्री (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह एक व्यवस्था का प्रश्न है। गवर्नर एड्रैस के बारे में माननीय इन्दौरा जी जो कुछ भी कहना चाहें कह लें इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने एड्रैस में क्या कहा यहां यह चर्चा का विषय नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) इन्दौरा जी, आप एक मिनट हमारी बात सुनने का मादा तो रखिए हम तो आपकी बात सुनने के लिए चुप बैठे रहे हैं। हम जानते हैं कि अब आप जाने वाले हैं और जाने के बहाने ढूंढ रहे हैं लेकिन हम आपको जाने का मौका नहीं देंगे। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने हरियाणा के एक सच्चे सपूत को अपने एड्रैस में श्रद्धांजलि दी है तो इसमें क्या गलत है। पूरा सदन उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ओबीचुएरी रैजोल्यूशन लेकर आया था इसमें क्या गलत बात है। इन्दौरा जी केवल यह बताने के लिए खड़े हुए थे कि ये उस समय क्यों भाग कर चले गये थे। उस समय ये क्यों नहीं आये। इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। लोकदल के साथी उस समय हाउस में हाजिर रहकर सरकारी परम्पराओं का उल्लंघन करके यहां से भाग गये और जब एक माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया तो अब ये उस बात को घुमा रहे हैं जबकि इनको सीधा जवाब देना चाहिए कि ये अमुक कारण की वजह से नहीं आये। ये लोग इस बात का सही जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर ये इस बारे में अपना सही जवाब दे दें तो माननीय सदस्य की जिज्ञासा शांत हो जायेगी और वे अपना प्रस्ताव वापिस ले लेंगे।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, *********

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. डॉ० साहब, यहां एक बात यह आई है कि इनैल्ली members were not present in the House at the time of the obituary references. आप इस बारे में कारण बता दें कि आप सदन में किस कारण से नहीं आये उसके बाद तो बात ही खत्म हो जाएगी। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा के प्रति हमारे दिल में भी बहुत आदर है। हाउस में उपस्थित होना दूसरी बात है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि आप शोक प्रस्ताव के समय क्यों सदन में उपस्थित नहीं थे। आज आप चार लोग उपस्थित हो अगर उस दिन एक सदस्य भी होता तो यह प्रश्न ही नहीं उठता। उस दिन विलफुल ऑबिच्यूरी में एबसैंट थे (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि माननीय चौधरी रणबीर सिंह जी का जो चिन्तन था अगर माननीय सदस्य अपनी विचारधारा को उनके चिन्तन की दिशा में मोड़ दें तो समाज के उत्थान के काम आ सकता है। अगर इनको माननीय चौधरी रणबीर सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो उनके विचारों पर चिन्तन करें ना कि ये मानसिकता की बात करें। (शोर एवं व्यवधान) हम हर जगह उपस्थित थे ये केवल सदन की बात करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, इन्होंने यह पूछा है कि श्रद्धांजलि के समय आप उपस्थित क्यों नहीं थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामकुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी श्री कर्ण सिंह दलाल ने जो यह निन्दा प्रस्ताव सदन के सामने पेश किया है, यह बहुत सही प्रस्ताव है और इन लोगों की जितनी निन्दा की जाये उतनी कम है। असल में तो ये अपराधी लोग हैं और इनका इस तरह की सभाओं से कोई लेना-देना नहीं है। इस देश के इतने महान लोग चले गये, इस देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉ० आर० वेंकटरमन चले गये और पूर्व प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी चले गये लेकिन इन लोगों के पास शोक प्रस्ताव में शामिल होने का भी समय नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, अपराधी तो ये खुद हैं। जिन लोगों से चुनकर आये हैं अब वे इनको देख रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, ये किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान) डॉ० सीता राम जी, भारतीय जनता पार्टी आपकी एलायन्स पार्टी रही है, उसके सदस्य अपनी बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के आपके साथी आपकी कलई और पोल खोल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, अपराधी कैसे कह सकते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डॉ० सीता राम जी, आप अपनी सीट पर बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामकुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ी जलालत और क्या हो सकती है कि ये लोग टी०ए०, डी०ए० लेकर चले गये लेकिन श्रद्धांजलि में शामिल नहीं हुए। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। इनकी जितनी भी निन्दा की जाये कम है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० सीता राम : आप अपना तरीका सुधारो। आपको तो असैम्बली से बाहर कर देना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : It is not the way. (Interruption and noises)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, ये कैसे बोलते हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामफल चिड़ाना : अध्यक्ष महोदय, ये अपराधी कैसे कह सकते हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामकुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, यह बात तो सारी दुनिया जानती है। (विघ्न)

Mr. Speaker : Chirana Ji, please take your seat. I allow you to speak. (Noise and interruptions). Chirana Ji, please go to your seat. It is not the way. (Noises and Interruption).

श्री रामफल चिड़ाना : अध्यक्ष महोदय, ये तो सदन में बोलने के ही लायक नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मिस्टर चिड़ाना, मैं आपको अलाऊ कर रहा हूँ, आप अपनी सीट से बोलिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामकुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति हाउस में न आये तो कोई बात नहीं है। अगर ये आ भी गये थे तो दस्तखत करके जाना नहीं चाहिए था। उसके बाद इतने महान लोगों को श्रद्धांजलि देने का इतना महान कार्य चल रहा था। डॉ० बैंकेट रमन कितने बड़े नेता थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह को श्रद्धांजलि देनी थी उनकी शोक सभा चल रही थी। चौधरी रणबीर सिंह इतने बड़े फ्रीडम फाईटर थे उनके शोक प्रस्ताव बदस्तूर थे। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि इन लोगों की, जो यहां आकर चले गए हैं, निन्दा की जाए। इनके खिलाफ शोक प्रस्ताव में शामिल न होने पर निन्दा प्रस्ताव पास होना चाहिए और हाउस में आप ऐसा प्रस्ताव ला सकते हैं कि यहां पर आकर चले गए उनकी निन्दा की जाए। सभी ने यहां से चले जाना है, शोक प्रस्ताव में जो लोग हाजिर नहीं हुए और बेकायदगी की बात की है वे इसके लिए मुआफी मांगे। अगर उन्होंने शोक प्रस्तावों में हिस्सा नहीं लेना था तो उनको यहां पर आने की जरूरत ही नहीं थी वे अपने घर पर ही रहते। अगर यहां पर आकर इतने महान कार्य में हिस्सा नहीं लेना था तो यहां किस लिए आए, केवल कुछ पैसों के लिए यहां पर आए

थे। चौधरी कर्ण सिंह दलाल जी का जो प्रस्ताव है मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ कि इन लोगों की घोर निन्दा की जाए।

डॉ० सीता राम : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, *** *** *** ***

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, यह कोई प्वायंट ऑफ आर्डर नहीं है इसलिए आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न) Nothing is to be recorded. (Interruptions) आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न) समय बहुत ही कम है, काम ऐसे नहीं चलेगा। प्लीज आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न)

प्रो० छत्तरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी चौधरी कर्ण सिंह दलाल जी ने जो प्रस्ताव हाउस के सामने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है उसमें अगर किसी के यहां कोई भी शोक हो जाए या कोई व्यक्ति दुनिया से चला जाए, उसका निधन हो जाए तो सरबबाल में उसके सम्मान में उस बात को लेते हैं। आप जानते हैं कि जिनके बीच आपस में गोलियां चल रही हों, हत्या हुई हो या केसिज चल रहे हों और दुश्मन के घर में भी अगर कोई डैथ हो जाती है तो किसी भी स्टेज पर उसमें कोई व्यक्ति यह नहीं कहता है कि अच्छा हुआ है और उसके दोलड़े पर बैठता है। स्पीकर सर, हरियाणा विधान सभा यह हरियाणा की चुनी हुई पंचायत है इसमें यह परम्परा रही है कि दो सैशनों के बीच में जो आत्माएं हमें छोड़ कर चली जाती हैं उनके ऑबिच्यूरी रैफरैंस आते हैं। स्पीकर सर, कोई नया सदस्य किसी वजह से हाउस में न आ पाए या किसी गम्भीर तकलीफ में हो तो अलग बात है लेकिन ऑबिच्यूरी रैफरैंसिज में वर्तमान में सभी सीनियर लीडर्ज को हाउस में हाजिर रहना चाहिए ताकि वह अपनी श्रद्धांजलि दे सकें। स्पीकर सर, यह बात सही है कि सभी सदस्यों को इस अवसर पर बोलने का मौका नहीं मिल पाता है लेकिन ओपोजीशन के जो सीनियर साथी बैठे हैं कम-से-कम उनको अपनी बात कहने का समय होता है। स्पीकर सर, आप भी इस सभ्यता से परिचित हैं। सारा हाउस जानता है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे अफसोस पर या ऑबिच्यूरी रैफरैंस पर नहीं जाता है तो समाज उसकी निन्दा करता है, चर्चा करता है कि देखो फलाने को आज शर्म आनी चाहिए कि वह आज के दिन भी नहीं गया जबकि उसको जाना चाहिए था। ये सारी बातें अपने समाज में चर्चा का विषय रहती हैं। स्पीकर सर, इस बारे में भजन लाल जी के बारे में भी जिक्र हुआ कि दो सिगनेचर मार कर चले गए। स्पीकर सर, वे हाउस के अन्दर आकर आधा घंटा और बैठ जाते तो उनके प्रति शोभनीय बात ही कही जाती। देश के एक पूर्व राष्ट्रपति आज हमारे बीच में नहीं रहे उनके प्रति ऑबिच्यूरी थी, देश के प्रधान मंत्री जिन्होंने अपनी पार्टी में रहते हुए ही चुनौतीपूर्ण कार्य किया और फिर प्रधान मंत्री के ओहदे पर आए, वे एक रैवोल्यूशनरी व्यक्ति के रूप में थे उनके बारे में ऑबिच्यूरी आई थी। स्पीकर सर, इस देश का संविधान हमारे लिए धर्म ग्रंथ है और हम इसके अन्दर पूरी आस्था रखते हुए पूरे देश की पॉपुलेशन के विकास की बात सोचते हैं। उसके एकमात्र अलाईव सदस्य आज हमारे बीच में नहीं रहे और को-इन्सीडैंटली वे इस

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[प्रो० छत्तर पाल सिंह]
हाउस के नेता के पिताश्री थे। ये दोनों ही बातें उस दिन की महत्ता को बहुत बढ़ाते थे। इसके अलावा शहिदों, स्वतन्त्रता सेनानी और हमारे कुछ सदस्यों के रिलेटिवज़ जो हमारे बीच में नहीं रहे उनके नाम भी ऑबिच्यूरी में शामिल थे। यहां पर गवर्नर एड्रैस के बाद विशेष रूप से अपोजिशन के सभी सदस्य हाउस के अन्दर उपस्थित नहीं रहे। स्पीकर सर, ऑबिच्यूरी रैफरैंसिज के बाद हमारे अपोजिशन के कुछ सदस्य हाउस में दिखे। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी तरफ से ऑबिच्यूरी रैफरैंसिज के बारे में कोई रैसीव डिसिज़न लिया गया हो। एक मैसेज कहीं प्रिवेल हुआ, ऐसी सैल पूरे हाउस को आई। अपोजिशन का कोई भी सदस्य यहां पर नहीं था, सब के सब हाउस से बदारद थे।

श्री अध्यक्ष : गौतम साहब तो हाउस में थे।

प्रो० छत्तर पाल सिंह : स्पीकर सर, गौतम साहब तो उनसे इत्तफाक नहीं रखते हैं हालांकि इनकी पार्टी का इनैलो के साथ समझौता हुआ है। (विघ्न) डॉक्टर सुशील इन्दौरा जी, मैं सारी सयानी बातें कहूँगा, आप सुनें तो सही। (विघ्न) डॉक्टर साहब, कोई भी शब्द ऐसा नहीं आएगा जिस पर आप आपत्ति कर सको। लेकिन स्पीकर सर, ने जो इशारा किया है और आपकी पार्टी के नेतृत्व में और उनकी पार्टी के नेतृत्व में जो फैसला लिया है उसके बारे में आप अखबारों में पढ़ते हैं। राम कुमार गौतम जी यहां पर भी जो बोलते हैं वह भी आप सुनते और देखते हैं। इन्होंने अपनी पार्टी की विचारधारा का आपकी पार्टी की विचारधारा के साथ मेल नहीं है उसके बारे में कहा है। यह तो इनकी हिम्मत है कि इन्होंने पार्टी में रहते हुए, पार्टी के विधायक होने के बावजूद विचारधारा के आधार पर पार्टी के फैसले का विरोध किया है। आज जितनी भी पोलिटिक्स पार्टियां हैं, यदि उनकी इन्टरनल डैमोक्रेसी मजबूत हो जाए तो आप जितने साथी यहां पर बैठे हुए हैं और आपके साथी जब आपस में बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपकी आत्माएं भी मजबूत हो जाएंगी। आप कई बार उनकी बातें मानने को मजबूर हो जाते हैं। (विघ्न)

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि बात का बतंगड़ चाहे जितना भी बना लो, वह अलग बात है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। This is just a co-incidence. (विघ्न)

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded.

Dr. Sushil Indora : * * * *

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर साहब, इस बात पर कोई राजनीति करे यह ठीक नहीं है। मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई राजनीति नहीं है। इस बारे में हाउस की एक इन्टैंशन थी कि इतना बड़ा ईशू था। (विघ्न) चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी बोलना चाहते हैं। आप सभी एक मिनट बैठ जाएं। (विघ्न) डॉक्टर इन्दौरा जी, सभी लोग अपनी सीटों पर बैठ गए हैं आप भी बैठ जाएं। (विघ्न)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

डॉ० सुशील इन्दौरा : सर, इन्होंने तो चौधरी रणबीर सिंह को बहुत सस्ता बना दिया। वे तो बहुत महान नेता रहे हैं।

वित्त मंत्री (श्री बिरेन्द्र सिंह) : स्पीकर साहब, बड़ी सिम्पल बात है। कर्ण सिंह दलाल जी ने जो प्रस्ताव रखा है या कहिए कि उन्होंने जो बात कही है उस पर सीता राम जी जो कि इनेलो के डिप्टी लीडर हैं। (विघ्न) डॉ० इंदौरा हैं कोई बात नहीं वे भी बैठे हुए हैं ये इस बारे में दो शब्दों में बता दें कि इनका अबसैन्ट होना अन-इंटैशनल था या ये जानबूझकर अबसैन्ट हुए थे? इससे सारी बात खत्म हो जाएगी।

Dr. Sushil Indora : Sir, this was not intentional. It was co-incidental and it was not our intention.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, मेरी एक दरखास्त है। डॉक्टर साहब ने चौधरी बिरेन्द्र सिंह के खड़ा होने से पहले बड़ा स्पष्ट कह दिया कि 'It was co-incidental and it was not our intention.' इसलिए मैं माननीय सदस्य को कहूँगा कि in light of what Dr. Indora has said, I would request Shri Karan Singh Dalal to withdraw his resolution.

श्री अध्यक्ष : ठीक है, दलाल साहब, आप इस बारे में क्या चाहते हैं?

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब, माननीय चौधरी बिरेन्द्र सिंह जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है इन्दौरा साहब मात्र बहाना बनाकर अगर ऐसी बात कहें तो ठीक नहीं है लेकिन अगर इनकी इंटेशन सही है तो माननीय चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने जो बात कही है वह बहुत ही अच्छी बात है इसलिए मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करने के लिए निवेदन करता हूँ।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, मैंने पहले ही कह दिया है कि यह हमारी इंटेंशन नहीं थी, यह महज को-इंसीडैंटल था।

श्री अध्यक्ष : डॉक्टर इंदौरा, चूंकि वह बात हाउस को अशोभनीय लगी इसलिए हाउस के मैम्बर्ज और मैं खुद भी यह जानना चाहते थे कि यह इंटेशनली था या को-इंसीडैंटल था। जो व्यवहार किया गया वह अशोभनीय था। हाउस में इतना बड़ा इशु ओबिचुएरी रैफरैंस जोकि राष्ट्रीय नेताओं के बारे में था, आया था लेकिन चलो, अब यह मामला खत्म हो गया।

कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट में संशोधन

प्रो० छत्तर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी एक रिक्वैस्ट है कि हमारे माननीय चीफ मीनिस्टर साहब के पिताश्री रणबीर सिंह जी की कल दोपहर को रस्म पगड़ी है और सभी माननीय सदस्य वहां जाना चाहते हैं। मेरी गुजारिश है कि यदि कल हाउस की कार्यवाही

[प्रो० छत्तर पाल सिंह]
स्थगित कर दें तो सभी मैम्बर्ज वहां जा सकते हैं। यह सभी सदस्यों की भावना है कि कल हाउस की बैठक नहीं होनी चाहिए।

आवाजें : ठीक है जी।

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that there will be no sitting of this House on 11th February, 2009 and the business which was to be transacted on 11th February, 2009 will now be taken up in the first sitting of the House on Friday, the 13th February, 2009.

Voices : Yes, yes.

Mr. Speaker : There will be no sitting of this House on 11th February, 2009 and the business which was to be transacted on 11th February, 2009 will now be taken up in the first sitting of the House on Friday, the 13th February, 2009.

डॉ० सीता राम : स्पीकर सर, 12 तारीख को सैशन कितने बजे आरम्भ होगा?

श्री अध्यक्ष : 12 फरवरी, 2009 को सैशन 2.00 बजे (अपरान्ह) आरम्भ होगा।

Dr. Sushil Indora : Sir, We have no objection.

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हाउस की सहमति के अनुसार कल दिनांक 11.2.2009 को सदन की बैठक नहीं होगी। दिनांक 11.2.2009 का बिजनैस दिनांक 13.2.2009 को प्रथम बैठक में टेकअप कर लिया जाएगा। (विघ्न) अभी बी०ए०सी० की रिपोर्ट आ रही है उसमें यह अमैंडमैंट इन्कलूड कर लेंगे।

घोषणाएं

(क) अध्यक्ष द्वारा

(i) चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची

Mr. Speaker : Hon'ble Members, under Rule 13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following Members to serve on the panel of Chairpersons :—

1. Shri Karan Singh Dalal, M.L.A.
2. Shri Shadi Lal Batra, M.L.A.
3. I.G. Sher Singh, M.L.A.
4. Dr. Sushil Indora, M.L.A.

(ii) अनुपस्थिति के सम्बन्ध में सूचना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I am to inform you that I have received a letter dated 10th February, 2009 from Shri Naresh Yadav, MLA vide which he has

informed that due to road accident, he will not be able to attend the Session of Haryana Vidhan Sabha on 10th February, 2009.

(iii) अनुपस्थिति की अनुमति

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a letter dated 10th February, 2009 from Shri Yadvendra Singh, MLA which reads as under :—

"Dear Sir,

LEAVE OF ABSENCE

I shall not be able to attend the Vidhan Sabha Session on 10th, 12th and 13th of February, 2009, due to personal reasons.

I request you to kindly grant me leave of absence for the above dates.

Thanking you,"

Mr. Speaker : Is it the pleasure of the House that leave of absence be granted to Shri Yadvendra Singh, MLA to remain absent for 10th, 12th and 13th February, 2009 ?

Voices : Yes, yes.

Mr. Speaker : The leave is granted.

(ख) सचिव द्वारा

Mr. Speaker : Now, the Secretary will make an announcement.

सचिव : महोदय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने मार्च, 2008 तथा सितम्बर, 2008 में हुए सत्रों में पारित किए थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अपनी अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूँ।

MARCH SESSION, 2008

1. The Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill, 2008.
2. Guru Jambheshwar University of Science and Technology Hisar (Amendment) Bill, 2008.

SEPTEMBER SESSION, 2008

1. Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences Rohtak (Amendment) Bill, 2008.
2. The Indian Stamp (Haryana Amendment) Bill, 2008.
3. The Haryana Regulation of Property Dealers and Consultants Bill, 2008.

[सचिव]

4. The Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Second Amendment) Bill, 2008.

5. The Haryana Underground Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Bill, 2008.

6. The Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 2008.

7. The Haryana Municipality Public Disclosure Bill, 2008.

8. The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2008.

9. The Haryana Town Improvement Bill, 2008.

10. The Haryana Municipal Citizens' Participation Bill, 2008.

11. The Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill, 2008.

12. The Haryana Tax on Entry of Goods into Local Areas (Amendment) Bill, 2008.

कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now I report the time table of the various business fixed by the Business Advisory Committee.

The Committee met at 11.00 A.M. on Friday, the 6th February, 2009 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs, the Assembly whilst in Session, shall meet on Monday at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. and on Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday will meet at 9.30 A.M. and adjourn at 2.00 P.M. without question being put.

On Friday, the 6th February, 2009, the Assembly shall meet immediately half an hour after the conclusion of the Governor's Address and adjourn after the conclusion of Obituary References. On Tuesday, the 10th February, 2009, the Assembly shall meet at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. without question being put.

On Thursday, the 12th February, 2009, the Assembly shall meet at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. without qeustion being put. On Friday, the 13th February, 2009, the Assembly shall meet at 9.30 A.M. and adjourn at 1.30 P.M. without question being put and the Assembly shall meet again at 2.00 P.M. and adjourn at 6.30 P.M. without question being put. On Friday, the 20th February, 2009 the Assembly shall meet at 2.00 P.M. and adjourn after the conclusion of the Business entered in the List of Business.

The Committee, after some discussion, further recommends that the business on 6th, 10th to 13th, 16th to 18th and 20th February, 2009 be transacted by the

Sabha as under :—

The House will meet immediately half an hour after the conclusion of the Governor's Address on the 6th February, 2009.	1. Laying a copy of the Governor's Address on the Table of the House. 2. Obituary References.
Saturday, the 7th February, 2009	Holiday.
Sunday, the 8th February, 2009	Holiday.
Monday, the 9th February, 2009	Holiday.
Tuesday, the 10th February, 2009 (2.00 P.M.)	1. Questions Hour. 2. Presentation and adoption of First Report of Business Advisory Committee. 3. Papers to be laid/re-laid on the Table of the House. 4. Presentation of 4th Preliminary Report of the Committee of Privileges and extension of time for presentation of the final report thereon. 5. Presentation of Preliminary Report of the Committee of the House to inquire into the details of public properties transferred/auctioned/allotted during the years 1999-2000 to 2004-2005 and extension of time for presentation of the final Report. 6. Discussion on Governor's Address.
Wednesday, the 11th February, 2009 (9.30 A.M.)	Off Day.
Thursday, the 12th February, 2009 (2.00 P.M.)	1. Questions Hour. 2. Non-official Business.
Friday, the 13th February, 2009 (9.30 A.M.) (1st Sitting)	1. Questions Hour. 2. Motion under rule 121. 3. Resumption of discussion on Governor's Address and Voting on

[सचिव]

	Motion of Thanks.
	4. Presentation, Discussion and Voting on Supplementary Estimates (2nd Instalment) for the year 2008-2009 and Report of the Estimates Committee thereon.
	5. Resumption of Discussion on Special Report of the Committee of Privileges.
Friday, the 13th February, 2009 (2.00 P.M.) (2nd Sitting)	Presentation of Budget Estimates for the year 2009-2010.
Saturday, the 14th February, 2009	Holiday.
Sunday, the 15th February, 2009	Holidy.
Monday, the 16th February, 2009 (2.00 P.M.)	1. Questions Hour.
	2. Presentation of Reports of the Assembly Committees.
	3. Discussion on Budget Estimates for the year 2009-2010.
Tuesday, the 17th February, 2009 (9.30 A.M.)	1. Questions Hour.
	2. Resumption of discussion on Budget Estimates for the year 2009-2010.
Wednesday, the 18th February, 2009 (9.30 A.M.)	1. Questions Hour.
	2. Resumption of discussion on Budget Estimates for the year 2009-2010 and reply by the Finance Minister thereon.
	3. Discussion and Voting on Demands for Grants on Budget Estimates for the year 2009-2010.
Thursday, the 19th February, 2009	Holiday.
Friday, the 20th February, 2009 (2.00 P.M.)	1. Questions Hour.
	2. Motion under Rule 15 regarding Non-stop sitting.

3. Motion under Rule 16 regarding adjournment of the Sabha sine-die.
4. Papers to be laid, if any.
5. Presentation of Reports of the Assembly Committees.
6. The Haryana Appropriation Bill in respect of Supplementary Estimates (2nd Instalment) for the year 2008-09.
7. The Haryana Appropriation Bill in respect of Budget Estimates for the year 2009-2010.
8. Legislative Business.
9. Any other Business.

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion that this House agrees with the recommendations contained in the first Report of the Business Advisory Committee.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That this House agrees with the recommendations contained in the first Report of the Business Advisory Committee with the modification that the sitting fixed for 11th February, 2009 will be off day and the business fixed for 11th February, 2009 will be taken up on first sitting of the 13th February, 2009.

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House agrees with the recommendations contained in the first Report of the Business Advisory Committee with the modification that the sitting fixed for 11th February, 2009 will be off day and the business fixed for 11th February, 2009 will be taken up on first sitting of the 13th February, 2009.

Mr. Speaker : Question is—

That this House agrees with the recommendations contained in the first Report of the Business Advisory Committee with the modification that the sitting fixed for 11th February, 2009 will be off day and the business fixed for 11th February, 2009 will be taken up on first sitting of the 13th February, 2009.

The motion, as amended, was carred.

सदन के कार्यक्रम में परिवर्तन

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, I have one more suggestion through you to the House that as per the business listed in the List of Business, there will be very less time left for discussion on Governor's Address so, on 12th February, 2009, the non official day may be converted into an official day so that large number of Members who want to speak on Governor's Address they can express their opinion. This is only a suggestion subject to if the House feels.

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, इस पर मेरा एतराज है क्योंकि गैर सरकारी कामकाज के दिन ही सदस्य अपनी बात कह सकते हैं और एक ही दिन होता है।

श्री अध्यक्ष : क्या आप गवर्नर एड्रैस पर नहीं बोलना चाहते हैं?

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर एड्रैस पर भी बोलूंगा इसलिए आप सैशन का समय और बढ़ा लीजिए इसमें क्या दिक्कत है सरकार के पास बहुत समय है 20 की बजाए सैशन को और बढ़ा लीजिए।

श्री अध्यक्ष : सरकार के पास या मैम्बर्ज के पास आप सरकार और पार्टी की बात बहुत करते हैं और हाउस की बात कम करते हैं।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि सैशन का समय घटाना और बढ़ाना सरकार की कैन्सैंट से होता है इसलिए मैं यह कहता हूँ कि सरकार के पास फालतू टाईम है काम तो कुछ है नहीं सैशन का समय और बढ़ा लिया जाए।

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, श्री ओम प्रकाश चौटाला जी बी०ए०सी० के सदस्य हैं वे न तो कभी बी०ए०सी० की मीटिंग में आते हैं और न ही कभी अपना कोई सुझाव रखते हैं। वे डॉक्टर इन्दौरा को अपनी जगह क्यों नहीं नोमिनेट कर देते।

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि हम जैसे सदस्यों को बहुत कम ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर कोई बिल लेकर आना है, कोई रेजोल्यूशन लाना है और हरियाणा प्रदेश के हित में कई अनेकों ऐसी बातें हैं जिस दिन कोई अपनी बात कहना चाहते हैं। एक ही तो दिन होता है वह दिन भी अगर सरकार खा जाए तो बताओ बचेगा क्या।

श्री अध्यक्ष : चलो अब तो हाउस पर इस बात को छोड़ दिया यह तो हाउस का काम है हाउस जैसा कहेगा वैसे कर लेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं इन्दौरा साहब की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि चौटाला साहब की सरकार के समय पांच सालों में आफिशियल डे को नॉन ऑफिशियल डे में कभी कंवर्ट नहीं कराया गया इनकी सरकार ने सारा समय ऐसे ही निकाल दिया। ये सारे समय को ही खाते रहे।

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, आपका सुझाव आ गया है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आप इतनी उदारता दिखा रहे हैं सभी सदस्यों को बोलने का समय भी दे रहे हैं। 12 तारीख को जो गैर सरकारी कामकाज का दिन है अगर आप ठीक समझें तो उसमें ज्यादा रेजोल्यूशन नहीं हैं आधा घण्टा या पौना घण्टा जो हमारे गैर सरकारी संकल्प हैं उनके ऊपर चर्चा हो जाए और उसके फौरन बाद आप सरकारी काम काज कर लें। सर, अगर इसको आप अडोप्ट कर लें तो अच्छा होगा।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव तो यह है कि नॉन ऑफिशियल डे को ऑफिशियल डे में कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि गवर्नर एड्रैस पर ज्यादा मैम्बर्ज को बोलने के लिए समय मिल जाए।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप अपने नॉन ऑफिशियल रैजोल्यूशन के बारे में गवर्नर एड्रैस पर डिस्कशन के समय ही बोल लेना। You can speak on Governor's Address.

श्री कर्ण सिंह दलाल : ठीक है जी।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, with the sense of the House and keeping in view the feelings expressed by the Members in the House that instead of transacting non-official business on the non-official day i.e. 12th February, 2009, official business will be transacted and the Governor's Address will be discussed so that more members could speak on motion of thanks on the Governor's Address.

सदन की मेज पर रखे जाने वाले / पुनः रखे जाने वाले कागज पत्र

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will lay / re-lay papers on the Table of the House.

Power Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to lay on the Table of the House—

The Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Ordinance, 2009 (Haryana Ordinance No. 1 of 2009).

The Haryana Fire Service Ordinance, 2009 (Haryana Ordinance No. 2 of 2009).

The General Administration Department Notification No. S.O. 31/H.A. 3/1975/S.8/2008, dated the 16th April, 2008 regarding amendment in Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Allowances Rules, 1997, as required under section 8(2) of the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances Act, 1975.

The General Administration Department Notification No. S.O. 32/H.A. 3/1970/S. 8 and 9/2008, dated the 16th April, 2008

[Shri Randeep Singh Surjewala]

regarding amendment in Haryana Ministers Allowances Rules, 1972, as required under section 9(2) of the Haryana Salaries and Allowances of Ministers Act, 1970.

The General Administration Department Notification No. S.O. 46/H.A.9/1979/S. 8/2008, dated the 27th May, 2008 regarding amendment in Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Rules, 1979, as required under section 8(3) of the Haryana Legislative Assembly (Facilities to Members) Act, 1979.

The Personnel Department Notification No. G.S.R. 5/Const./Art. 320/2008, dated the 6th February, 2008 regarding amendment in Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1973, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The Personnel Department Notification No. G.S.R. 27/Const./Art. 318/2008, dated the 7th August, 2008 regarding amendment in Haryana Public Service Commission (Conditions of Service) Regulations, 1972, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The Personnel Department Notification No. G.S.R. 30/Const./Art. 320/2008, dated the 18th August, 2008 regarding amendment in Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1973, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

Sir, I also beg to lay on the Table of the House—

The Personnel Department Notification No. G.S.R. 31/Const./Art. 320/2008, dated the 21st October, 2008 regarding amendment in Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1973, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 79/H.A.-6/2003/S.60/2003, dated the 22nd May, 2003 regarding the Haryana General Sales Tax Rules, 1975, as required under section 60(4) of the Haryana Value Added Tax Act, 2003.

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O. 113/H.A.-6/2003/S.60/2003, dated the 21st November, 2008 regarding amendment in the Haryana Value Added Tax (Second Amendment) Rules, 2008, as required under section 60(4) of the Haryana Value Added Tax Act, 2003.

The Excise and Taxation Department Notification No. S.O.

115/H.A.-6/2003/S.60/2008, dated the 27th November, 2008 regarding amendment in the Haryana Value Added Tax (Third Amendment) Rules, 2008, as required under section 60(4) of the Haryana Value Added Tax Act, 2003.

The Revenue and Disaster Management Department Notification No. S.O. 2/H.A.-38/2008/S.18/2009, dated the 6th January, 2009 regarding the Haryana Regulation of Property Dealers and Consultants Rules, 2009, as required under section 18(3) of the Haryana Regulation of Property Dealers and Consultants Act, 2008.

The Annual Accounts of the Haryana Khadi and Gramodyog Board for the year 2003-2004, as required under section 19(3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The Annual Accounts of the Haryana Khadi and Gramodyog Board for the year 2004-2005, as required under section 19(3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The 8th Annual Report of Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam Limited for the year 2006-2007, as required under section 619-A (3)(b) of the Companies Act, 1956.

The Annual Report for the year 2007-2008 (1.4.2007 to 31.3.2008) of Lokayukta, Haryana, as required under section 17 (4) of the Haryana Lokayukta Act, 2002.

The Audit Report on the Accounts of Haryana Financial Corporation for the year ended 31st March, 2008, as required under section 37 (7) of the State Financial Corporations Act, 1951.

The Revised Explanatory Memorandum pertaining to FRIs as to the action taken on the Interim Report of Third State Finance Commission Haryana, as required under Article 243-I(4) and 243-Y(2) of the Constitution of India.

The Finance Accounts of the Government of Haryana for the year 2007-2008 in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Appropriation Accounts of the Government of Haryana for the year 2007-2008 in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

[Shri Randeep Singh Surjewala]

The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 2008 (Civil) of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 2008 (Revenue Receipts) of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

The Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended 31st March, 2008 (Commercial) of the Government of Haryana in pursuance of the provisions of Clause (2) of Article 151 of the Constitution of India.

विशेषाधिकार मामलों के संबंध में विशेषाधिकार समिति का प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Now, Shri Karan Singh Dalal, M.L.A., Chairperson, Committee of Priviieges, will present the Fourth Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Randeep Singh Surjewala, Parliamentary Affairs Minister, Haryana against Shri Om Parkash Chautala, MLA in respect of misconduct, misbehaviour and disorderly disrupting the proceedings of the House, unbecoming of a Member of the House, thereby committing the contempt of the House/breach of privilege on 20.3.2007 and on earlier occasions also and will also move that the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Shri Karan Singh Dalal (Chairperson, Committee of Privileges) : Sir, I beg to present the Fourth Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Randeep Singh Surjewala, Parliamentary Affairs Minister, Haryana against Shri Om Parkash Chautala, MLA in respect of misconduct, misbehaviour and disorderly disrupting the proceedings of the House, unbecoming of a Member of the House, thereby committing the contempt of the House/breach of privilege on 20.3.2007 and on earlier occasions also.

Sir, I beg to move—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

वर्ष 1999-2000 से 2004-2005 तक की अवधि के दौरान सार्वजनिक सम्पत्तियों के हस्तांतरण/नीलामी/आबंटन की विस्तृत जांच करने के लिए हरियाणा विधान सभा की समिति का प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Hon'ble Members now, Shri Phool Chand Mullana, Chairperson, Committee of the Haryana Vidhan Sabha to inquire into the details of public properties transferred/auctioned/allotted during the years 1999-2000 to 2004-2005 will present the Second Preliminary Report of the Committee and will also move that the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Shri Phool Chand Mullana (Chairperson, Committee of the Haryana Vidhan Sabha, to inquire into the details of public properties transferred/auctioned/allotted during the years 1999-2000 to 2004-2005) : Sir, I beg to present the Second Preliminary Report of the Committee of the Haryana Vidhan Sabha to inquire into the details of public properties transferred/auctioned/allotted during the years 1999-2000 to 2004-2005.

Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Question is—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा

Mr. Speaker : Hon'ble Members now, discussion on the Governor's Address will take place. Shri Venod Kumar Sharma, M.L.A. will move his motion.

Shri Venod Kumar Sharma (Ambala City) : Sir, I beg to move—

> "That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 6th February, 2009 at 2.00 P.M."

स्पीकर सर, मेरे दोस्त इन्दौरा जी जब इस बात को मान रहे थे और इस बात का जिक्र कर रहे थे कि इनएडवरटेंटली या बाई को-इंसीडैंस ओबीच्यूरी रैफरैंसिज़ के दौरान वह और उनकी पार्टी के दूसरे सदस्यगण शामिल नहीं हो सके तो मुझे उम्मीद थी कि शायद वे इसके लिए हाउस से क्षमा मांगेंगे। हाउस में इस बात का बड़ा भारी शोक था क्योंकि इनके गैरहाज़िर होने की वजह से हमारी परम्परा पर एक बड़ा आघात लगा था। फिर भी मैं इन्दौरा जी की इस बात को मानता हूँ कि भले ही उन्होंने क्षमायाचना की बात नहीं कही लेकिन अपनी गलती को जरूर माना है और उसको देखते हुए श्री करण सिंह दलाल जी ने अपना रैजोल्यूशन वापिस ले लिया है। इसके साथ ही इन्दौरा जी ने जो बात कही है कि चौधरी रणबीर सिंह जी की जीवनी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए मैं उनके इस विचार से भी सहमत हूँ क्योंकि चौधरी रणबीर सिंह ही ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने परिवार की रिवायतों का अनुसरण करते हुए इस देश की आजादी के लिए अपने आपको महज़ 22 वर्ष की उम्र में ही देश के प्रति समर्पित कर दिया था। देश की आजादी के लिए उन्होंने हिन्दुस्तान की 7 जेलों में साढ़े तीन साल तक लगातार सजा काटी और नज़रबंद रहे। वे कांस्टीचुएंट असैम्बली के आखिरी जीवित मैम्बर होने के साथ-साथ पंजाब विधान सभा, हरियाणा विधान सभा, लोकसभा और राज्य सभा के सदस्य भी रहे। चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा महज़ मुख्यमंत्री के पिताश्री ही नहीं थे बल्कि नौजवानों और देश के करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा-स्त्रोत भी थे। मैं खुद उनकी जीवनी पढ़ रहा था। यह बात आज हम सभी लोग मानते हैं कि राजनीति में कुछ उसूल होने चाहिएं अर्थात् राजनीति उसूलों के ऊपर करनी चाहिए। हमें इस बात की खुशी है कि चौधरी रणबीर सिंह जी ने उन उसूलों को समक्ष रखते हुए अपना सम्पूर्ण राजनीतिक जीवन व्यतीत किया। इसके साथ ही 65 साल की उम्र में उन्होंने यह फैसला ले लिया कि अब वे राजनीति से सन्यास लेंगे। मैं समझता हूँ कि आज के राजनीतिक व्यक्तियों को उनसे ज्यादा से ज्यादा शिक्षा लेनी चाहिए। राजनीति में अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर देश, समाज और जनसाधारण की सेवा किस तरह से की जाती है यह शिक्षा हमें उनसे लेनी चाहिए और उनका अनुसरण करना चाहिए। इसके साथ ही मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री को मैं सदन के जरिये कांग्रेच्यूलेट करना चाहूँगा कि उन्होंने अमेरिका और दूसरे देशों के साथ जो न्यूक्लियर समझौता किया है उसकी वजह से देश में प्रगति और उन्नति का एक बहुत बड़ा समुन्द्र हमें देखने को

16.00 बजे

मिलेगा। इसके साथ ही मैं अपनी सरकार द्वारा पिछले चार साल में किये गये कार्यों के बारे में भी बताना चाहूँगा। वर्ष 2004-05 में हरियाणा प्रदेश का जो प्लान साईज था वह 2236 करोड़ रुपये था और आज 2009-10 में हरियाणा प्रदेश का जो प्लान साईज है वह 10 हजार करोड़ रुपये का है जो पिछली सरकार से लगभग 5 गुना ज्यादा है। जो प्रोग्रैस, जो उन्नति हरियाणा प्रदेश में पिछले 4 वर्ष में हुई है उसको हम प्लान साईज से नहीं आंक सकते। हरियाणा प्रदेश की जो उन्नति पिछले 4 वर्षों में हुई है वह इस प्लान साईज से कई गुणा ज्यादा है। जब वर्ष 2004-05 में 2236 करोड़ रुपये का प्लान साईज था उस समय और उससे पहले भी तो हरियाणा में कहीं सड़कों का काम, नहरों का काम, स्वास्थ्य का काम, शिक्षा का काम देखने को नहीं मिलता था। यह बात समझ में नहीं आती कि 2236 करोड़ रुपये में वर्ष 2004 में कितना पैसा सरकार ने लोगों की भलाई के लिए लगाया और इसमें से कितना पैसा अपनी भलाई के लिए लगाया। इस बारे में आँकड़े प्राप्त नहीं हुए लेकिन इस बात की गवाही लोगों की तरफ से मिलती है। जितना पैसा अब हरियाणा में लगाया गया है और आने वाले वर्ष में लगेगा, पिछले 40 वर्षों में भी इतना पैसा नहीं लगा होगा और इतनी उन्नति हरियाणा में नहीं हुई होगी। कुछ आँकड़े और कुछ तथ्य अवश्य मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इससे पहले मैं यह जरूर कहना चाहूँगा कि पिछली सरकार में नीयत और नीति में अन्तर था। न तो लोगों की सेवा की सरकार की नीयत थी और न ही ऐसी नीति निर्धारित की गई जिससे लोगों को फायदा हो। पिछली सरकार ने अपने स्वार्थों के लिए जो कार्य किये हैं उनको हरियाणा की जनता आज तक भूली नहीं है। लोग आज भी त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। हमारी सरकार ने जो वायदे किये वे पूरे किये और जो वायदे नहीं किये थे वे भी पूरे किये। हमारी सरकार लोगों की कसौटी पर खरी उतरी है। जिन वायदों के साथ हमारी सरकार ने प्रदेश के शासन की बागडोर सम्भाली थी पिछले 4 वर्षों में न केवल उन्हें हकीकत में बदला है बल्कि जन-कल्याण एवं विकास के कार्य किये हैं। किसानों की भलाई के लिए भी ऐतिहासिक फैसले लिये हैं। वह सरकार जो किसानों के हित की सरकार कहलाती थी उस सरकार के बारे में अगर ज्यादा कुछ न कहा जाये तो ही अच्छा है क्योंकि पिछली सरकार ने न तो किसानों को किसानों की पैदावार के असली मूल्य दिये और न ही किसानों के लिए कोई अच्छे कार्य किये। न किसानों को बिजली दी और न ही किसानों को पानी दिया। हमारी सरकार ने सबसे पहले किसानों के 1600 करोड़ रुपये के बिजली के कर्जे माफ किये। स्पीकर सर, यह वायदा हमने लोगों के साथ नहीं किया था। यह कोई चुनाव के लिए किया हुआ कार्य नहीं था क्योंकि चुनाव तो अभी बहुत दूर थे। यह कार्य लोगों की उन मुश्किलों को देखते हुए किया गया जिन मुश्किलों में पिछली सरकार ने उनको डाल दिया था। यह कह कर कि आप बिजली के बिल मत भरना हम बिजली के बिल नहीं चाहते। जब उन लोगों ने बिजली के बिल नहीं दिये तो उनके ऊपर गोलियाँ चलवाई गईं। हमारी सरकार ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया कि जो लोग बिजली के बिल नहीं भर सकते हैं उनको इन बिलों से माफी दी जाये। स्पीकर सर, यह एक ऐतिहासिक फैसला था जो हमारी सरकार ने सबसे पहले लिया। हमारी सरकार ने किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए केन्द्र सरकार के साथ बातचीत की। केन्द्र सरकार ने पिछले चार साल में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 450 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाए हैं जबकि एन०डी०ए० की

[श्री विनोद कुमार शर्मा]

पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल में केवलमात्र 40 रुपये की बढ़ोत्तरी की थी। वह सरकार जो अपने आपको किसानों की हितैषी सरकार कहती थी उसने किसान के लिए पिछले पांच साल में 40 रुपये बढ़ाए जबकि हमारी सरकार ने और पांच साल में 450 रुपये बढ़ाए। इन दोनों का आपस में मिलान करके देखें कि कौन सी सरकार किसानों के हित की सरकार है। कौन सी सरकार किसानों की हितैषी सरकार है और कौन सी सरकार किसानों के हित को समझती है इसमें कुछ कहने की जरूरत महसूस नहीं होती। अध्यक्ष महोदय, हमारे अनुरोध पर यू०पी०ए० सरकार ने हमारी सरकार ने चावल की 1121 पूसा धान की किस्म के निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध को हटवाया तथा उसको बासमती का दर्जा दिलवाया। हमारे जिन किसानों ने यह फसल बोई थी उनको इस वजह से बहुत लाभ हुआ और वे जिन्स को पर्याप्त मात्रा में बाहर भेजने में सफल हुए। स्पीकर सर, गन्ने का सर्वाधिक भाव किसान को दिया गया। हरियाणा सरकार ने गन्ना उत्पादकों को सर्वाधिक भाव दिया है। पिछले चार वर्षों में हमारी सरकार ने गन्ने की विभिन्न किस्मों के लिए 170, 165 और 160 रुपये का भाव दिया है जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। पिछले चार वर्षों से पहले हरियाणा में जो सरकार थी उस सरकार ने अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में मात्र 10 या 12 रुपये की बढ़ोतरी गन्ने के मूल्यों में की थी जबकि इस सरकार ने हर साल गन्ने के भाव में लगातार बढ़ोतरी की है। 56 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी पिछले चार साल में की गई है। मैं समझता हूँ कि किसान के लिए जो गन्ने के भाव दिये गये हैं उससे हमारे हरियाणा के किसान बहुत खुश हैं। किसानों की सबसे बड़ी समस्या यह भी थी कि बहुत से डिपार्टमैंट्स बहुत से कार्यों के लिए जमीन का अधिग्रहण करते थे लेकिन किसानों को उनकी भूमि का पर्याप्त मूल्य नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने इसको मद्देनजर रखते हुए दो बार फलोर रेट संशोधित किए हैं। अब स्थान विशेष के आधार पर ये दरें 20 लाख, 16 लाख और 8 लाख रुपये प्रति एकड़ निर्धारित की गई हैं और मुआविजा में दूसरे लाभ मिलने से यह राशि बढ़ कर 26 लाख रुपये, 20.80 लाख रुपये, 10 लाख 40 हजार रुपये हो जाती है। इसके साथ ही साथ सरकार ने नया सिस्टम बनाया है जिसके जरिये किसानों की नियमित आय सुनिश्चित करने के लिए 33 वर्ष तक के लिए 15,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति एकड़ रॉयल्टी और इसमें हर वर्ष 500 रुपये की बढ़ोत्तरी करने का निर्णय किया है। स्पीकर सर, इसमें एक बहुत ही जरूरी पक्ष है। हमारे किसान भाइयों को जब मुआवजा मिलता था तो वे उस पैसे को परिवार में कहीं न कहीं लगा देते थे। वह पैसा परिवार में खर्च होने के बाद उन किसान भाइयों की परिवार की तरफ उतनी अहमियत नहीं रहती थी क्योंकि न तो उनके हाथ में जमीन थी और न ही उनके हाथ में पैसा था। इसी बात को देखते हुए सरकार ने एक नया फैसला किया कि आने वाले 33 साल के लिए उसी भूमि के ऊपर उनको जो पैसा मिला है उस पैसे के बावजूद उसके अलावा उनको 15 हजार रुपये प्रतिवर्ष प्रति एकड़ उनको दिया जाएगा ताकि वह किसान अपनी जमीन जाने के बाद किसी के ऊपर निर्भर न रहे। किसान को अपनी जमीन से बड़ा प्रेम होता है और अपनी जमीन जाने के बाद वह किसी पर आश्रित न रहे इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया है। हमारी सरकार ने पहली बार नहर के पानी का समान बंटवारा किया है। स्पीकर सर, पिछले वर्षों में देखा गया कि हरियाणा प्रदेश

के कुछ ऐसे इलाके हैं जिन में पानी की भरमार थी उन इलाकों में जरूरत से ज्यादा पानी जाया करता था और कुछ ऐसे इलाके थे जहां पर शायद देखने को भी पानी नहीं मिलता था। कृषि योग्य भूमि में जब हमें सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होती थी तो किसान आसमान की तरफ देखते थे। बारिश के ऊपर निर्भर करते थे क्योंकि राज्य में नहरों का जाल नहीं था। यहां पर मुझे इस बात को कहने में बड़ा गर्व महसूस होता है कि पंजाब और हरियाणा की सिंचाई स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू की सोच और स्वर्गीय रणबीर सिंह हुड्डा जी के प्रयासों से सम्भव हुई है। भाखड़ा डैम जब बना उसके बाद हरियाणा और पंजाब में नहरों का जाल बिछा और सिंचाई की वजह से बंजर जमीनें उपजाऊ जमीनें बनीं। उसकी वजह से हमारे इलाके में खुशहाली आई। लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोगों के स्वार्थ की वजह से कुछ लोगों के लालच की वजह से इन इलाकों में कभी पानी की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। हमारी सरकार ने पहली बार नहरी पानी के समान बंटवारे के लिए भाखड़ा मेन लाईन हांसी-बुटाना नहर का निर्माण कार्य पूरा किया है। इस नहर से अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, हिसार जिले के हांसी मण्डल, भिवानी, महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, मेवात, फरीदाबाद, झज्जर, रोहतक, सोनीपत और पानीपत के किसानों को लाभ होगा। अध्यक्ष महोदय, लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत से अम्बाला सिंचाई परियोजना तैयार की गई है और केन्द्रीय जल आयोग की स्वीकृति के लिए भेजी गई है। इस परियोजना से वर्षा ऋतु में यमुना नदी के अतिरिक्त पानी के उपयोग से यमुनानगर, अम्बाला और पंचकूला जिले की 1 लाख 35 हजार 628 हैक्टेयर जमीन की सिंचाई हो सकेगी और भू-जल स्तर में भी सुधार होगा। स्पीकर साहब, बहुत से प्रश्न यहां पर उठाए जाते हैं और बहुत सी राजनैतिक पार्टियां अपने-अपने नेताओं के द्वारा एस०वाई०एल० कैनाल के बारे में बहुत चर्चा करती हैं। एस०वाई०एल० कैनाल का फैसला कांग्रेस की सरकार ने किया था। 1982 में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इसके निर्माण कार्य का उद्घाटन किया था। एस०वाई०एल० कैनाल काफी हद तक पंजाब में बनाई भी जा चुकी थी। अध्यक्ष महोदय, 15 जनवरी, 2002 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एस०वाई०एल० के माध्यम से हरियाणा के पक्ष में फैसला भी दिया। इस फैसले में निर्देश भी दिए कि अगर पंजाब सरकार निर्धारित समय में नहर का निर्माण करने में असफल रहती है तो केन्द्र सरकार अपनी किसी एजैंसी से यथा सम्भव शीघ्रता से इसका कार्य पूरा करवाए। उस वक्त केन्द्र में एन०डी०ए० की, पंजाब में अकालियों की और हरियाणा में आई०एन०एल०डी० की सरकारें थीं। आई०एन०एल०डी० और अकालियों में आपस में जो सांझ है, आपस का जो भाईचारा है उसको हम भूले नहीं हैं। लेकिन इनके आपस के भाईचारे और आपस की सांझ की वजह से जो नुकसान हरियाणा को हुआ है शायद उसकी भरपाई कभी न हो सके। इसकी जवाबदेही उस वक्त की आई०एन०एल०डी० की सरकार को और आज उनकी पार्टी के यहां बैठे हुए मेरे दोस्तों को देनी पड़ेगी। अगर उस वक्त एस०वाई०एल० कैनाल ये बना देते तो आज हरियाणा के लाखों करोड़ों लोगों को फायदा होता। सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए उनके साथ दोस्ती रखने के लिए हरियाणा में एस०वाई०एल० के पानी को नहीं आने दिया गया। (विघ्न)

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। अभी शर्मा जी ने कहा कि उस वक्त सैन्टर में एन०डी०ए० की सरकार थी, हरियाणा में आई०एन०एल०डी० की

[डॉ० सुशील इन्दौरा]
सरकार थी और पंजाब में अकाली दल की सरकार थी। अगर उस वक्त एस०वाई०एल० नहर बना देते तो आज हरियाणा की जनता को बहुत फायदा होता। चलो मैं मानता हूँ कि उस वक्त नहीं बना पाए लेकिन आज केन्द्र में कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार है। लेकिन मैं इनसे यह पूछना चाहता हूँ कि आज ये कब तक एस०वाई०एल० नहर को बनवा देंगे। इस बारे में ये सीधा जवाब दे दें। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, आपको पता है कि यह सारा मामला सब-ज्यूडिस है। (विघ्न) आप फिर भी यहां पर इस तरह से बात कर रहे हो। आप तो इस तरह से बात कर रहे हो जैसे कि आपको कुछ भी पता नहीं है। (विघ्न) You know the whole position. (विघ्न)

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ एक बात कहता हूँ कि नहर निर्माण के मामले में कोई सब-ज्यूडिस बात नहीं है।

श्री विनोद कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं इन्दौरा जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये इतने यूनानिमस हैं, इतने लार्ज हार्टिड हैं कि ये अपनी गलती मानते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा जी, आप ऐसा कह सकते हैं। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजिज़ को राष्ट्रपति जी ने रैफरैंस किया हुआ है। यह सारा मामला फुल बैंच के पास है। (विघ्न)

डॉ० सुशील इन्दौरा : यह नहर निर्माण के मामले में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, ऐसा है कि इसके टैंडर हो चुके थे और यह नहर बॉर्डर तक बनानी थी। उसके बाद ही यह सारा रैफरैन्स आया है। डॉक्टर साहब, आपको सारा पता है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, इस नहर के निर्माण के मामले में कोई भी मामला कोर्ट में पैंडिंग नहीं है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : इन्दौरा साहब, आप अभी बैठें। (विघ्न)

डॉ० सुशील इन्दौरा : ******

Mr. Speaker : Nothing to be recorded.

श्री विनोद कुमार शर्मा : स्पीकर साहब, डॉ० साहब की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये अपनी बात को मान लेते हैं, अपनी गलती को युनानीमसली मान लेते हैं। यह बहुत अच्छी बात है। (विघ्न) डॉ० साहब, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ कि आपने कहा कि चलो, हम नहीं बना पाए और आप कब तक यह बना देंगे। यही इनका प्रश्न है। इनके प्रश्न का सिर्फ एक ही जवाब है कि इसको बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम इसको बनाएंगे।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

वक्त की बात नहीं है लेकिन ये मान गए हैं कि ये इसको बनाना नहीं चाहते थे। इस बात को ये मानते हैं कि ये इसको बनाना नहीं चाहते थे।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, कांग्रेसी अगर रोड़ा नहीं अटकाते तो हमने तो कब की यह नहर बनवा दी होती।

श्री विनोद कुमार शर्मा : स्पीकर साहब, हमारे पास तो रोड़े ही नहीं हैं तो अटकाएंगे कहाँ से? आजकल कई यात्राएं चल रही हैं। कोई आक्रोश यात्रा चल रही है और कोई जन-आक्रोश यात्रा चल रही है। जन आक्रोश तो है लेकिन वह जन आक्रोश इनकी पुरानी सरकार के खिलाफ है। उस यात्रा में जिस तरह से लोग इनको बताते हैं कि वर्ष 2004-05 से पहले जिस प्रकार से पिछली सरकार ने कार्य किए, वह आक्रोश अभी तक लोग भुला नहीं पाए हैं। इस आक्रोश का खामियाजा तो ये आने वाले चुनाव में देख लेंगे कि लोगों में इनके प्रति कितना आक्रोश है। (विघ्न) स्पीकर साहब, अब मैं बिजली के बारे में कहना चाहूँगा। पिछली सरकार ने पता नहीं क्यों बिजली की जरूरत को नहीं समझा। (विघ्न) पिछली सरकार ने इस बात को नहीं समझा कि हरियाणा को बिजली की जरूरत पड़ेगी, किसानों को बिजली की जरूरत पड़ेगी, इंडस्ट्रियलिस्ट्स को बिजली की जरूरत पड़ेगी। अपने शासनकाल में उन्होंने कोई भी नये बिजली के संयंत्र लगाने की कोशिश नहीं की। हमारी सरकार ने पिछले चार वर्षों के दौरान यह फैसला किया है कि इस समय जो बिजली की उत्पादन क्षमता लगभग 4753 मेगावाट है उसको हमारी सरकार आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ाएगी। स्पीकर साहब, हिसार जिले में खेदड़ गांव में 4297 करोड़ रुपये की लागत से लग रहे 1200 मेगावाट की क्षमता का राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट का 50 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। इसकी 600 मेगावाट की पहली इकाई दिसम्बर, 2009 में और 600 मेगावाट की दूसरी इकाई मार्च, 2010 तक तैयार हो जाएगी। इसी तरह से जिला फतेहाबाद में कुम्हारियां गांव में 2800 मेगावाट का परमाणु संयंत्र लगाने के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। (विघ्न) हम चाहेंगे कि ये भी इस बारे में हमारा समर्थन करें।

डॉ० सुशील इन्दौरा : स्पीकर साहब, *****

Mr. Speaker : Nothing to be recorded.

श्री विनोद कुमार शर्मा : स्पीकर साहब, हमारी सरकार बिजली क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए लगभग चालीस हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : डॉ० साहब, वह पॉलिसी बता रहे हैं और पौलिसी बताने में झूठ नहीं होता।

श्री विनोद कुमार शर्मा : स्पीकर साहब, यह तो हमारी सरकार की पौलिसी है। पूरी सिंसियरिटी के साथ हम काम करेंगे, इसका हम इनको विश्वास दिलाते हैं। (विघ्न) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य में बिजली उत्पाद, प्रसारण और वितरण मजबूत बनाने

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[श्री विनोद कुमार शर्मा]

के लिए 25524 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इतनी राशि का पहले कभी भी प्रावधान नहीं किया गया। नये संयंत्र लगाने के लिए और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए इतनी राशि का प्रावधान किया गया है। (विघ्न)

बिजली मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला) : अध्यक्ष महोदय, इंदौरा जी और सीताराम जी सीनियर सदस्य हैं इनको बैठे-बैठे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इन जैसे सदस्यों को बैठे-बैठे अनाप-शनाप टिप्पणी करना शोभा नहीं देता। (विघ्न)

श्री विनोद कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने किसानों के साथ-साथ, मजदूरों के साथ-साथ व्यापारियों के साथ-साथ शहरों में जो कार्यक्रम चालू किए हैं उनके जरिए अर्बन एरियाज में उन्नति के नये आयाम हमारी सरकार ने कायम किए हैं। यह बहुत सराहनीय है। पहले जिन एरियाज में सीवरेज की लाइनें नहीं थीं, वहां अब सीवरेज की लाइनें पड़ रही हैं। जहां सड़कें नहीं थीं, वहां सड़कें बनाई जा रही हैं। हमारी सरकार ने अप्रैल, 2008 में गृहकर हटाकर 9 लाख परिवारों को 35 करोड़ रुपये की राशि का लाभ दिया है। पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को सुविधायें दी हैं। पेयजल प्रदान करने पर खासतौर पर ध्यान दिया है। गांवों में पेयजल की विशेषतौर पर दिक्कत थी। हमारी सरकार ने इंदिरा गांधी पेयजल स्कीम शुरू की है और इस स्कीम के तहत तीन वर्षों में 8 लाख अनुसूचित जाति के परिवारों को मुफ्त कनैक्शन दिये जाएंगे। अब तक 4.5 लाख से अधिक कनैक्शन दिये जा चुके हैं। ऐजूकेशन के क्षेत्र में पिछले 4 वर्षों में सरकार ने बहुत से काम किए हैं। कॉलेज शिक्षा, स्कूल शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा, मेडीकल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा आई०टी०आई० के दृष्टिकोण से हटकर भविष्य की जरूरत के अनुसार हमारी सरकार ने क्रांतिकारी पहल की है और ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। वर्ष 2008 को शिक्षा वर्ष के रूप में मनाया गया है। हमारे प्रदेश में इससे पूर्व शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका था कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद विद्यार्थी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। स्पीकर सर, हमारी सरकार ने शिक्षा को आगे बढ़ावा देने के लिए जो कार्य किए हैं उसके बाद वर्ष 2007-08 में जो ऐजूकेशन इंडैक्स बना है उसमें वर्ष 2006-07 में हरियाणा प्रदेश 20वें से 7वें स्थान पर पहुँच गया है। आने वाले समय में इससे भी आगे हम जाएंगे लेकिन शिक्षा के माध्यम से जो कार्य हम अपने विद्यार्थियों के लिए करना चाहते हैं उसमें हम कुछ कमी अवश्य महसूस करते हैं। विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करते समय वह मौके नहीं मिलते जो मिलने चाहिएं। विशेषतौर पर गांवों में रहने वाले विद्यार्थियों और गरीब बच्चों को जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उनको शिक्षा का स्यार उतना अच्छा नहीं मिलता। लैवल प्लेयिंग फील्ड, जो एक तरह की समान शिक्षा है वह विद्यार्थियों को नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वे बच्चे जब शिक्षा ग्रहण करके कंपिटीशन में जाते हैं तो पीछे रह जाते हैं। नौकरियां न मिलने का एक बहुत बड़ा कारण मैं यह भी समझता हूँ कि एक तरह का वातावरण, एक तरह का माहौल, एक तरह की शिक्षा और एक तरह के टीचर्ज सबको मिलने चाहिएं ताकि शिक्षा ग्रहण करते समय किसी तरह का भेदभाव न हो और आगे चलकर यह बच्चे हमारे देश के कर्णधार बनें। हरियाणा से ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी निकलकर देश में और विदेशों में जायें और हमारा नाम रोशन करें। आज मंत्री जी ने

प्रश्नकाल के दौरान यह बातें कहीं कि जो विद्यार्थी गरीब हैं उनके नम्बर कम आते हैं और वे फेल हो जाते हैं तो उनको पास करने के लिए ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। पिछले कई वर्षों से यह कार्य किया जा रहा है। फिर हम अपने बच्चों को ग्रेस मार्क्स देकर पढ़ायेंगे तो यह बात सही है कि कुछ हद तक वे बच्चे शिक्षा तो ग्रहण करेंगे लेकिन जब शिक्षा का फायदा लेना चाहेंगे या कम्पीटिशन के एग्जाम में आयेंगे और जब उनको नौकरी की तलाश होगी तब वहां पर हमारे द्वारा दिया गया फायदा, हमारे द्वारा दिए गये ग्रेस मार्क्स उनके काम नहीं आयेंगे। ग्रेस मार्क की प्रक्रिया को छोड़कर हमें शिक्षा के स्यार को, शिक्षा के स्टैण्डर्ड को आगे बढ़ाना चाहिए। एक जैसा मौका सबको देना होगा ताकि शिक्षा के फील्ड में सबको बराबर का हक मिले। हमारी सरकार ने गरीब परिवार के बच्चों के लिए अनूठी मासिक वजीफा स्कीमें बनाई हैं। हमारी सरकार ने अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की ए श्रेणी और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बच्चों को स्कूल और कॉलेज के स्तर पर 500 करोड़ रुपये की अनूठी मासिक वजीफा स्कीमें शुरू की हैं जिसके तहत अनुसूचित जाति के पहली कक्षा से पांचवीं तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 100 रुपये और लड़कियों को 150 रुपये प्रति महीना दिए जा रहे हैं और छठी कक्षा से आठवीं तक की कक्षा में पढ़ने वाले लड़कों को 150 रुपये और लड़कियों को 200 रुपये प्रति महीना दिए जा रहे हैं। नौवीं कक्षा से बाहरवीं तक की कक्षा में पढ़ने वाले लड़कों को 200 रुपये और लड़कियों को 300 रुपये प्रति महीना दिए जा रहे हैं। इसके अलावा ग्याहरवीं और बाहरवीं कक्षा के विज्ञान विषय में पढ़ने वाले लड़कों को 300 रुपये और लड़कियों को 400 रुपये दिए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को स्कूल खर्च के लिए कक्षा अनुसार 740 रुपये और 1450 रुपये वार्षिक एकमुश्त एलाउंस भी दिया जा रहा है। हमारी सरकार ने यह सब फैसले उन लोगों को सामने रखकर किए हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ हैं। यह हमारी सरकार का वायदा है कि इस में सुधार किया जायेगा लेकिन साथ ही मेरा सुझाव है कि जो विद्यार्थी हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जिन स्कूलों का नतीजा अच्छा न हो जहां पर मुतवातर लगातार अच्छे नतीजे न आते हों, वहां पर पढ़ाने वाले टीचर्ज साहेबान पर भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। उनकी भी इस बारे में रिसपौंसिबिलिटी होनी चाहिए, एकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए क्योंकि ये चन्द लोग हरियाणा प्रदेश, इस देश और विद्यार्थियों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। अगर उनको कोई ठीक ढंग से नहीं पढ़ाता है तो उनके अधिकारों से उन्हें वंचित किया जाता है। जो अधिकार हमारे संविधान में और हमारे समाज ने उनको दिए हुए हैं उन अधिकारों से उनको वंचित किया जाता है जिसके लिए दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। इस संदर्भ में शिक्षा के प्रसारण के लिए नये विश्वविद्यालय हरियाणा सरकार ने अपने प्रदेश में खोले हैं जिनमें सोनीपत में दीन बन्धु छोटूराम इंजीनियरिंग कॉलेज को दीन बन्धु साईंस एण्ड टैक्नालॉजी विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय का दर्जा भी बढ़ाकर साईंस एण्ड टैक्नालॉजी विश्वविद्यालय कर दिया गया है और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय में बिजनैस स्कूल और नॉलेज पार्क की भी स्थापना की जा रही है। खानपुर कलां में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। ये विश्वविद्यालय देश का ऐसा पहला विश्वविद्यालय है जिसमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का सब-सैण्टर खोला गया है। जिला रोहतक के गाँव गरनावठी में आई०आई०एम० स्थापित

[श्री विनोद कुमार शर्मा]

किया जायेगा। यह देश का छठा आई०आई०एम० होगा जो कि 165 एकड़ भूमि पर 250 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया जायेगा। इसके अलावा कुण्डली में राजीव गांधी ऐजूकेशन सिटी भी स्थापित की जा रही है। इस सिटी में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की तर्ज पर उच्च कोटि की शिक्षण संस्थाएं स्थापित होंगी ताकि हरियाणा और एन०सी०आर० के नौजवानों को अच्छी उच्च शिक्षा के लिए विदेश न जाना पड़े। यह एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तर्ज पर ये संस्थाएं स्थापित होंगी और उनमें हरियाणा के विद्यार्थियों को 25 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा। हरियाणा के बच्चों को हायर स्टडी के लिए अच्छा मौका उनको घर पर ही मिलेगा और उनको विदेश जाने की जरूरत नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, तकनीकी शिक्षा का प्रसार आज के युग की जरूरत है। पूरी दुनिया में तकनीकी शिक्षा का प्रसार हो रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। जो मुल्क तरक्की याफ्ता हैं आज वे मुल्क हिन्दुस्तान की तरफ देख रहे हैं, हिन्दुस्तान के बच्चों की तरफ देख रहे हैं और यहां के पढ़े लिखे नौजवानों की तरफ देख रहे हैं। पिछले 40 सालों में राज्य में 257 तकनीकी संस्थाएं स्थापित हुई थीं और आज प्रदेश में 610 तकनीकी संस्थाएं हैं यानि कि पिछले 40 सालों के दौरान तकनीकी संस्थाओं में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 40 हजार थी जबकि पिछले 4 सालों में यह संख्या 80 हजार हुई है। 40 सालों में 40 हजार विद्यार्थी और 4 सालों में 80 हजार विद्यार्थी, यह अपने-आप में एक मापदंड है कि जितना कार्य 40 सालों में तकनीकी शिक्षा के प्रसार के लिए हुआ है उतना कार्य इस सरकार ने इन 4 सालों में किया है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह इंजीनियरिंग कॉलेजिज़ 40 सालों में 40 बने हैं जबकि इन 4 सालों में 38 नए इंजीनियरिंग कॉलेजिज़ नए खोले गए हैं। यह भी अपने-आप में एक मिसाल है कि जितने कॉलेजिज़ 40 सालों में खुले उतने ही कॉलेजिज़ इस सरकार ने 4 सालों में खोले हैं। एम०बी०ए० कॉलेजिज़ पिछले 40 सालों में 32 थे जबकि इन 4 सालों में 61 और एम०बी०ए० कॉलेजिज़ खोले गए हैं यानि कुल मिलाकर अब 93 एम०बी०ए० कॉलेजिज़ हैं। शिक्षा की तरफ हमारी सरकार का ध्यान है ताकि शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के प्रसार से हम अपने बच्चों के लिए नौकरियों का प्रावधान कर सकें और हमारे बच्चे नौकरियां पा कर अपने देश की सेवा कर सकें। लड़कियों और गरीब बच्चों के लिए सुविधाएं इस सरकार ने दी हैं। सभी आई०टी०आई० और तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश हेतु लड़कियों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। रोजगार के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या हरियाणा और दूसरे प्रदेशों में है। हरियाणा में खासतौर पर नौजवान विद्यार्थी जब पढ़ लिखकर आते हैं, वे रोजगार न मिलने की शक्ल में नाउम्मीद हो जाते हैं। रोजगार दिलवाने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। रोजगार दिलवाने के लिए हमारी सरकार ने जो कार्य किया है वह यह है कि नई उद्योग नीति से एक दशक में 10 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त करवाने का लक्ष्य रखा है। अध्यक्ष महोदय, लाडली स्कीम बड़ी लोकप्रिय स्कीम है। इस स्कीम के तहत परिवार में दूसरी लड़की के जन्म पर 5 वर्ष की अवधि तक प्रति वर्ष 5000 रुपये दिए जाते हैं। अभी तक इस योजना के तहत 87,841 परिवारों को लाभ प्रदान किया जा चुका है। यह आमतौर पर देखा गया है कि जिन परिवारों में

सिर्फ लड़कियां होती हैं उन परिवारों में लड़कियों के प्रति उदासीनता परिवार की तरफ से दिखाई जाती है। इस चीज को सामने रखते हुए लाडली सामाजिक सुरक्षा पैंशन स्कीम नामक एक नई योजना शुरू की गई है। ऐसे माता पिता को 60 वर्ष की बजाय 45 वर्ष की आयु में 500 रुपये प्रति माह पैंशन देने का निर्णय किया गया है। यह सही बात है कि किसी भी समाज और प्रदेश को आगे बढ़ाने में हमारे नवयुवकों का हाथ है। खेलों का विकास हमारे नवयुवकों को आगे ले जाने में और सक्षम करने में अहम रोल प्रदान करता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीजिंग ओलम्पिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाले भिवानी के श्री विजेन्द्र सिंह को 50 लाख रुपये हमारी सरकार की तरफ से नकद ईनाम दिया गया है, इसी जिले के मुक्केबाजी में ही क्वार्टर फाईनल में पहुँचने वाले श्री अखिल कुमार व श्री जितेन्द्र कुमार को भी 25-25 लाख रुपये की राशि बतौर ईनाम दी गई और इनके कोच श्री जगदीश सिंह को भी 25 लाख रुपये नकद ईनाम देकर सम्मानित किया गया। कुश्ती में क्वार्टर फाईनल में पहुँचने वाले सोनीपत के श्री योगेश्वर दत्त को भी 25 लाख रुपये की राशि ईनाम के तौर पर दी गई। यह राशि हमारी सरकार ने ओलम्पिक में गये मुक्केबाजों और दूसरे खिलाड़ियों को भी दी है। यह सब कुछ खेलों का सम्पूर्ण विकास करने के लिए किया गया है। मैं यहां यह कहना चाहूँगा कि इससे पहले जो सरकार थी उसने खेलों के विकास की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया जिससे हरियाणा में जितना खेलों का विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हो पाया। इससे पहली सरकार ने खेलों के विकास की तरफ ध्यान न देकर खेलों और खेलों के अदायरों के ऊपर कब्जा करने की कोशिश जरूर की। जब भी किसी खेल की कोई कमेटी बनती थी तो देखने को यही मिलता था कि एक परिवार का कोई सदस्य किसी कमेटी का अध्यक्ष बना है या खेल से सम्बन्धित किसी फैडरेशन का अध्यक्ष बना है। इस प्रकार से उन्होंने अपने आपको यहीं तक महदूद रखा कि कमेटी और फैडरेशन का अध्यक्ष बना जाये। इसके अलावा उनका दूसरा लक्ष्य होता था इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन में अपनी रिप्रेजैंटेशन देना। खेलों के विकास की तरफ उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी क्योंकि न तो वे खिलाड़ी थे और न ही खेलों के बारे में कुछ जानते थे। वे सिर्फ राजनीति जानते थे और अपने राजनीतिक लाभ के लिए खेलों के अदायरों में बहुत ज्यादा इंटरफिरैंस करते थे जिससे कि हरियाणा में पिछले समय में जो खेलों का विकास हो सकता था वह नहीं हुआ। हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हम अपने नौजवानों को बेहतर और आधुनिक सुविधाओं के साथ सभी अंतर्राष्ट्रीय खेलों का अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण दिलायेंगे जिससे कि वे खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़कर नैशनल और इंटरनैशनल लैवल पर प्रदेश के साथ-साथ देश का नाम भी रोशन कर सकें। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ हमारी सरकार ने एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। प्रदेश सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से हरियाणा राज्य में आए प्रत्येक कश्मीरी परिवार को एक हज़ार रुपये प्रति मास की वित्तीय सहायता दी जा रही है। यह कैसी विडम्बना है कि हमारे देश में हमारे ही देश के लोगों को अपने ही प्रदेश के कुछ दहशत-पसंद लोगों की कार्यवाईयों से अपना घर छोड़ना पड़ा और जब तक कि वहां के हालात ठीक नहीं हो जाते वे अपने प्रदेश में वापिस भी नहीं जा सकते। हमारी सरकार द्वारा उनकी मुश्किलों को देखते और समझते हुए उनके समर्थन में उनकी मदद करने के लिए एक हज़ार रुपये प्रति मास की दर से उनको राशि दी जा रही है। इस बारे

[श्री विनोद कुमार शर्मा]

में मेरी सलाह है और मैं अपनी तरफ से सरकार से गुजारिश भी करूंगा कि सरकार को इस राशि को बढ़ाना चाहिए क्योंकि आज के युग में एक हजार रुपये प्रतिमास देने से किसी परिवार का गुजारा नहीं हो सकता। एक हजार रुपये प्रति महीना उन लोगों के लिए बहुत ही कम राशि है जो अपना घर-बार छोड़कर हमारे पास आकर बसे हैं। उनकी भरपूर मदद करना आज हमारा फर्ज है। अध्यक्ष महोदय, गरीब आदमी का अपना मकान हो यह सपना महात्मा गांधी जी ने देखा था। उनके इस सपने को पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने 2300 करोड़ रुपये की लागत से महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना तैयार की है। अध्यक्ष महोदय, यहां मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि वर्ष 2004-05 में तत्कालीन सरकार का टोटल प्लान आऊटले 2236 करोड़ रुपये था और उस 2236 करोड़ रुपये में से कितना पैसा उस सरकार ने लोगों की भलाई के लिए खर्च किया, कितना सड़कों पर लगाया और कितना अन्य विकास कार्यों में लगाया यह तो मैं नहीं बता सकता लेकिन मैं यह जरूर कह सकता हूँ कि वह पैसा कहीं लगा हुआ हमें दिखाई नहीं दिया। वह सारा पैसा कहां गया इस पर तो शायद इन्दौरा जी ही रोशनी डाल सकते हैं। हम इंतजार करेंगे कि वे इस पर रोशनी डालें। अध्यक्ष महोदय, एक बात इन्दौरा जी को माननी ही पड़ेगी कि जो उनकी सरकार के समय में पूरा प्लान आऊटले था 2236 करोड़ रुपये और उससे ज्यादा राशि यानि 2300 करोड़ रुपये की लागत से हमारी सरकार द्वारा गरीब व्यक्तियों के परिवारों को 100-100 गज के मुफ्त प्लाट देने की योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के परिवारों को, बी०सी०-ए कैटेगरी के परिवारों को और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले सभी परिवारों को 100-100 गज के प्लाट मुफ्त दिये जायेंगे। पिछली सरकार का जितना प्लान बजट था उतने पैसे में हमारी सरकार द्वारा गरीब लोगों को मुफ्त प्लाट दिये जा रहे हैं ताकि वे अपना घर बसा सकें। इस योजना के तहत दो साल में 6 लाख परिवारों को मुफ्त प्लाट दिये जायेंगे और 27 जनवरी, 2009 तक एक लाख 18 हजार से अधिक प्लाट आबंटित किये जा चुके हैं। इन बस्तियों में सभी मूलभूत नागरिक सुविधायें उपलब्ध करवाई जायेंगी। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जातियों तथा विमुक्त व टपरीवास जातियों के लोगों को मकान बनाने के लिए दिये जाने वाले अनुदान की राशि को भी हमारी सरकार द्वारा 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है। इसी तरह से इंदिरा गाँधी पेयजल स्कीम के तहत 977000 अनुसूचित जातियों के परिवारों को निजी कनैक्शन और पानी की टंकी मुफ्त प्रदान की जा रही है और अब तक साढे 4 लाख कनैक्शन दिये जा चुके हैं। उन परिवारों के लिए सरकार की बहुत बड़ी सोच थी कि जो लोग पीने के पानी से महरूम थे उन परिवारों के लिए पीने के पानी की टंकी और कनैक्शन लगा कर दिये जायें ताकि उनको पीने का पानी मिल सके। इसके तहत 9 लाख 77 हजार लोगों को इसका फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे व्यापारियों की भलाई के लिए बहुत से कार्य हमारी सरकार ने किये हैं। छोटे से छोटे व्यापारी से लेकर बड़े से बड़े व्यापारी तक को हमने राहत दी है। चाहे हलवाई हो, दवा विक्रेता हो, खुदरा विक्रेता हो, टूल विक्रेता हो, जूता विक्रेता हो या छोटा दुकानदार हो, सबके लिए वर्ष में एक लाख रुपये से कम कर अदा करने वाले व्यापारियों को वार्षिक कर विवरणी दाखिल करने वाले व्यापारियों को वार्षिक कर

विवरणी दाखिल करने की छूट दी गई। वैट डी-3 जारी करने की न्यूनतम सीमा 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दी गई है। देरी से कर अदा करने के मामले में ब्याज की दर 90 दिन तक 1.5 प्रतिशत से कम करके 1 प्रतिशत कर दी गई है और 90 दिन के बाद यह दर 3 प्रतिशत से घटा कर 2 प्रतिशत कर दी गई है। कैश मीमो जारी करने की न्यूनतम सीमा 100 रुपये से बढ़ा कर 300 रुपये की गई है। घोषणा फार्म का प्रयोग किये बिना मैन्यूफैक्चरिंग में प्रयोग होने वाले 159 मदों पर कर की दर घटा कर 4 प्रतिशत की गई है। चावल के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्यात पर कर वापसी का प्रावधान कर दिया है। जैसे राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण में सबसे पहले कहा गया कि पूरी दुनिया में मंदी के हालात पैदा हुए हैं। उस मंदी का असर हमारे हरियाणा प्रदेश पर भी है। यह असर खासतौर से उन लोगों पर जो व्यापारी शहरों में बैठे हैं और छोटे-छोटे सन्नतकार जो छोटी-छोटी चीजें बना कर इस देश से दूसरे देशों में भेजते थे, एक्सपोर्ट करते थे पर हुआ है। आज उनका कारोबार बंद होने के कगार पर आ गया है। आज इस मैल्ट डाऊन का असर पूरे हरियाणा में, पूरे देश में और हर सूबे में देखने को मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार उन लोगों के लिए और भी कुछ ऐसे प्रावधान करेगी जिससे उनको राहत मिलेगी। ऐसी टैक्स कन्सैशन हम उनको दें जिसकी वजह से जो व्यापारी आज मुश्किल में हैं उन व्यापारियों के ऊपर जो बोझ है वह थोड़ा सा कम हो सके और वह मंदी के सफर से निकल कर फिर अपना अच्छा व्यापार कर सकें। इसकी वजह से फिर से सरकार को अच्छी आमदनी होने लगेगी और हमारी सरकार हमारे प्रदेश में और अधिक उन्नति कर सकेगी। स्वतंत्रता सेनानियों और भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण मैं समझता हूँ कि होना चाहिए। हमारे देश की आजादी के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दीं, जो लोग देश की आजादी के लिए लड़े उन लोगों ने अपने लिए देश की आजादी नहीं मांगी थी उन्होंने अपने परिवारों को छोड़कर हमारे लिए देश की आजादी माँगी थी। आज अगर हम आजाद देश में रह रहे हैं, आज अगर हमारे हक और हकूक महफूज हैं तो इसी वजह से हैं क्योंकि उन लोगों ने हमारे लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए लड़ाई लड़ी थी। भले ही उनको बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ी और उन लोगों के परिवारों को जितना ज्यादा हो सके लाभ मिलना चाहिए। उनको सहायता दी जानी चाहिए। उनकी सहायता केवल धन से ही नहीं करनी चाहिए, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। अगर उन्हें धन की आवश्यकता है तो धन से भी उनकी सहायता करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने अपनी जिन्दगी के वे वर्ष देश की आजादी के लिए न्यौछावर किये जिन वर्षों में वे अपना परिवार पाल सकते थे, अपने लिए कोई व्यापार कर सकते थे, अपने लिए मकान बना सकते थे, अपने लिए कुछ कर सकते थे, उन्होंने वे वर्ष इस देश के लिए, हमारे लिए, इस देश के करोड़ों बाशिंदों के लिए न्यौछावर किये हैं उनके प्रति हमारा फर्ज बनता है। उसी फर्ज को सामने रखते हुए हमारी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को 1525 रुपये की जो पैंशन मिलती थी उसको बढ़ा कर 5500 रुपये कर दिया है। हरियाणा सरकार द्वारा 60 वर्ष से अधिक उम्र के भूतपूर्व सैनिकों तथा उनकी विधवाओं को जो कोई पैंशन प्राप्त नहीं कर रहे थे, को एक हजार प्रति मास की वित्तीय सहायता भी दी जाती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से सम्बन्ध रखते हैं। उनके दादा और उनके पिता जी ने इस देश की आजादी के लिए

[श्री विनोद कुमार शर्मा]

कुर्बानियाँ दी और अपने परिवार में उन्होंने एक ही शिक्षा दी कि हम देश के लिए लड़ेंगे, देश की आज़ादी के लिए लड़ेंगे और उन्हीं का अनुसरण करते हुए आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे देश की आजादी के उन परवानों के खानदानों को चलाते हुए आज अपनी सरकार के जरिये इस प्रदेश के लिए और इस प्रदेश के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद और विश्वास है कि आज जो स्कीम्ज उन्होंने शुरू की हैं वे उनको ईमानदारी से पूरा करेंगे। इस बात का विश्वास पूरे प्रदेश और इस हाउस को है। उनके मन में किसी को भुलावा देने या किसी तरह की कोई गलतफहमी रखने की बात नहीं है। स्पीकर सर, मुझे पूर्ण विश्वास और उम्मीद भी है कि जिस राह पर वे चल रहे हैं, जिस राह को हमारी सरकार ने पकड़ा है, उस राह पर चलते हुए जैसे हमारे प्रदेश के लोग खुश हैं आज से पहले कभी इतने खुश नहीं हुए हैं, मेरे साथ बैठे हुए लोगों को आने वाले समय में इसका उदाहरण मिलेगा। इससे पहले कि मैं अपने भाषण को विराम दूं मैं आपके सामने एक बात जरूर रखना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति आज से करीब 4 वर्ष पहले कैसी थी। 4-5 वर्ष पहले जैसी कानून-व्यवस्था की स्थिति थी उसको बोले बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। उस वक्त ऐसा लगता था कि हरियाणा दिल्ली के पास होते हुए भी एक ऐसा प्रदेश है जहां रहना दूभर और बहुत मुश्किल था। ऐसे लोग, जो सरेआम गुनाह करते थे, सरेआम जुल्म करते थे सरकार की तरफ से उनको पनाह दी जाती थी। ऐसे लोग सरेआम गरीब आदमी को लूटते थे, सरेआम दूसरों की जायदाद पर नज़र रखते थे। स्पीकर सर, ऐसे लोगों का उस समय बहुतायत था और इस प्रकार के इंसिडैंटस आम होते थे। हमारे इलाके में कुछ ऐसा वातावरण बना कि दूसरे लोगों और बहुत से इण्डस्ट्रियलिस्ट्स ने यह मन बना लिया था कि हरियाणा से पलायन करके किसी दूसरी जगह पर अपनी इण्डस्ट्रीज़ और बिजनैस ले जाएंगे। स्पीकर सर, मुझे आज यह कहते हुए खुशी हो रही है कि हरियाणा में हमारी सरकार की नीतियों की वजह से पूरे देश से और विदेशों से भी हजारों लोगों ने यहां आ कर अपनी इण्डस्ट्रीज़ लगाने का मन बनाया है और इस प्रदेश में अपना धन लगाने की इच्छा व्यक्त की है। स्पीकर सर, इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ तथा सदन के सभी सदस्यों से यह रैजोल्यूशन पास करने की प्रार्थना करता हूँ और इसको सपोर्ट करता हूँ।

श्री उदयभान (हसनपुर, अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद! 06 तारीख को महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण सदन में रखा और उसके सम्बन्ध में माननीय साथी श्री विनोद शर्मा जी ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा है, उसके अनुमोदन के लिए मैं खड़ा हूँ। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने हमारे हरियाणा प्रदेश के महान सपूत चौधरी रणबीर सिंह जी, जो हमारे स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख सेनानी थे, के सम्बन्ध में जिक्र किया है। अध्यक्ष महोदय, चौधरी रणबीर सिंह जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को हम कुछ शब्दों में पूरा ब्यान नहीं कर सकते। स्पीकर सर, उनका संघर्ष तो इतनी बड़ी गाथा है कि उनकी प्रशंसा में कितनी ही किताबें लिखी जा सकती हैं। वे बहुत ही बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। वे महान देशभक्ति, ईमानदारी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति थे और एक आदर्शवादी और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। उनका जीवन राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और धार्मिक तौर पर बहुत बड़े संघर्ष की

गाथा है। उन्होंने अपने जीवनकाल में अपने जवानी के दिनों में अंग्रेजों के शासन के खिलाफ संघर्ष किया। स्वाधीनता संग्राम के आन्दोलनों में भाग लिया तथा साढ़े तीन वर्ष घर में कैद रहे तथा दो वर्ष तक नजरबन्दी की जेल में रहे। उन्होंने आठ साल तक अम्बाला, रोहतक, लाहौर, मुल्तान, स्यालकोट, हिसार, फिरोजपुर आदि जेलों में हमारी आजादी के लिए अपनी जवानी के दिन गुजारे। स्पीकर सर, मैं समझता हूँ कि हिन्दुस्तान के वे प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो सात साल तक विधाई संस्थाओं के सदस्य रहे। वे संविधान सभा के एकमात्र जीवित सदस्य थे। जहां वे संविधान सभा के सदस्य रहे, वहीं पर वे अस्थाई लोक सभा, राज्य सभा, पंजाब विधान सभा और हरियाणा विधान सभा के सदस्य भी रहे। सभी अदायरों में रहते हुए उन्होंने देश और प्रदेश की सेवा की है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। उन्होंने सिंचाई मंत्री के रूप में पंजाब और हरियाणा के किसानों को जो कुछ दिया है उसको भुलाया नहीं जा सकता है। आज हिमाचल, पंजाब और हरियाणा प्रदेश के अन्दर जो खुशहाली नजर आती है वह सब उनकी ही देन है। उनकी वजह से ही इन प्रदेशों में हरित क्रान्ति आई है। स्पीकर सर, भाखड़ा बांध परियोजना भी उनके समय में पूरी हुई और उसकी वजह से ही पंजाब और हरियाणा के किसानों ने बहुत तरक्की की है। इसके साथ-साथ व्यास नदी पर पौंग डैम परियोजना भी उन्हीं की देन है। हमारे यहां फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात और पलवल चारों जिलों के साथ-साथ राजस्थान के लोगों को भी गुड़गांव कैनाल के माध्यम से सिंचाई सुविधा मिली है जिसका एकमात्र श्रेय रणबीर सिंह जी को जाता है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के ये चारों जिले उनका यह अहसान कभी नहीं उतार सकते हैं। स्पीकर सर, उन्होंने अपने पिता चौधरी मातुराम जी, अपने दादा चौधरी बखतावर सिंह जी से और आर्य समाज से सामाजिक मंच पर बोलने की प्रेरणा ली थी। अध्यक्ष महोदय, हमारे स्वतन्त्रता संग्राम के नायक लाला लाजपत राय जी और शहीदे आजम भगत सिंह जी के परिवारों से उनके संबंध थे उसका ही परिणाम था कि उन्होंने सामाजिक मोर्चे पर संघर्ष किया। उन्होंने गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी। हरिजनों और बैकवर्ड कलासिज़ के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। वे हरिजन सेवक संघ और अखिल भारतीय पिछड़ा संघ के भी अध्यक्ष रहे। उन्होंने पिछड़े वर्ग के प्रति, जातिवाद के प्रति जो पाखंड था, अविश्वास था उसके विरूद्ध लड़ाई लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। चौधरी रणबीर सिंह जी हमारे इस प्रदेश के लिए और देश के लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने हरियाणा प्रदेश की सरकार के नीतिगत दस्तावेज़ का जो ब्यौरा पेश किया है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनके मंत्रीमंडल को बधाई देता हूँ कि उन्होंने चार साल के अन्दर हरियाणा प्रदेश को कहां से कहां पहुँचा दिया है। अध्यक्ष महोदय, शर्मा जी ने जिक्र किया था कि चार साल पहले वर्ष 2004-05 का प्लान बजट 2236 करोड़ रुपये का था और अब 2009-10 में 10 हजार करोड़ रुपये का प्लान बजट है। यह इस बात को दर्शाता है कि हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कितना बेहतरीन और शानदार कार्य किया है। यह जो पांच गुणा प्लान बजट में वृद्धि हुई है उसके लिए यह सरकार बधाई की पात्र है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगा पिछले साल 6650 करोड़ रुपये का प्लान बजट था जो कि इस बार 10 हजार करोड़ रुपये का है। इस बजट में 50 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ौतरी

[श्री उदयभान]

हुई है। इसी प्रकार से जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सपना देखा था और कहा था कि हरियाणा प्रदेश को नम्बर एक पर लाऊंगा उसको कार्यन्वित करते हुए आज जो प्रति व्यक्ति आय हरियाणा प्रदेश की है वह पूरे देश में गोवा के बाद दूसरे नम्बर पर है। यह आय 58 हजार 531 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है जो कि अपने आप में बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसी प्रकार से इन्वैस्टमैंट के रूप में सी०एम०आई० (सैन्ट्रल फार मॉनिटरिंग ऑफ इण्डियन इकोनोमी) की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक हरियाणा प्रदेश इन्वैस्टमैंट के मामले में नम्बर एक पर है। रिपोर्ट के हिसाब से 78 हजार 5 सौ रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से इन्वैस्टमैंट हुई है। अध्यक्ष महोदय, पांच साल पहले जो इनैलो की सरकार थी उनके समय में हरियाणा प्रदेश इन्वैस्टमैंट के मामले में 13वें नम्बर पर था और आज वही हरियाणा प्रदेश पहले नम्बर पर है। इसके लिए मैं इस सरकार को और सरकार के मंत्रिमंडल को और सहयोगियों को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। जहां तक सरकार का आम आदमी को लाभ देने का सवाल है, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। बिजली के बिलों के ब्याज के बारे में पिछली सरकार बनने से पहले वे कहते थे कि न मीटर रहेगा और न रीडर रहेगा। वे उस समय कहते थे कि बिजली तो आएगी लेकिन मीटर नहीं रहेगा। उनका उस समय यह भी कहना था कि बिजली के बिल देने की जरूरत नहीं है। वे लोगों को भड़काते थे और कहते थे कि जब हमारा राज आएगा तो बिजली के बिल किसी को भरने की जरूरत नहीं होगी और अगर बिजली वाले बिजली के बिल मांगने आएं तो आप उनके नाक कान काट लेना। वे लोगों को कहते थे कि आप उस्तरा रखो और एक ब्लेड रखो। उसके बाद लोगों ने बहकावे में आकर बिजली के बिल्ज भरने बंद कर दिए। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और दूसरे लोगों ने अपनी झोली फैला फैलाकर गांव-गांव जाकर इनके लिए वोट मांगे और इनकी सरकार बनवायी। अध्यक्ष महोदय, इनका बिजली के बिल्ज न भरने का बिल्कुल झूठा आश्वासन था। जिन्होंने इनके लिए वोट मांगे थे जब उन्होंने इनसे कहा कि आपकी वजह से लोगों ने बिजली के बिल्ज नहीं भरे और अब उनके ऊपर ब्याज का बोझ चढ़ गया है इसलिए अब आप कम से कम ब्याज तो माफ कर दें। स्पीकर साहब, आपको भी पता ही है कि इनके राज में एक दो नहीं बल्कि नौ-नौ किसानों को गोलियों से उड़ाया गया था। स्पीकर साहब, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष घासीराम नैन ने घर-घर जाकर इनकी सरकार बनवाने के लिए वोट मांगे थे लेकिन जब उन्होंने बिजली के बिलों के ब्याज माफ करने के लिए कहा तो उन पर केस दर्ज करके वे धाराएं लगायी गयी थी जो देशद्रोहियों, उग्रवादियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों पर लगायी जाती हैं। इस तरह की धाराएं लगाकर उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। मैं चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बगैर किसी मांग के बिजली के बिल मुआफ किए। कांग्रेस पार्टी का इस बारे में कोई वायदा नहीं था फिर भी उन्होंने एक कलम से ही 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ कर दिए। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। इसी प्रकार से 823 करोड़ रुपये के कोऑपरेटिव बैंक के, लैंड मोर्टगेज बैंक के, हरियाणा हरिजन कल्याण निगम के, बैकवर्ड क्लासिज निगम के या लाई माई लोगों के जो लोन थे, जो ब्याज था वे सभी उन्होंने माफ कर दिए। हाउस टैक्स चाहे वह देहात में रहने वालों का हो या शहर में रहने वालों का

हो, सभी का माफ करने का भी काम किया है। मैं इसके लिए सरकार का धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। स्पीकर साहब, बिजली, सड़क और पानी एक बुनियादी आवश्यकता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और बिजली मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि बिजली जैसे मामले में जहां पिछली सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया उन्होंने एक भी प्रोजैक्ट नहीं लगाया वहीं हमारी सरकार ने बिजली के चार-चार प्रोजैक्ट टेकअप किए हैं। पहले केवल 1857 मेगावाट बिजली का ही अपने लैवल पर उत्पादन होता था। स्पीकर साहब, आपको पता ही है कि एक प्रोजैक्ट तैयार होने में तीन साल तो कम से कम लग ही जाते हैं क्योंकि सबसे पहले जमीन ऐक्वायर करनी पड़ती है, उसके लिए धन मुहैय्या करवाना पड़ता है। जो मूलभूत आवश्कताएं हैं उनको उपलब्ध करवाना पड़ता है, जो रॉ मैटीरियल है उसके लिए इंतजाम करना पड़ता है और यह देखना होता है कि यह प्लांट कोल बेस्ड होगा, नैप्था बेस्ड होगा या गैस बेस्ड होगा। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि चार-चार प्रोजैक्ट इस सरकार ने टेकअप किए हैं। यमुनानगर का जो थर्मल पावर प्लांट है यह पहले बीस पच्चीस साल से उलझा पड़ा था क्योंकि पहले वाली सरकार लेनदेन के चक्कर में पड़ी थी, उनका सौदा नहीं पटा था। अब इस सरकार के आते ही उसका काम शुरू हुआ है न केवल काम शुरू हुआ है बल्कि आज वह रिकार्ड समय में पूरा भी हो गया है और अब उससे उत्पादन भी शुरू हो गया है। हमें इस बात की बहुत खुशी है। स्पीकर साहब, इसी तरह से हिसार जिले में खेदड़ गांव में 1200 मेगावाट के राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट की 600 मेगावाट की पहली इकाई का कार्य दिसम्बर, 2008 में और 600 मेगावाट की दूसरी इकाई का कार्य मार्च, 2010 में पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार से झाड़ली में 1500 मेगावाट का एक और प्रोजैक्ट है इसमें से आधी बिजली हमें मिलेगी। इसी तरह से 1320 मेगावाट का एक और प्रोजैक्ट झज्जर में आ रहा है। इसके अलावा 3835 मेगावाट बिजली केन्द्र सरकार की विभिन्न परियोजनाओं से मिलने की व्यवस्था की गयी है। मैं इसके लिए सरकार को बधाई देता हूँ क्योंकि सरकार ने यह मामला बहुत गंभीरता से लिया है। इसके अलावा अक्षय ऊर्जा नीति के तहत 709 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए भी स्वतंत्र बिजली उत्पादकों के साथ समझौते किए गए हैं। इसके अलावा ट्रांसमिशन लाईन पर सब-स्टेशनों की क्षमता बढ़ायी गयी है जो कि बिजली विभाग की तरफ से बहुत सराहनीय कार्य हुआ है। मैं इसके लिए सरकार को बहुत बधाई देता हूँ। जहां तक सड़कों की बात है, वर्ष 2008-09 में सड़कों का बजट 670 करोड़ रुपये था जो अब बढ़ाकर 1540 करोड़ रुपये कर दिया गया है यानी दोगुणे से भी ज्यादा सड़क का बजट इस सरकार ने किया है। अब सड़कों के बारे में चर्चा हुई है। सरकार ने जो कदम उठाए हैं उन पर चैक करने की जरूरत है ताकि कहीं क्वालिटी से कोई समझौता न हो, यह तो अलग बात है लेकिन सरकार का जो काम है वह नजर आता है। सड़कों के लिए वर्ष 2009-10 में बजट दुगुना किया गया है, 1540 करोड़ रुपये बजट किया है। एन०सी०आर०, नाबार्ड और पी०एम०जी०एस०वाई० की स्कीम के तहत 2200 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य शुरू किए गए हैं जिनके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को इनके इस प्रयास के लिए बधाई देना चाहूँगा कि वर्ष 1966 से 2005 तक 16 आर०ओ०बी० बने और इन चार सालों में 33 आर०ओ०बी० पर काम चल रहा है जिनमें से 9 पूरे भी हो चुके हैं और

17.00 बजे

[श्री उदयभान]

7 आर०ओ०बी० दिसम्बर, 2009 तक पूरे हो जाएंगे। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इसके लिए मैं बधाई भी देना चाहूँगा और साथ ही साथ एक रिक्वैस्ट भी करना चाहूँगा। मुझे इस बारे में आश्वासन भी दे रखा है कि होडल हसनपुर रोड पर जैसे आर०ओ०बी० के बारे में लिखित उत्तर में बताया, वह आर०ओ०बी० 25 करोड़ 14 लाख रुपये की लागत से सैंक्शन किया गया है उसमें रेलवे विभाग के अधिकारी की इंस्पैक्शन रिपोर्ट बाकी बची है उसको भी जल्दी से पूरा कराएंगे, ऐसी उम्मीद है। इसकी हमारे इलाके में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। खुद मंत्री जी ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और वे इसके लिए बधाई के पात्र हैं। हमारे होडल हसनपुर वाले आर०ओ०बी० को जल्दी से शुरू करवाने की कृपा करें। दूसरी जो सड़कें हैं रसूलपुर से वाया गुलाबपुर हसनपुर इसके अलावा पालरी, मुंडफटी, मानपुर और कौंडल गांव की सड़क हैं। ये सड़के पी०एम०जी०एस०वाई० से मंजूर हुई थीं और इनकी बहुत ही खस्ता हालत है। इन सड़कों के लिए फंड चाहे नाबार्ड से लो, चाहे एन०सी०आर० या पी०एम०जी०एस०वाई० से लें लेकिन इन सड़कों को जल्दी से जल्दी बनवाने का कष्ट करें। जहां तक पानी का मामला है, उसके लिए भी सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं। चौधरी रणबीर सिंह जी के समय से रेणुका और किसाऊ बांध की प्रपोजल चली थी, पिछली सरकार ने इस ओर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया था। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और सिंचाई मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। ये कई बार इस सिलसिले में दिल्ली में मीटिंग्ज में गए और इस मामले को पूरे जोर शोर से उन मीटिंग्ज में उठाया। रेणुका बांध हमारे हाथ से खिसक चुका था। उसको इन्होंने दोबारा से सिरे लगाने का प्रयास किया और उसके लिए 100 करोड़ रुपये की राशि भी दी। मुख्यमंत्री जी और सिंचाई मंत्री जी के प्रयासों और इंटरवेंशन से हमें इस मामले में काफी कुछ कामयाबी मिली है। अध्यक्ष महोदय, रेणुका, किसाऊ और लखवार डैम हमारे दक्षिणी हरियाणा की जीवन रेखा है। जहां तक हमारे फरीदाबाद और गुड़गांव एरिया में सिंचाई का सवाल है, जब इनमें कुछ पानी स्टोर हो जाए तो पूरा पानी इधर से ही आ सकता है। सिंचाई के पानी की सबसे बुरी हालत हमारे गुड़गांव, फरीदाबाद और मेवात के हिस्से में है। जैसा कि मंत्री जी के नोटिस में भी है कि मेरा जो क्षेत्र है उसमें तीन रजबाहे हैं जो आगरा कैनाल से जाते हैं उनमें एक तो होडल रजबाहा है, दूसरा हसनपुर रजबाहा है और तीसरा हथीन रजबाहा है, इन तीनों की टेल मेरे हल्के में जाती है और टेल पर पानी नहीं है। इसलिए मेरा क्षेत्र इससे सबसे ज्यादा अफैक्टिड है। होडल के आसपास के जो 15 किलोमीटर के रेडियस के गांव हैं, वे सारे के सारे इससे अफैक्टिड हैं उनमें किसी में पानी नहीं है मैं बताना चाहूँगा कि बंचारी, सौंग, डाड़का, बोराका, सोमवास, गोड़ा पट्टी, होडल, बलवाना और डकोरा ये ऐसे गांव हैं जहां न तो सिंचाई के लिए पानी है न पीने का पानी है। जहां तक अंडरग्राउंड वाटर की बात है, वह खारा है। ये बहुत बड़े-बड़े गांव हैं और सीधे तौर पर अफैक्टिड हैं। जो गोछी ड्रेन है उस पर लिफ्ट चैनल लगाकर डाड़का माइनर के माध्यम से इनकी सिंचाई हो सकती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूँगा कि क्या वे इस बारे में जांच करवायेंगे और इस स्कीम के माध्यम से उन गांवों में सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाने की कृपा करेंगे? मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि बन्चारी, सरायें, सोन्ध, होडल

आदि गांवों में पीने का पानी जरूर पहुँचाये। इन गांवों के बारे में 18 दिसम्बर, 2005 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार की घोषणा में कहा था कि होडल सब-डिवीजन के किसी भी गांव में पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन पांच-छः गांवों में पीने के पानी की सही व्यवस्था नहीं है। बन्धारी गांव में तो पानी बिल्कुल नहीं है हालांकि वहां पर पीने के पानी की स्कीम मन्जूर हो गई है और 10-12 किलोमीटर से पानी आयेगा लेकिन उसमें बहुत डिले हो रही है। वह स्कीम पूरी होने वाली थी लेकिन कान्ट्रैक्टर बीच में ही काम छोड़कर चला गया है। इस स्कीम का थोड़ा-सा काम बाकी है उसको शीघ्र करवाने की जरूरत है। आपके माध्यम से मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस तरफ भी ध्यान दिया जाए। जहां तक शहरी विकास का मामला है, इसमें सरकार ने सराहनीय कार्य किया है इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे हल्के की नगरपालिका को पिछली सरकार के समय चौटाला साहब ने भंग कर दिया था लेकिन इस सरकार ने उस नगरपालिका को दोबारा से बहाल कर दिया है इसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : क्यों भंग कर दी थी?

श्री उदय भान : स्पीकर सर, चौटाला साहब भेदभाव का रवैया रखने वाले थे इसलिए हमारी नगरपालिका को भंग कर दिया गया था और उनको इन कर्मों की सजा भी मिल गई। अभी तो इनके पल्ले कुछ नहीं है। अभी तो इनको इस बात के लिए खोदना है। इन्होंने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है कि ये अकेले दम पर कांग्रेस पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। ये तो कोई न कोई बैसाखी ढूंढते हैं चाहे हाथी का सहारा मिल जाये चाहे बी०जे०पी० का कमल मिल जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी याददाश्त ताजा करना चाहूँगा। हमारे फरीदाबाद में बी०जे०पी० नेता चाहे उस समय के अध्यक्ष श्री रतनलाल कटारिया हों, चाहे पार्टी प्रभारी वीर कुमार यादव हों या रामचन्द्र बैन्दा हों, चाहे सीता राम सिंगला हों या बी०जे०पी० पार्टी के विधायक दल के नेता श्री कृष्णपाल गुर्जर हों इनमें से कोई भी ऐसा नेता नहीं था जिसके लट्ठ नहीं लगे हों, जिनकी पिटाई न हुई हो और गोली न चली हो। सबके कुर्ते फाड़ दिए और इन्होंने अटल जी और आडवाणी जी को जाकर त्राहि माम, त्राहि माम न किया हो कि हमें चौटाला जी के जुल्मों से बचाओ। उस जालिम से बचाओ। ये लोग बहुत बुरी तरह से जाकर रोये और अब जाकर इन्होंने एक अवैध गठबन्धन कर लिया। अध्यक्ष महोदय, अवैध रिश्तों का तो पता है उनका हाल तो वही होना है जो चाँद मोहम्मद और फिजा का हुआ है। वह गठबन्धन ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इनकी तो नेवला और सांप वाली दोस्ती है। (शोर) अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को और मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसी पापुलेशन जो विलेजिज और शहरों में थी जहां 50 प्रतिशत से ज्यादा आबादी थी उनके डिवैलपमैंट के लिए 50 लाख रुपये दिये गये जोकि बहुत ही क्रान्तिकारी कदम है हमारी नगरपालिका में एस०सी० वार्ड, जिनकी पापुलेशन 50 प्रतिशत से ज्यादा थी उनके डिवैलपमैंट के लिए एक-एक करोड़ रुपये दिए गये और तेज गति से विकास के कार्य चल रहे हैं। उसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। मेरे हल्के के होडल में वार्ड नम्बर 9 किसी वजह से रह गया है उसके लिए सरकार से मेरा निवेदन है कि वहां की पापुलेशन 60 प्रतिशत से ज्यादा है और उसके लिए पैसा अभी तक नहीं पहुँचा है। मंत्री जी से निवेदन है कि

[श्री उदय भान]

वहां पर पैसा पहुँचाया जाए। दो गांवों बुधराना और पिंगोठ भी इसी कंडीशन में आते हैं। जो सुविधा मंत्री जी ने घोषित की है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वहां पर सुविधा मुहैया करवाई जाए। मैं इस सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दलित परिवारों को 100-100 गज के प्लाट देकर इतना बड़ा काम किया है। अध्यक्ष महोदय, यह काम 40 साल पहले श्रीमती इन्दिरा गान्धी जी ने किया था। हरियाणा प्रदेश पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर पहला प्रदेश है जहां पर यह योजना लागू की जा रही है और लगभग एक लाख 18 हजार 296 लोगों को महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत प्लाट अलॉट कर दिए गए हैं। यह बहुत बड़ा कार्य किया गया है और इसको भुलाया नहीं जा सकता। गरीब आदमी अगली बार ब्याज समेत सरकार को इसकी भरपाई करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 40 साल पहले लोगों के पास गुंजाइश होती थी। लोग कह देते थे कि तू मेरे खेत पर अपने लिए झोपड़ी बना ले, तू मेरे यहां मकान बना लें। उस समय जमीन की वैल्यू नहीं होती थी। जितनी आज एक गज जमीन की कीमत है उस समय इतनी कीमत में दो एकड़ जमीन आ जाती थी। आज एक गज, एक फुट तो क्या एक इंच जमीन के पीछे गोलियां चल जाती हैं। आज के जमाने में एक आदमी के 4 बेटे हों और उनके अलग-अलग राशन कार्ड हों और उनको अगर 500 गज जमीन मिलती है तो 500 गज जमीन की जितनी वैल्यू है उतनी वह सारी जिन्दगी में भी नहीं कमा सकता। गरीबों को प्लाट देना सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। इसमें निश्चित तौर से सरकार ने 6 लाख 7 हजार परिवारों को लाभ होने के बारे में बताया है जोकि एक सराहनीय कार्य है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि इसमें थोड़ा संशोधन किया जाए कि जो लोग इस लाभ से किसी न किसी तरह वंचित रह गए हैं और उनका हक बनता है तो उनकी एप्लीकेशन लेकर जांच करवाकर उनको ये प्लाट दिए जाएं। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में आज सरकार ने अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। खासकर भीमराव अम्बेडकर ने सबसे पहले शिक्षित बनो का नारा लगाया था उसको हमारे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने अमलीजामा पहनाया है। जो गरीब बच्चे पढ़ाई छोड़ जाते थे, कोई 5वीं पढ़कर, कोई 8वीं पढ़कर और कोई 10वीं कक्षा तक पढ़कर वे पढ़ाई न छोड़ जाएं उसके लिए उनको वजीफा देने का बहुत बड़ा काम इस सरकार द्वारा किया गया है। जो एस०सी०/बी०सीज० के पहली क्लास में बच्चे पढ़ने जाएंगे, उनको पीले कार्ड की जरूरत नहीं है और साथ ही बी०पी०एल० वाली दूसरी जातियों के बच्चों को किताबें फ्री, वर्दी फ्री और साथ में लड़के को 100 रुपये और लड़की को 150 रुपये प्रति मास देने का काम किया गया है। छठी से आठवीं कक्षा तक के लड़कों को 150 रुपये प्रति माह और लड़कियों को 200 रुपये प्रति माह, नौवीं से बारहवीं कक्षा तक के लड़कों को 200 रुपये प्रति माह और लड़कियों को 300 रुपये प्रति माह तथा ग्यारहवीं से बारहवीं कक्षा तक के विज्ञान पढ़ने वाले लड़कों को 300 रुपये प्रति माह तथा लड़कियों को 400 रुपये प्रति माह वजीफे के रूप में देने का जो काम किया गया है, यह एक सराहनीय कदम है और इसको एस०सी० और बी०सी० क्लास की पीढ़ियां और खासकर दलित वर्ग के लोग कभी भुला नहीं सकते। अध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन बातें और कहना चाहूँगा। अगर सरकार इनको पूरा करवा दें

तो न कोई हाथी बिगाड़ सकेगा, न कोई डायनासोर बिगाड़ सकेगा और न ही कोई अष्टावक्र हमारा कुछ बिगाड़ सकेगा। इन में से किसी के बस में भी कुछ नहीं रहेगा। अध्यक्ष महोदय, दो तीन काम आप हमारे और करवा दें। एस०सी० और बी०सी० कैटेगरी के रिजर्वेशन में जो बैकलॉग है उसको पूरा कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। अध्यक्ष महोदय, संविधान का जो 85वां संशोधन सरकार ने किया है जो 16.3.2006 से प्रोसपैक्टिव है उसको रिट्रोसपैक्टिव करो। 17 जून, 1985 के संविधान की जो मूल भावना है इसको पूरी तरह से पूर्ण भावना के साथ लागू करें। अध्यक्ष महोदय, क्लास-I और क्लास-II की प्रमोशन में रिजर्वेशन दी जाएं तो आप देखेंगे कि इसके बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप से यह अनुरोध करूंगा कि आप हमारी इन मांगों पर गौर करें और मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि मैंने जो बताया है उन बातों को नोट कर लें और इनको पूर्ण करवा दें। धन्यवाद।

Mr. Speaker : Motion moved—

That an address be presented to the Governor in the following terms :—

"That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 6th February, 2009 at 2.00 P.M."

डॉ० सुशील इन्दौरा (ऐलनाबाद, अनुसूचित जाति) : अध्यक्ष महोदय, माननीय विनोद शर्मा जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर दिया है मैं उस पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं अभिभाषण की शुरुआत चौधरी रणबीर सिंह जी से करूंगा जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे। चौधरी रणबीर सिंह जी ने जिस तरीके से अपने व्यक्तित्व को उभारा और संवारा, वह किसी समुदाय और किसी संस्था में संकुचित होकर नहीं रह सकता, कहने को भले ही वे कांग्रेसी थे लेकिन पूरे समाज का हित उनके अपने चिन्तन में समाहित था। मैं समझता हूँ कि आज देश को इसकी आवश्यकता है। इसके साथ ही मैं उन लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि आज प्रदेश को दिशा देने का दावा करने वाले नेताओं को अगर चौधरी रणबीर सिंह जी के जीवन से कुछ सीखना है तो सबसे पहली चीज यह है कि वे अपने समस्त चिन्तन को समाज के हित में लगायें। मैं चौधरी रणबीर सिंह जी के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूँगा कि सरलता से सच्चाई की बात कहने वाली एक राजनीतिक, देशभक्त आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। ऐसे देशभक्तों और राजनीतिज्ञों को ही याद किया जाता है। स्पीकर सर, इस सदन की एक परम्परा है कि जब भी वर्ष के प्रारम्भ में विधान सभा का प्रथम सैशन शुरू होता है तो सर्वप्रथम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता है। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के माध्यम से सरकार अपनी नीतियों और कार्यक्रमों का उल्लेख करके बताती है कि वह भविष्य में प्रदेश के लोगों के लिए क्या करने जा रही है और प्रदेश के लोगों के प्रति सरकार की क्या सोच है। अभिभाषण के माध्यम से समाज को आईना दिखाया जाता है कि सरकार किस तरह की नीतियां और

[डॉ० सुशील इन्दौरा]

कार्यक्रम बनाकर हर वर्ग का भला और हर प्रकार के विकास के कार्य करती है। स्पीकर सर, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि अभिभाषण में कहीं कोई ऐसी झलक नहीं है। सरकार का गुणगान तो बहुत है और सरकार की प्रशंसा में कसीदे भी बहुत पढ़े गये हैं। जैसे अभी माननीय विनोद शर्मा ही कह रहे थे कि घुमारियां में परमाणु बिजली घर लगा देंगे। यह तो कोसों दूर की बात है। ऐसी बातें तो कही गई हैं लेकिन हकीकत और सच्चाई की बात यह है कि गरीब आदमी को कैसे अपना पेट भरने के काबिल बनाया जायेगा और जो लोग काम की तलाश में आज दर-दर भटक रहे हैं उन बेरोजगारों को कैसे रोजगार देकर लोगों का सम्पूर्ण जीवन संवारा जायेगा, इसके बारे में अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया है। स्पीकर सर, अभी एक माननीय सदस्य विनोद शर्मा जी ने चुनावी वायदों का जिक्र किया। मैं चुनावी वायदों पर तो बाद में आऊंगा लेकिन अभिभाषण में आर्थिक मंदी की भी बात की गई है। अभिभाषण के शुरू में कहा गया है कि आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक मंदी है और अगर देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है तो प्रदेश का भी आर्थिक मंदी से गुजरना स्वाभाविक है। प्रदेश भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। आर्थिक मंदी के क्या कारण हैं यह कहीं नहीं बताया गया है। आर्थिक मंदी की परिभाषा भी नहीं दी गई है सिर्फ आर्थिक मंदी का जिक्र किया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए सरकार के असफल प्रयास होते हैं कि अपनी असफलताओं को कैसे छिपाया जाये। हरियाणा सरकार ने भी अपनी असफलताओं को छिपाने के भरपूर प्रयास किए हैं लेकिन असफलताओं को छिपाना बहुत मुश्किल है। इन्हीं कारणों से बेकारी और भुखमरी बढ़ रही है और किसान आत्महत्यायें कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे एक रिपोर्ट पढ़ने को मिली जिसमें बताया गया था कि देश में 17 हजार किसानों द्वारा आत्महत्यायें की गई हैं। कांग्रेस पार्टी की जो राज्य और केन्द्र सरकार किसानों का मसीहा होने का दावा करे, उसके राज में किसानों द्वारा आत्महत्यायें करना बड़ी चिंता की बात है। विवश लोग सरकार से जो उम्मीदें करते हैं कांग्रेस के लोग उनको कैसे पूरा कर सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, आज आर्थिक मंदी का रोना रोया जा रहा है। आर्थिक मंदी का मतलब अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है सिवाय इसके और कुछ भी नहीं है। आर्थिक मंदी का मतलब होता है उत्पादित वस्तु का मूल्य कम हो जाना और जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनका बहुतायत हो जाना। देश में इतनी मात्रा में वस्तुएं हों कि उनको कोई खरीदने वाला ही नहीं हो। मैं तो समझता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। आज कहीं नहीं लग रहा कि देश में जो उत्पादित वस्तु हैं उनकी कीमत कम है या कहीं पर ऐसा भी नहीं लग रहा कि आर्थिक मंदी के नाम पर जो चीजें हैं वे बहुतायत में हैं और हमें खुले तौर पर मिल रही हैं। लेकिन फिर भी एक ढकोसला बनाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री और यू०पी०ए० अध्यक्ष सोनिया गाँधी को धन्यवाद दिया जाता है कि हमने इस आर्थिक मंदी पर कंट्रोल कर लिया है। आर्थिक मंदी के नाम पर पैकेज दिये जा रहे हैं। लेकिन वे पैकेज भी बड़े-बड़े उद्योगपतियों को दिये जा रहे हैं न कि किसी गरीब किसान को। यह हकीकत भी है और सभी जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, गरीब आदमी और गरीब किसान के लिए उनके दिल में कोई जगह नहीं है। किसानों के लिए यह सिर्फ

ढकोसला करती है और किसान के लिए कुछ काम नहीं करती। मैं मजदूर का बेटा हूँ, मजदूर तो किसान के खेत में काम करता है और मुझे पता है कि किसान के खेत में कैसे काम किया जाता है। आर्थिक मंदी अगर देखने को मिली है तो यहाँ बड़े-बड़े शेयर बाजारों पर देखने को मिली है। शेयर बाजार में तो आर्थिक मंदी देखने को मिली है या बड़े औद्योगिक घरानों पर मंदी का असर पड़ा है। बड़े औद्योगिक घरानों को देश में 1,50,000 करोड़ रुपये की हानि देखी गई है इसमें दो राय नहीं या म्यूच्यूअल फण्ड में मंदी देखी गई है। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया था कि जितने भी सरकारी बैंक्स हैं अप्रैल से लेकर दिसम्बर, 2008 तक उन्होंने मुनाफा कमाया है और उसके बावजूद भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको आर्थिक पैकेज दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, 3 लाख हजार करोड़ रुपये के करीब रिजर्व बैंक ने सिर्फ बैंकों को पैकेज दिया है जबकि बैंक मुनाफा कमा रहे थे। आर्थिक मंदी का रोना रोने वाले लोगों को बता रहा हूँ कि कांग्रेस सरकार ने आर्थिक मंदी के लिए क्या किया है? स्पीकर सर, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये जो लाभ कमाने वाले बैंक हैं उनको रिजर्व बैंक ने कैसे पैकेज दे दिया, यह कोई आर्थिक प्रबन्धन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इंदौरा जी, आप पार्लियामैंट में बोल रहे हैं या असैम्बली में बोल रहे हैं?

डॉ० सुशील इन्दौरा : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो शुरुआत में बात कही गई है मैं उसी पर बोल रहा हूँ। अगर शुरू में आप कुछ पन्ने पलट कर देखें तो यही बातें लिखी हुई हैं। मैं भी वही बात कहते हुए हरियाणा की ओर आ रहा हूँ कि ऐसे आर्थिक प्रबन्धन का दावा करने वाली यह हरियाणा प्रदेश की सरकार है, वह भी इस तरह की गतिविधियों से अछूती नहीं है। इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश की जो आर्थिक कहानियाँ घड़ी जा रही हैं जैसे कहा गया है कि वर्ष 2007-08 में प्रति व्यक्ति आय 58531 रुपये आंकी गई है। **(इस समय सभापतियों की सूची में से एक माननीय सदस्य श्री कर्ण सिंह दलाल पदासीन हुए)** सभापति महोदय, वर्ष 2007-08 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) का आकलन 1,53,087 करोड़ रुपये किया गया जबकि वर्ष 2006-07 में यह 1,30,033 करोड़ रुपये था और वर्तमान मूल्यों पर 17.7 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। जो पर कैपिटा इन्कम दिखाई गई है वह औसतन तो दिखाई गई है लेकिन उसमें यह तो बताया ही नहीं है कि कौन इससे नीचे है और कितने परसैंट लोग इससे ऊपर हैं। मेरी मान्यता है कि अगर हम सही आकलन करें और सही ढंग से देखें तो पर कैपिटा इन्कम में हरियाणा आगे नहीं है जबकि सरकार कहती है कि गोवा के बाद हमारा दूसरा नम्बर है। हम इस बात को मान भी लें तो पर कैपिटा इन्कम में कितने ऐसे लोग हैं इसकी कोई दर भी नहीं बताई गई है। थोड़े से लोग हो सकते हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी लेकिन ज्यादातर लोग गरीब हैं फिर भी हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम नम्बर एक हैं। चेयरमैन साहब, दूसरी बात यह है कि मैं हरियाणा न्यूज देखता हूँ और हरियाणा न्यूज में पर कैपिटा इन्कम भी आती है। दूसरी जगहों से भी आंकड़े आते हैं मैं उनका भी जिक्र करूंगा। बड़े दावे के साथ ये लोग उंगली उठा कर यह कहते हैं कि हरियाणा नम्बर वन पर है लेकिन हरियाणा नम्बर वन पर कहां से है? जिस प्रदेश में किसान को वक्त पर खाद नहीं मिलती, जिस प्रदेश में किसानों की लागत

[डॉ० सुशील इन्दौरा]

मूल्य बीज से ज्यादा है वह हरियाणा प्रदेश किस प्रकार से नम्बर वन पर आ पाएगा? चेयरमैन सर, बड़े दावे किये जाते हैं कि इतनी बिजली पैदा कर दी। बिजली के बारे में मैं थोड़ी देर में आता हूँ। चेयरमैन सर, मैं यह कहना चाहता था कि इस पर कैपिटा इन्कम का क्या फायदा हुआ है। इसमें अधिक से अधिक भरमार उन लोगों की है जिनकी इन्कम 8800 से भी कम है वे लोग अपने बच्चों को शिक्षा कहां से दिलवाएंगे क्या उनके लिए सरकार ने कोई इन्तजाम किया है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान दिया है। ऐसे बच्चे जिनकी आमदनी कम है वे अपने अभिभावकों को जीवनयापन के साधन कैसे मुहैया करवा पाएंगे, कैसे उनकी देख-रेख कर पाएंगे? यह सब कैसे होगा? जिन बेचारों के पास झोंपड़ी तक नहीं है और सिर ढंकने तक के लिए छत नहीं है इस मंहगाई के दौर में वे लोग अपने सिर छिपाने के लिए किस प्रकार से झोंपड़ी तैयार कर पाएंगे यह तो सरकार ने बताया ही नहीं। बड़े दावे के साथ एक बात कह दी कि हरियाणा देश में नम्बर वन है और पर कैपिटा इन्कम में हरियाणा दूसरे नम्बर पर है। चेयरमैन सर, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि ये लोग गरीबों की बात करते हैं। हरियाणा प्रदेश की सरकार और केन्द्रीय सरकार इस देश का हिस्सा है। अगर यहां पर हम केन्द्र सरकार की बात कर रहे हैं तो कृषि के नाम पर सरकार ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहे देश में हो चाहे प्रदेश की हो ये लोग राजनीतिक रोटियां सेंकने में कोई गुरेज नहीं करते हैं। चेयरमैन सर, ये लोग कोई न कोई ऐसा शोशा छोड़ देते हैं जिससे किसान को फायदा कम होता है और उसके बीच के दलालों को ज्यादा फायदा होता है। आज अगर हम सही मायनों में देखें तो किसान को जो सुविधाएं मिलनी चाहिएं वह नहीं मिल रही हैं। अगर खाद की बात करें तो किसान को खाद वक्त पर नहीं मिलता। अभी हमारे साथी उदय भान जी यह कह रहे थे कि तीन नहरें लगती हैं लेकिन टेल पर आज तक पानी नहीं पहुंचा है। जब जरूरत होती है तो खाद के वक्त खाद नहीं और बीज के वक्त किसान को बीज नहीं मिलता। यहां तक कि जब बेचारा किसान डीजल से अपनी फसल पकाने का काम कर रहा होता है तो वह भी समय पर नहीं मिलता है। चेयरमैन सर, इस प्रकार से किसान का भला कैसे होगा? अगर हम आंकड़ों में देखें तो हमें सबसिडी के नाम पर क्या मिलता है? केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही सबसिडी की बात करें तो सबसिडी का असर सीधे हरियाणा सरकार पर भी पड़ता है। सबसिडी के नाम पर करोड़ों रुपये दिये जाते हैं लेकिन किसान को उसका कोई फायदा नहीं मिलता है। करोड़ों रुपये की सबसिडी दी जाती हैं लेकिन उसमें हमने किसानों के लिए कभी यह प्रयास नहीं किया कि किसान की जो फसल है उसका लागत मूल्य कम हो और जो उसकी उपज है उसके भाव को बढ़ाने का काम करते। हमने पिछली बार 46 रुपये कपास का समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम किया था। केन्द्र सरकार समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसान की आस जगा देती हैं कि सरकार कुछ तो देगी। चाहे गेहूं की बात हो चाहे दूसरी फसलों की बात हो, लेकिन उस आस में मिलता क्या है। अभी यहां पर ये कह रहे थे कि हमने पूसा धान पर प्रतिबन्ध हटा दिया आज 100 रुपये की जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी वह घटा दी लेकिन इससे किसानों को क्या मिला। किसान के हाथ से निकल कर वह धान तो अब बिचौलियों के हाथ में चला गया है तो आपने एक्सपोर्ट ड्यूटी घटा दी और वाहवाही लूट ली लेकिन यह ड्यूटी तो किसानों का

भला नहीं कर सकती है। आपने उस वक्त प्रतिबंध हटाया जब उसके भाव गिर गए थे। आज आप मुच्छल धान का भाव जाकर पूछो। (विघ्न) किसानों की जीरी किस भाव में बिकी थी, आप वह भी देख लें और आज किस भाव में बिक रही है वह भी देख लें। आज जीरी को 1300-1400 रुपए प्रति क्विंटल में भी कोई नहीं पूछता है। किसानों ने अपनी जीरी को अपने घरों में इसलिए रखा था कि शायद दाम बढ़ जाएं। उन्होंने उसको अपने घरों में तूड़ी की तरह रखा था लेकिन उसका उनको कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने गीली जीरी घरों में रख ली थी और वह भी सूख कर आधी हो गई लेकिन उनको उसका कुछ भाव नहीं मिला और आज यह सरकार किसानों के भले की बात करती है। चेयरमैन सर, कृषि विशेषज्ञों की जो रिपोर्ट है मैं उसके अनुसार बताना चाहता हूँ कि गेहूं पर प्रति एकड़ लागत 22,700 रुपए थी और बिकी 18,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से। यानि कि किसान को 4,700 रुपए प्रति एकड़ का नुकसान हुआ है। अगर धान की बात की जाए तो किसान की प्रति एकड़ लागत 27,265 रुपए आती है और आमदनी 25,000 रुपए प्रति एकड़ होती है। चेयरमैन सर, ऐसे कैसे चलेगा। हमने कभी प्रयास नहीं किए कि उनको अच्छे दाम मिलें। चेयरमैन सर, खास करके गेहूं की फसल है, चावल की फसल है उसके अच्छे दाम किसानों को मिलने चाहिएं। इस सरकार ने अपने अभिभाषण में कहा था कि हमने इतने मीट्रिक टन ज्यादा गेहूं और धान पैदा किया है। लेकिन मैं इनको यह कहना चाहता हूं कि उत्पादन दर तो नहीं बढ़ी है। उत्पादन दर तो कम हुई है। आज सरकार ने उत्पादन दर को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया है। चेयरमैन सर, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में नहीं हैं, वे कुछ करोड़ रुपए सोनिया गांधी जी से माफ करवाकर ले आए और सोनिया गांधी जी के कंधे पर हल रख कर कह देते हैं कि सोनिया जी किसानों की सबसे बड़ी हितैषी हैं। बेचारी सोनिया को क्या पता कि कनक क्या होती है, चने क्या होते हैं। उनको तो यह पता है कि यह आटा है, यह कनक का है या चने का है। यह भी उनको पता नहीं होगा वे तो कोई और आटे की रोटियां बनाते होंगे। तो ऐसे में किसानों का भला नहीं हो सकता है। चेयरमैन सर, अगर सरकार सही मायने में किसानों का भला करना चाहती है तो यह जो खाद की काला-बाजारी है, पहले इसको बंद करना होगा। यह जो बीज के कट्टे टाईम पर नहीं मिलते हैं उनको पूरा करना होगा और समय पर किसानों को देना होगा। दूसरे जो सिंचाई के पानी की बात यहां पर आई मैं उस बारे में कहना चाहूँगा। अब विनोद शर्मा जी यहां पर बैठे हुए नहीं हैं वे सदन में कह रहे थे कि एस०वाई०एल० कैनाल का पानी हमारी पार्टी नहीं लाई है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर एस०वाई०एल० नहर का पानी हरियाणा में कोई लाएगा तो चौधरी देवी लाल जी के पद चिन्हों पर चलते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ही लाएंगे यह कांग्रेस के बस की बात नहीं है। मैं तो यह कहता हूँ कि कांग्रेस के लोगों ने सिर्फ एस०वाई०एल० कैनाल के नाम पर एक विवाद खड़ा कर दिया है। इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। इनकी सरकार के वक्त के चार साल के अभिभाषणों को मैं पढ़ रहा हूँ। आखिरी साल में शायद इस सरकार का एक और अभिभाषण आएगा। उसके बाद आएगा कि नहीं आएगा। (विघ्न)

श्री नरेश कुमार प्रधान : चेयरमैन सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से अपने साथी से जानना चाहता हूँ कि ये जो इतना इतरा कर किसानों

[श्री नरेश कुमार]

की बात कर रहे हैं क्या ये वही लोग नहीं हैं जिन्होंने किसानों से वायदे किए थे कि जब भी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार आएगी तो न मीटर रीडर होगा न ही मीटर होंगे? जब इनकी सरकार आई तो किसानों ने इनको इनका वायदा याद दिलवाया कि माननीय चौटाला साहब आपने यह वायदा किया था कि जब आपकी सरकार आएगी तो बिजली के बिल माफ कर दिए जाएंगे। तो इन हत्यारों ने बिजली बिल माफ करने की बजाए, किसानों का भला करने की बजाए उन पर गोलियों की बौछार करवा दी थी। इस बारे में आज जनता जानती थी और गली-गली में यह आवाज उठती थी "वाह रे चौटाला तेरा कानून, पानी महंगा सस्ता खून।" आज ये किस मुंह से यहां पर किसानों के भले की बात कर रहे हैं। आज इनसे शर्म भी शर्मा रही है। ये यहां पर बोलते हुए सोनिया जी तक पहुंच गए। छोटा मुंह बड़ी बात करते हैं। जिस सोनिया गांधी ने 60,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्जा माफ करवाया उसके ऊपर ये कटाक्ष कर रहे हैं। चेयरमैन सर, इनके लिए बड़े शर्म की बात है। इनसे तो शर्म भी शर्मा रही है। पता नहीं किस मुंह से ये बात कर रहे हैं, कौन से गंगा जल में ये मुंह धोकर आते हैं? ओम प्रकाश चौटाला जी ने चुनाव जीतने के लिए तीन-तीन साल के बच्चों पर सदन के अंदर गोलियां चलवा दी थीं लेकिन आज ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं। आज अखबारों में कई कई पेजों पर जन आक्रोश यात्रा के बारे में इन्होंने विज्ञापन दे रखे हैं। क्या ये उस जन आक्रोश को भूल गए जब इनकी सरकार के वक्त बहादुरगढ़ के अंदर पांच-पांच साल की बच्चियों का रेप कर उनको कुचल दिया जाता था और उनकी हत्या कर दी जाती थी? वाहवाही लूटने के लिए यह कह कर कि हमने हत्यारों को पकड़ा है, राह चलते पागलों पर मुकदमें बनवा दिए जाते थे लेकिन आज ये किसान की बात कर रहे हैं, जन आक्रोश की बात कर रहे हैं। क्या लोग यह भूल गए कि इनकी सरकार के वक्त में दुलीना के अंदर चार-चार हरिजन के बच्चों को जिंदा जलवा दिया गया था तब जन आक्रोश करने वाले कहां गये थे? क्या हरियाणा के लोग उस बात को भूल जाएं? आज किस मुंह से ये इतरा रहे हैं। बड़े दुख की बात है बड़े शर्म की बात है। (विघ्न)

डॉ० सुशील इन्दौरा : चेयरमैन सर, क्या प्वायंट ऑफ आर्डर इतना लम्बा होता है? (विघ्न)

श्री रामफल चिड़ाना : चेयरमैन सर, आप मेरी बात सुनें। (विघ्न)

श्री सभापति : चिड़ाना साहब, आप बैठिए क्योंकि आपके नेता अपनी बात कहने लग रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप अपनी बात पूरी करिए।

डॉ० सुशील इन्दौरा : सभापति महोदय, अगर प्वायंट ऑफ आर्डर इतना ही लम्बा होगा तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मुझे दिक्कत नहीं है। आप मेरे से पहले उनको भाषण दिलवा दीजिए मुझे कोई ऐतराज नहीं है। प्वायंट ऑफ आर्डर तो केवल क्लैरिफिकेशन के लिए होता है। सरकार में चमचों की कमी नहीं होती है और चमचों का इलाज मेरे पास नहीं है। (विघ्न)

श्री सभापति : वे आपके लिए कुछ नहीं कह रहे हैं।

डॉ० सुशील इन्दौरा : सभापति महोदय, वे मेरे लिए तो नहीं कह रहे हैं लेकिन जिस

किसी के लिए भी वे कह रहे हैं उससे एक प्रकार की झलक तो मिलती ही है। सर, मैं यह कह रहा था कि यह बात हकीकत है और सारा देश इस बात को जानता भी है कि अगर कोई किसान के हित की बात करता था तो उसका नाम चौधरी देवीलाल ही है। अगर यह सच नहीं है तो आप बताओ। चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा किसानों के लिए लड़ाई लड़ी। किसानों की बहुत सी स्कीम्ज चौधरी देवीलाल जी ने चलायीं। चाहे ओलावृष्टि का मुआवजा देने की बात हो, चाहे और कोई बात हो, चौधरी देवीलाल जी ने ही किसानों के लिए यह स्कीम शुरू करवायी। चाहे एक आना देकर उन्होंने इस स्कीम को शुरू किया लेकिन शुरू तो करवाया। इन्होंने बुढ़ापा पेंशन 500 रुपये करने की बात कही थी लेकिन एक अठन्नी भी नहीं बढ़ायी। सर, मैं यह कह रहा था कि एस०वाई०एल० कैनाल हरियाणा प्रदेश के लिए जीवन रेखा है। उसका पानी लाना हर सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। जहां तक मेरी जानकारी है कि एस०वाई०एल० कैनाल के निर्माण का कोई मामला आज भी कोर्ट में लम्बित नहीं है। ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के प्रयास ही थे कि वर्ष 2002 में कोर्ट से यह निर्णय हुआ था कि एक साल के अंदर पंजाब सरकार यह नहर बनवाएगी और अगर एक साल के अंदर पंजाब सरकार यह नहर नहीं बनवा सकती तो केन्द्रीय सरकार किसी केन्द्रीय एजेंसी के माध्यम से यह नहर बनवाएगी। अगर निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा फिर पानी तो आ ही जाएगा। सभापति महोदय, मैं इस बात को नहीं कहता। 19 दिसम्बर, 1991 को तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी ने हरियाणा विधान सभा में खुलकर स्वीकार किया था कि एस०वाई०एल० कैनाल पर अगर सबसे ज्यादा काम हुआ है तो वह चौधरी देवीलाल जी की सरकार के समय में हुआ है। उन्होंने यह भी कहा था कि मेरी चौधरी देवीलाल जी से कोई दोस्ती नहीं है कि मैं दोस्ती में यह कह रहा हूँ। चौधरी बंसीलाल जी की एक आदत थी कि वे सही बात को सही बात कहते थे इसलिए उन्होंने कहा था कि एस०वाई०एल० कैनाल पर अगर सबसे ज्यादा काम हुआ है तो वह चौधरी देवीलाल जी के टाईम में ही हुआ था। एस०वाई०एल० कैनाल की अगर पैरवी हुई है तो वह ओम प्रकाश चौटाला जी के टाईम में हुई है। कांग्रेस के लोग सिर्फ और सिर्फ विवाद पैदा करने का ही काम करते हैं।

Shri Tejender Pal Singh Mann : Chairman Sir, I have a point of order. यह जो देवी लाल जी वाली बात कही है, यह गलत है। मैं भी उस समय सदन का सदस्य था लेकिन उस समय चौधरी बंसी लाल जी ने यह नहीं कहा था कि देवी लाल जी के समय में इस बारे में कुछ हुआ था। बंसी लाल जी उन दिनों कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे और शमशेर सिंह सुरजेवाला जी उस समय इरीगेशन एवं पॉवर मिनिस्टर थे। उस समय उन्होंने सारे पंचों को, सरपंचों को बैंक्स में ले जाकर नहर का कंस्ट्रक्शन दिखाया था and which was almost 90% completed. Indoraji must make this correction in his record. यह रिकॉर्ड की बात है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : सर, यह भी रिकॉर्ड की बात है जो मैं बता रहा हूँ।

शिक्षा मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता) : जो मान साहब कह रहे हैं यह भी रिकॉर्ड की बात है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : आप रिकॉर्ड निकलाकर देख लें यदि मेरी बात सच नहीं होगी तो मैं इनकी बात मान लूंगा। यह हकीकत है कि पैरवी की है तो ओम प्रकाश चौटाला साहब ने की है। देश के लोग और प्रदेश के लोग इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस ने तो सिर्फ विवाद पैदा करने का काम किया। उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि हांसी-बुटाना लिंक चैनल बनवाकर विवाद पैदा कर दिया। पानी का समान बंटवारा ही करना था। यह बात तो सारा प्रदेश कहता है, कौन इसके लिए मना करता है लेकिन नहर बनाकर प्रदेश का 500-700 करोड़ रुपया बेफिजूल खर्च कर दिया गया है। उस समय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी कहां गए थे? चाहिये तो यह था कि दूसरे राज्यों की सरकारों के साथ बैठक करके पहले उस मामले को सुलझाते कि हमने पानी लेना है। (विघ्न)

सिंचाई मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : चेयरमैन सर, इंदौरा जी पहले यह बताएं कि ये बी०एम०एल० हांसी बुटाना के हक में है या खिलाफ हैं? इनके नेता जनाक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने यह कहा है कि यदि बी०एम०एल० हांसी-बुटाना लिंक नहर बन जाती है तो हरियाणा में गृह युद्ध हो जाएगा। ये इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं। खुद पीछे होकर बादल को आगे कर रखा है और पीछे लोकदल के ये लोग हैं। ये नहीं चाहते कि जो हरियाणा की असली जीवन रेखा है जिसके बनने से 16 जिलों को लाभ होगा, वह बने। यह आज उसकी निंदा कर रहे हैं। इनको थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। इनको प्रदेश के हित की कोई चिंता नहीं है।

डॉ० सुशील इन्दौरा : हम पूरी चिंता करेंगे।

Mr. Chairperson : No running commentaries, please.

कैप्टन अजय सिंह यादव : बी०एम०एल० हांसी-बुटाना लिंक नहर हरियाणा की असली जीवन रेखा है जिसके बनने से 16 जिलों को लाभ होगा। इस नहर का बनना निहायत जरूरी था। हमने अपने इलैक्शन मैनीफैस्टो में भी कहा था कि हम पानी का समान बंटवारा करेंगे।

Mr. Chairperson : No running commentaries, please.

कैप्टन अजय सिंह यादव : सभापति महोदय, इन्होंने कोई भी ऐसी कार्यवाही नहीं की जिससे पानी का समान बंटवारा हो सके। नारनौल में पीने के पानी की बहुत कमी है। रिवाड़ी, फरीदाबाद और मेवात के इलाके में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं इन्होंने उसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इन्होंने उस समस्या के हल के लिए कुछ करने की बजाय लिटिगेशन डाली जिसके परिणामस्वरूप ये हाईकोर्ट में भी औंधे मुंह पड़ गए और सुप्रीमकोर्ट में भी औंधे मुंह पड़ेंगे। (विघ्न) नहर तो बनेगी ही और पानी का समान बंटवारा भी होगा।

डॉ० सुशील इन्दौरा : मैं खुले शब्दों में एक बात कहना चाहता हूँ कि पानी के समान बंटवारे के हक में सारा प्रदेश है। हर आदमी इसके हक में है लेकिन पानी का समान बंटवारा करें तो सही। ये लोग बंटवारा करने की बजाय विवाद पैदा करते हैं। मुख्यमंत्री

जी और मंत्री जी कहां गए थे जब बैठकें हो रही थीं। पहली बैठक में ही भाखड़ा को पंक्चर करने की परमीशन क्यों नहीं ली। बजाय उसके कोर्ट में कहते हैं कि हमें तो पीने का पानी दे दो हम लिफ्ट से उठा लेंगे। (विघ्न) यह हाल है सरकार का जो कोर्ट में जाकर कहती है कि हमें तो पीने के लिए पानी दे दो, हम पम्प लगाकर लिफ्ट से पानी उठा लेंगे। सभापति महोदय, अगर सरकार अच्छे कार्य करेगी तो मैं कहता हूँ कि मैं उसका समर्थन करूंगा। लेकिन ये कुछ करके तो दिखायें। हाईकोर्ट के मामले में सरकार एक प्रस्ताव लेकर आई थी अगर हमने उस प्रस्ताव का समर्थन न किया हो तो बताएं। हमने उस प्रस्ताव का खुले दिल से समर्थन किया था। सरकार कोई भी प्रस्ताव लेकर आये मैं कहता हूँ कि अपनी पार्टी की तरफ से दावा कर रहा हूँ कि अगर एस०वाई०एल० बनाने की बात है तो चलो मेरे साथ सारे विधायक चलो हम कार सेवा करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन सरकार विवाद पैदा करने के लिए अगर यह काम करती है तो हम उसे कैसे बर्दास्त करेंगे। फिर ये कहते हैं कि जनआक्रोश रैली में कहा है। यह बात तो शायद पहले कभी कही हो। लोगों में इस बात का आक्रोश है। जब चुनाव में ये लोग जायेंगे तब पता चलेगा कि आक्रोश हमारे प्रति है या सरकार के प्रति है। यह जन आक्रोश रैली लोगों की मांग थी। लोग अजय सिंह चौटाला जी के पास गये और कहा कि इस सरकार ने हमारी बहुत बर्बादी कर दी है प्रदेश की बहुत बर्बादी कर दी है। इस सरकार ने बुरा हाल कर दिया है, न कानून व्यवस्था है न कोई और चीज है इसलिए इस सरकार से बचाओ और लोगों को साथ लेकर चलो।

श्री विनोद कुमार शर्मा : सभापति महोदय, माननीय इन्दौरा जी जन आक्रोश का पता करना चाहते हैं किसके खिलाफ है तो मैं इनको खुला न्यौता देता हूँ कि ये आयें और आकर अभी चुनाव लड़ लें। दूर तक जाने की क्या जरूरत है हम इन्तजार करने को तैयार नहीं हैं। ये कल आ जायें भेजो अपने नेता को मेरे खिलाफ चुनाव लड़ ले, मैं तैयार हूँ।

डॉ० सुशील इन्दौरा : सभापति महोदय, चुनाव तो आ गये।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सभापति महोदय, शर्मा जी ने जो ऑफर दी है इससे फेयर ऑफर और क्या हो सकता है। ये चौटाला जी को कहें कि वे इस्तीफा दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : डॉ० सीताराम जी, आप किस की इजाजत से बोल रहे हैं। Dr. Sita Ram Ji, no running commentary, first you should seek permission from the chair and then speak. Dr. Indora, countinue your speech.

डॉ० सुशील इन्दौरा : सभापति महोदय, ये चुनाव तो आने वाले ही हैं, कांग्रेस के लोगों को पता चल जायेगा कि उनकी क्या हस्ती है। जब जनता इनके पीछे होगी तो ये लोग भागते नजर आयेंगे।

श्री सभापति : डॉ० इन्दौरा जी, आप पांच मिनट में अपनी स्पीच खत्म कीजिए।

डॉ० सुशील इन्दौरा : सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जी जिस स्टेज पर जाते थे एक बात

[डॉ० सुशील इन्दौरा]
ही कहते थे कि अगले तीन साल में हरियाणा प्रदेश को पूरी बिजली दे दूंगा। आज हालात क्या हैं। क्या मुख्यमंत्री जी बतायेंगे कि आज प्रदेश में बिजली के हालात क्या हैं?

श्री सभापति : डॉक्टर साहब, आप अपनी सुजैशन दीजिए और पांच मिनट में अपनी स्पीच को कन्क्लूड कीजिए।

डॉ० सुशील इन्दौरा : सभापति महोदय, बिजली की हालत यह है कि आज लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। सरकार कहती है कि बिजली के प्लांट लग रहे हैं। मैं आपको बताऊं सर, कि बिजली के जो लौसिज़ हैं, आज प्रदेश में बिजली की जो पैदावार है, अगर उसका उचित प्रबन्धन कर दिया जाए और उसका ठीक वितरण कर दिया जाए तो ऐसे हालात नहीं रहेंगे। हर बार लांछन लगा दिए जाते हैं कि पिछली सरकार ने यह किया। चौधरी देवीलाल जी की नीतियों की सरकार तो 11 साल तक थी।

श्री सभापति : आप अपने सुजैशन दीजिए। आप पार्लियामेंटरियन भी रहे हैं।

डॉ० सुशील इन्दौरा : सभापति महोदय, मैं भूमिका बांधता हूँ उससे पहले ही आप मेरी बात को काट देते हैं तब मेरा दिमाग कहीं और चला जाता है। हमारी सरकार पर यह लांछन लगाया गया है कि पिछली सरकारों ने बिजली के मामले में कुछ नहीं किया। हकीकत यह है कि यमुनानगर का जो प्लांट अभी सरकार ने शुरू किया है उसकी शुरुआत चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी ने की थी। इसका श्रेय ये ले लें इन्हें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हरियाणा प्रदेश को बिजली तो दो। उसका श्रेय इन लोगों ने लेने की कोशिश की और फायदा बड़े घराने को भी पहुँचाने का काम किया। (विघ्न) इन्होंने उसका श्रेय लेने का काम किया। (विघ्न)

Mr. Chairperson : No running commentary, let him complete. डॉ० साहब, आपके पांच मिनट बाकी हैं आप अपने सुझाव दीजिए और अपनी स्पीच को कन्क्लूड कीजिए।

डॉ० सुशील इन्दौरा : सभापति महोदय, अगर प्रदेश की बात मुझे कहने की इजाजत नहीं दी जाती है तो मैं बैठ जाता हूँ। मैं सुझाव ही दे रहा हूँ, सर। अगर आप मुझे इजाजत नहीं देते हो तो जब आप कहेंगे मैं एक सैकेण्ड में उसी समय बैठ जाऊंगा। I will not take even a single second और मैं बैठ जाऊंगा।

Mr. Chairperson : Indora ji, don't waste your time, please give your suggestions.

डॉ० सुशील इन्दौरा : सभापति महोदय, अगर आप यहां पर हमें बोलने नहीं देंगे तो हम प्रदेश की जनता के सामने जाकर बोलेंगे। मैं बिजली की ही बात कह रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब यह नहीं कहते। सरकार को आज बने हुए कितने साल हो गये, चार साल हो गये हैं। जब सरकार बनी तो मुख्यमंत्री जी हर स्टेज से कहते थे कि बिजली दे दूंगा, बिजली दे दूंगा। जो लाइन लौसिज हैं अगर उसको आप देखें तो कई

फीडर्ज ऐसे हैं जिनमें लाइन लोसिज 98 फीसदी से ज्यादा हैं। ये आंकड़े इनकी रिपोर्ट के मुताबिक हैं। 14 फीडर्ज ऐसे हैं जिनमें 90 फीसदी लाइन लोसिज हैं। 48 फीडर्ज ऐसे हैं जिनमें 70 से 90 फीसदी लाइन लोसिज हैं। बिजली मंत्री जो यहां बैठे हैं और ध्यान से सुन रहे हैं कि कायदे कानून के हिसाब से 25 परसैंट से ज्यादा लाइन लोसिज होना ठीक नहीं है। 280 फीडर्ज ऐसे हैं जिनमें 50 फीसदी लाइन लोसिज हैं। ये लाइन लोसिज क्यों हैं, ये लाइन लोसिज इसलिए हैं क्योंकि कृषि के लिए बिजली मिलती नहीं और लाइन लोसिज का सारा बोझ बिना मीटर्ज के जो कनैक्शंज हैं, उन पर डाल दिया जाता है। ये लाइन लोसिज कृषि वालों के नहीं हैं बल्कि यह मिली भगत से होता है। अधिकारी बड़े-बड़े उद्योगपतियों से मिलकर चोरी करवाते हैं। सभापति महोदय, इस चोरी को बन्द करवाओ। ये लाइन लोसिज किसान पर डाल देते हैं कि कृषि के क्षेत्र में खपत हो गई। बेचारा किसान वैसे ही मारा जाता है और आंकड़े आ जाते हैं। आंकड़ों में लिख दिया जाता है कि कृषि के क्षेत्र में इतनी बिजली दी गई। हम सवाल पूछते हैं कि कितनी बिजली दी गई, कहा जाता है कि इतनी बिजली दी गई जबकि मिला कुछ नहीं और सरकार की वाह-वाह और बल्ले-बल्ले हो जाती है। किसान बेचारा रोता रहता है और इधर ये लोग पैसे बनाते रहते हैं, ठगी करते रहते हैं। सभापति महोदय, इस चीज को रुकवाइए। बिजली के लाइन लोसिज कम हों, ऐसे प्रबन्ध किए जाएं। बिजली के रेट नहीं बढ़ने चाहिएं। बिजली महंगी होगी तो किसान की उत्पादन लागत बढ़ेगी, उद्योगों की लागत बढ़ेगी और हर चीज की लागत बढ़ेगी। सस्ती बिजली पैदा करने के लिए हमारी सरकार को कोशिश करनी चाहिए। सभापति महोदय, ये स्टेजों पर जाकर झूठे दावे करते हैं कि बिजली के चार प्लांट लगा दिए। खेदड़ का प्लांट लगा दिया, झाड़ली का प्लांट लगा दिया। झाड़ली के प्लांट में दिल्ली का डिस्प्यूट है जो कभी भी सुलझ नहीं सकता। सभापति महोदय, मैं एक दिन झाड़ली प्लांट के बारे में अखबार में पढ़ रहा था कि दिल्ली वालों ने कह दिया कि हम इस प्लांट के लिए पैसा नहीं देंगे। सभापति महोदय, वे पैसा नहीं देंगे तो ये प्लांट कैसे पूरा होगा। ये 2011 की बात कहते हैं, 2011 में इनको कौन आने देगा।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं एक क्लैरीफिकेशन करना चाहता हूँ। वैसे तो बाकी जो बात है वे यह कह सकते हैं। झाड़ली के दिल्ली विवाद की बात इन्होंने की तो मैं सदन में कहना चाहता हूँ कि अगर दिल्ली बिजली नहीं लेगा तो 750 मेगावाट जो उनका हिस्सा है वह भी हम रख लेंगे, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हम पूरा पैसा देंगे और सरकार के पास पूरा पैसा है।

श्री सभापति : इन्दौरा जी, आप 3 मिनट में कन्क्लूड करें।

डॉ० सुशील इन्दौरा : सभापति महोदय, अभी तो मेरे पास सरकार के बहुत मुद्दे हैं अगर सब मुद्दों को गिनाने लगूं तो सारी रात हो जाएगी और इसके लिए हाउस की सिटिंग को एक्सटैंड करना पड़ेगा तभी बात बनेगी। (शोर एवं व्यवधान) सभापति महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। मेरा सुझाव बिजली के मामले में है। बिजली मंत्री जी बैठे हैं ये देखें कि आज बिजली की उत्पादन क्षमता कितनी है। आज हमारे बहुत से यूनिट बन्द पड़े हुए हैं। बिजली की उत्पादन क्षमता क्या है और उस उत्पादन क्षमता के अनुरूप

[डॉ० सुशील इन्दौरा]

हम बिजली पैदा कर पा रहे हैं या नहीं। अगर उसी हिसाब से बिजली पैदा कर लें तो प्रदेश के लोगों को पूरी बिजली मिल सकती है। कई बार तो हालात बहुत खराब हो जाते हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सभापति महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। माननीय सदस्य को अपनी बात कहने का अधिकार है और वे कह भी रहे हैं। मैं आपकी अनुमति से सदन को बताना चाहूँगा कि हरियाणा प्रान्त देश में अकेला ऐसा प्रान्त है जिसने वर्ष 2008 से शुरू करके वर्ष 2012 तक बिजली का एक नया कारखाना बनाने का निर्णय किया है। हम हरियाणा प्रदेश के किसान, गरीब, व्यापारी और मजदूर को बिजली देंगे। व्यापारी को बिजली देने में इनको ऐतराज हो सकता है लेकिन हमें कोई ऐतराज नहीं है। व्यापारी और दुकानदार भी हरियाणा प्रदेश के हिस्से हैं। हम हर व्यक्ति को बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बिजली का 600 मेगावाट का एक कारखाना यमुनानगर में चालू हो गया है। इस साल राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, खेदड़, जिला हिसार में चालू हो जायेगा जिसकी डॉक्टर साहब ने भी चर्चा की है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस प्लांट से इस साल में 1200 मेगावाट बिजली हरियाणा के गरीब, व्यापारी, किसान और दुकानदार को मिलेगी। इसके बाद हमें झाड़ली के पावर प्लांट से बिजली मिलनी शुरू हो जायेगी। माननीय सदस्य को शंका है कि इस पावर प्लांट पर कोई विवाद है। मैं इनको बताना चाहूँगा कि इस पावर प्लांट पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। इस पावर प्लांट के दोनों यूनिटों से क्रमशः जुलाई, 2010 और दिसम्बर, 2010 में हरियाणा के गरीब, किसान, व्यापारी और दुकानदार को बिजली मिलनी शुरू हो जायेगी। फिर वर्ष 2011 में महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट आ जायेगा और वर्ष 2012 में जो निजी क्षेत्र की और बिजली है वह भी आ जायेगी। इस प्रकार से वर्ष 2012 तक हरियाणा में 6 हजार मैगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन शुरू हो जायेगा। मुख्यमंत्री जी ने एक समय कहा था कि हम तीन से चार हजार यूनिट अतिरिक्त बिजली पैदा करेंगे लेकिन वायदे से बढ़कर आने वाले समय में उनके नेतृत्व में 6 हजार मैगावाट बिजली के उत्पादन का लक्ष्य 24 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पूरा करने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। 600 मैगावाट बिजली पैदा हो गई है और 1200 मैगावाट बिजली हम इस साल में पैदा करके दिखायेंगे। ये हमारा प्रयास है। जहां तक हमारे बंद पड़े यूनिटों का सवाल है, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे यूनिटस का जो पी०एल०एफ० इस साल आया है जब से पावर जैनरेशन कम्पनी अस्तित्व में आई अर्थात् जब से हरियाणा में बिजली के कारखाने लगे हैं तब से लेकर आज तक का सबसे ज्यादा है। चेयरमैन सर, हमारे कई यूनिट्स ऐसे हैं जो 103 और 104 परसैंट पी०एल०एफ० के ऊपर चले। चेयरमैन सर, इस बात के लिए आपको, मुझे और हरियाणा के अढाई करोड़ लोगों को फख्र होना चाहिए कि वे पावर प्लांट जो कभी 60 से 65 पी०एल०एफ० से ज्यादा नहीं गये आज वे 78 से 79 परसैंट एवरेज पी०एल०एफ० तक चलते हैं और कई ऐसे प्लांट हैं जो कि 101, 102, 103 और 104 परसैंट पी०एल०एफ० तक चले। यह अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है और आज तक ऐसा किसी अन्य सरकार के समय में नहीं हुआ। सभापति महोदय, मैं केवल जानकारी के आधार पर सम्मानित सदस्य को सूचित करना चाहता हूँ।

डॉ० सुशील इन्दौरा : सभापति महोदय, माननीय बिजली मंत्री जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ लेकिन इसके साथ इनको यह भी बताना चाहिए कि अगर हरियाणा में इतनी बिजली है तो फिर वह कहां गई और हरियाणा के लोग आज अंधेरे में क्यों बैठे हैं? ये यह क्यों नहीं बता पा रहे हैं?

श्री सभापति : इन्दौरा जी, प्रदेश में बिजली की कमी को दूर करने के लिए आप अपने सुझैशंज दें। आप इनको बताइए कि ऐसी हालत में इनको क्या करना चाहिए।

डॉ० सुशील इन्दौरा : सभापति महोदय, मैं अपने सुझाव भी दे रहा हूँ। जैसे मैंने लाईन-लॉसिज के बारे में बताया है कि यह अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार के कार्यकाल में 7 प्रतिशत लाईन-लॉसिज उत्तरी हरियाणा में और इसी प्रकार से तकरीबन 5 प्रतिशत लाईन-लॉसिज दक्षिणी हरियाणा में कम हुए हैं।

श्री सभापति : ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, माननीय सदस्य द्वारा जो भी प्वायंट्स उठाये जा रहे हैं उन्हें आप नोट कर लीजिए और उसके बाद आप कोई स्टेटमैंट देना चाहें तो आप दे दें। Mr. Indora, now you please conclude.

डॉ० सुशील इन्दौरा : सभापति महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। सरकार कहती है कि बिजली पानी के मुद्दे के अलावा कई और मुद्दे हैं और हम आने वाले चुनावों में विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। हरियाणा न्यूज़ पर एक गीत आता है कि तने राम की शूं। ये राम की शूं दिखाते-दिखाते सड़कें दिखाते हैं और अगर आप हरियाणा सरकार का वर्ष 2008 और 2009 का कैलेण्डर देखें तो उसमें तीन चीज़ें बड़ी प्राथमिकता के आधार पर दिखाई गई हैं। कैलेण्डर में सरकार का विज़न होता है कि सरकार दिखाना चाहती है कि हम क्या करना चाहते हैं। उसमें एक तो धुंआ उगलती हुई चिमनी दिखाई गई है, एक बड़ी सी नहर दिखाई गई है और सड़कें दिखाई गई हैं। अगर विकास की बात देखनी है तो आप मेरे क्षेत्र में चलें। मैं पिछले चार साल से लगातार कह रहा हूँ कि जाखल से कुलां तक सड़क बना दी जाये। उपरोक्त सड़क बनाने के लिए मुझे हर बार आश्वासन दे दिया जाता है लेकिन वह सड़क आज तक नहीं बनवाई गई है। सभापति महोदय, मैं सरकार पर यह भी आरोप लगाना चाहूँगा कि सरकार विधान सभा में माननीय सदस्यों को दिये गये आश्वासनों की कोई परवाह नहीं करती। हमें दिये गये आश्वासनों को कभी पूरा नहीं किया गया। आज तक हमारे पास कोई चिट्ठी नहीं आई। मंत्री जी की तरफ से एक बात कह दी जाती है कि मिल लेना और जब हम मिलने जाते हैं तो बताया जाता है कि मंत्री जी दौरे पर गये हैं। हम अपने आश्वासनों पर कार्यवाही करवाने के लिए कब तक मंत्रियों के पीछे-पीछे घूम सकते हैं। अगर विकास की बात की जाये तो मंगाला से टीटू खेड़ा तक की सड़क बना दी जाये, सिरसा से ऐलनाबाद की सड़क बना दी जाये जो कि आज तक नहीं बनी। मुझे यह बताया जाये कि कहां पर विकास हुआ। एक फ्लड़ी नहर बनी के पैरेलल बन कर पूरी तरह से तैयार है लेकिन उसमें अभी तक पानी नहीं छोड़ा

[डॉ० सुशील इन्दौरा]
गया है। इससे बड़ी चिन्ता की बात और क्या हो सकती है। चेयरमैन सर, सरकार कहती है कि प्रदेश में सौहार्दपूर्ण वातावरण है व्यापारी काम कर रहे हैं लेकिन हालात यह है कि व्यापारियों को तो सरेआम गोली मार दी जाती है।

श्री सभापति : इन्दौरा जी, आपका समय समाप्त हो गया है। डॉ० सीता राम जी, अब आप बोलिए।

डॉ० सीता राम : सभापति महोदय, मैं आज नहीं बोल पाऊंगा। इसलिए इन्दौरा साहब को ही समय दे दीजिए।

डॉ० सुशील इन्दौरा : सभापति महोदय, मैं बोल रहा ही हूँ इसलिए मुझे ही कुछ समय और दे दीजिए। ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना की बात की जा रही है लेकिन कहीं भी लोगों को काम नहीं दिया जा रहा। भारत निर्माण, ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के इतने बड़े-बड़े होर्डिंगज़ लगाये जाते हैं लेकिन हो तो कुछ भी नहीं रहा है। लोगों के कार्ड तक पूरे नहीं बने। कहीं-कहीं पर तो काम तक पूरा नहीं होता। इसी प्रकार से सरकार स्वच्छता की बात करती है। स्वच्छता के बारे में सरकार बताये कि सिरसा वालों को आज तक ट्रॉफी नहीं मिली। जब हिसार में महामहिम राष्ट्रपति जी आई थीं तो सिरसा वालों को वहां पर ठहरने के लिए स्थान तक नहीं मिला था। अगर आपको स्वच्छता देखनी है तो फतेहाबाद में नहर कालोनी के जो सरकारी मकान हैं उनके सामने सुबह 6 बजे देखो की स्वच्छता क्या चीज है?

श्री सभापति : आप चेयर को ऐड्रैस कीजिए।

डॉ० सुशील इन्दौरा : सभापति महोदय, पीने के पानी की और टंकियों की बात की जा रही है कि अनुसूचित जाति के लोगों को पीने के पानी का मुफ्त कनैक्शन और पानी की टंकी दी जाती है लेकिन यह भी गलत है क्योंकि दो-दो घरों के लिए एक ही पानी की टंकी लगाई जा रही हैं। अगर उनके टूवायलेट्स की बात करें तो वे ऊपर रखे हुए होते हैं और उनकी चारदिवारी तक नहीं बनाई जाती। आँकड़े पूरे कर लिए जाते हैं कि एक-एक घर में हमने स्वच्छता अभियान चलाया है। हर बार एक ही बात कह दी जाती है कि सरकार ने 1600 करोड़ रुपये के बिजली के बिल माफ कर दिये। इसी प्रकार से किसानों के 71 हजार करोड़ रुपये के कर्जे माफ करने की बात की जाती है। बिजली के बिल माफ तो दूर किसी का एक पैसा भी माफ नहीं किया गया। मुझे एक किसान मिल गया मैंने उससे पूछा कि आपका कितना पैसा माफ हुआ है तो उसने कहा कि मेरा तो 5 पैसे भी माफ नहीं हुए। कहाँ की सरकार, सरकार क्या कर रही है, सरकार बताये तो सही? आज सड़कों की बात की जा रही है, सड़कें बिल्कुल टूटी पड़ी हैं। कानून व्यवस्था की बात की जा रही है लेकिन उसका भी बुरा हाल है। आपके सामने खरक में लोग कुछ माँग कर रहे थे लेकिन उन पर गोलियाँ चलवा दीं। एक राजरानी थी उसको बिना बात के मार दिया। लोकतंत्र में कैसे अपने अधिकारों की बात करने वाले को मार दिया जाता है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सभापति महोदय, आपने डॉ० इन्दौरा जी को दो बार

एक्सटैंशन दे दी है लेकिन बहुत से सदस्य अब भी बाकी हैं, जो बोलना चाहते हैं। इसलिए आप उनके अधिकारों का भी ध्यान रखें।

श्री सभापति : इन्दौरा साहब, आप 45 मिनट बोल चुके हैं, आप कनक्लूड कीजिए।

डॉ० सुशील इन्दौरा : सभापति महोदय, मैं तो डेढ़ घंटा भी बोल सकता हूँ आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए मैं अपनी बात को खत्म कर लूंगा। आप से ज्यादा समय तो हमें माननीय अध्यक्ष महोदय ही दे दिया करते थे। आप तो पहली बार चेयर पर बैठे हैं आपको तो ज्यादा दरियादिल होना चाहिए। माननीय बिजली मंत्री जी से मेरा सवाल था कि बिजली के बिलों में पिछली बार का बिल जोड़ कर दे दिया जाता है और जब उसको ठीक करवाने के लिए जाओ तो उसमें भी सरकार का जवाब नहीं में होता है। सरकार द्वारा हकीकत जानने की बजाय लीपापोती की जाती है। अगर इसी प्रकार से लीपापोती की जायेगी तो हरियाणा नम्बर एक नहीं बन सकता। अगर हरियाणा को नम्बर एक राज्य बनाना है तो उसके लिए मेहनत करनी होगी और मेहनत करना कांग्रेस वालों के बस की बात नहीं है। कांग्रेस वाले तो ड्राइंग रूम में बैठकर फोली-फोली खा सकते हैं ये जनता का क्या भला कर सकते हैं? मेहनत तो हम जैसे लोग कर सकते हैं।

श्री सभापति : इन्दौरा साहब, आप खत्म करें। बहुत सारे मैम्बर्ज और भी बोलना चाहते हैं। अगर आप ही बोलते रहेंगे तो औरों को कैसे मौका मिलेगा?

डॉ० सुशील इन्दौरा : सभापति महोदय, मैं एक दो बात और कहना चाहता हूँ। एक तो मैं बी०पी०एल० पर बोलना चाहता हूँ और दूसरा 100-100 गज के प्लाटों के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ।

श्री सभापति : ठीक है, अगर बी०पी०एल० पर बोलना चाहते हो तो एक मिनट में बोल लो।

डॉ० सुशील इन्दौरा : सभापति महोदय, बी०पी०एल० के मामले में और पीने के पानी के मामले में हालत यह है कि लोग हर रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे पास ऐसे गांवों की लिस्ट हैं। (विघ्न) इन गांवों में पीने के पानी की बड़ी भारी किल्लत है। नेजियां खेड़ा गांव समाबास और चन्दकावास गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस लिस्ट में आने से रह गये हैं।

श्री सभापति : डॉक्टर साहब, आप इस बारे में सुझाव दें कि क्या किया जाये।

डॉ० सुशील इन्दौरा : सभापति महोदय, मैं सुझाव दे रहा था कि जो सही और वाजिब लोग हैं वे बी०पी०एल० की सूची में आने से रह गये हैं।

श्री सभापति : आप इस बारे में सुझाव दें कि सरकार क्या करें।

डॉ० सुशील इन्दौरा : चेयरमैन सर, वे लोग जो बी०पी०एल० की सूची में आने से

[डॉ० सुशील इन्दौरा]

वंचित रह गये हैं उनके नाम शामिल करने के लिए सरकार एक सही ऐजैंसी बनाए और जो लिस्ट बनी है उसकी जांच करवाएं। हालांकि सरकार इस प्रकार की कार्यवाही चार बार कर चुकी है। चार बार कार्यवाही होने के बावजूद भी यह विवाद अभी तक बना हुआ है। सरकार कोई सही ऐजैंसी गठित करके इसका सर्वे करवाए जो जायज और पात्र लोग हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए। जहां तक 100-100 गज के प्लॉट्स देने की बात है, वह एक ढकोसला मात्र है। सिर्फ गांवों की जमीनें हड़पने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। सिर्फ पंचायतों की जमीनों पर ही यह प्लॉट क्यों दिये जा रहे हैं। अगर सरकार ऐसे प्लॉट्स देना ही चाहती है तो जमीन खरीद कर प्लॉट्स दे। सभापति महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जहां बी०सीज० कैटेगरी में ए और बी का वर्गीकरण है वहां पर तो कोई विवाद नहीं है लेकिन एस०सीज० में ए और बी का वर्गीकरण करके एक रौला मचा दिया और यह कह दिया कि इसमें कोर्ट का मसला आ गया है। सरकार ने ऐसा क्यों किया, दो भाइयों को आपस में लड़ा दिया और एक विवाद खड़ा कर दिया। एस०सीज० की कैटेगरी बनी हुई थी और वह चल रही थी। (विघ्न)

श्री फूल चन्द मुलाना : सभापति महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। ये decision of the Court पर बात कर रहे हैं। इनका यह कहना है कि सरकार ने ए और बी वर्ग का झगड़ा करवा दिया। Sir, on a point of order मैं यह कहना चाहता हूँ कि this is the decision of the Court and not of the Government. सर, ये कह रहे हैं कि सरकार ने ए और बी का झगड़ा करवा दिया जब कि यह माननीय सुप्रीमकोर्ट का फैसला है कि there can be no caste within the caste. How can he say that Government is doing all this ? This is the wrong allegation and he should withdraw it.

डॉ० सुशील इन्दौरा : सभापति महोदय, अगर ऐसी बात है तो ए और बी कैटेगरीज भी संवैधानिक हैं। (विघ्न)

श्री सभापति : डॉक्टर साहब, आप सुझाव दीजिए कि इसमें क्या होना चाहिये ?

डॉ० सुशील इन्दौरा : सर, मेरे विचार से यह होना चाहिए कि ए कैटेगरीज वालों को भी कैटेगरी के हिसाब से लाभ दिया जाना चाहिए।

श्री सभापति : इन्दौरा साहब, ठीक है, अब आप अपनी सीट पर बैठें। अब श्री अरजन सिंह जी बोलेंगे। (विघ्न)

डॉ० सुशील इन्दौरा : सभापति महोदय, *** *** ***

श्री सभापति : इन्दौरा साहब, आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न) अरजन सिंह जी, आप बोलें। (विघ्न) इन्दौरा साहब आप बैठें। यह जो बोल रहे हैं वह रिकॉर्ड न किया जाए। Nothing to be recorded. (Interruptions) Indora Sahib, Please take your seat. Thank you very much. अरजन सिंह जी, अब आप बोलें।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

चौ० अरजन सिंह (छछरौली) : चेयरमैन साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। (विघ्न) चेयरमैन सर, सबसे पहले तो मैं मुआफी चाहूँगा कि उस दिन मैं भी उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ था जिनकी चर्चा हो रही थी। मेरा विश्वास कीजिए कि उस दिन जब महामहिम गवर्नर महोदय उठकर चले तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि सदन की कार्यवाही खत्म हो गई और अगले दिन सारा मामला डिस्कस होगा। उस दिन सारे के सारे सदस्य उठ लिये थे तो मैं यहां से उठ कर हुड्डा साहब के पास रोहतक चला गया था। उस दिन सदन से जाने के लिए मैं सौरी फील करता हूँ और उस दिन के श्रद्धांजलि प्रस्तावों के साथ मैं अपने आप को जोड़ता हूँ। मैं भी दिल की गहराइयों से दिवंगत आत्माओं के प्रति शोक प्रकट करता हूँ। अपने आप को चर्चा में जोड़ते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी बहुत ही महान और साधे इन्सान थे। अगर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो हमें उनके पदचिन्हों पर चलना चाहिए और जो उनकी भावना थी उसकी हमें कद्र करनी चाहिए। सभापति महोदय, आज मैं न तो कांग्रेस के पक्ष में कुछ कहूँगा और न ही विपक्ष के बारे में कुछ कहूँगा। (विघ्न) जो सच लगेगा उस पर सही बात कहूँगा और सही बात ही बताऊंगा। (विघ्न) सभापति महोदय, जहां तक चौधरी देवी लाल जी की बात है, डॉक्टर इन्दौरा जी, मैं उनकी दिल से कद्र करता हूँ। उन्होंने सरकार बनाने के लिए चाहे जो प्रोपेगेण्डा कर दिया होगा लेकिन उनकी आत्मा में कोई भी झूठी और लूट-खसोट की भावना नहीं थी। उनकी उसी भावना को लेकर लोगों ने उनको क्रैडिट दिया था और आगे उनके परिवार को भी क्रैडिट दिया था लेकिन उनके परिवार के लोगों ने जो किया उनको उसका नतीजा मिल गया। चेयरमैन सर, अब जनता इतनी भोली नहीं रही अब जनता सयानी हो गई है। एक समय वह था जब लोग एक-दूसरे के लिए जीते थे लेकिन अब लोग अपने लिए और अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए जीते हैं। वे अपने रास्ते पर रहते हैं कि हमें कहां फायदा हो सकता है और कहां नुकसान होगा। किसने लूटा, किसने खसोटा, किसने भला किया, हर आदमी आज अपने नफे नुकसान के साथ अटैच्ड है। इन्दौरा साहब पिछली सरकार का गुणगान कर रहे हैं मेरे ख्याल में यह उस समय सरकार में नहीं थे। अगर ये उस समय सरकार में होते तो उस सरकार को कुछ न कुछ सुझाव देते और उनको कुछ न कुछ समझाते लेकिन उस समय वे यहां पर नहीं थे और आज ये अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। वे इनकी बात सुनते या न सुनते यह तो उनकी भावना थी लेकिन ये अच्छी सलाह उनको देते। इन्दौरा साहब यहां पर नहीं थे। जहां तक इन्होंने फसलों की बात कही कि जीरी कम रेट पर गई है। पिछली सरकार में और इस सरकार में मैं तुलना करूं तो पिछली सरकार में व्यापारियों से पूछा जाता था और जो गवर्नमैंट रेट होते थे उससे कम में बोली हो जाती थी। 100-100 रुपये प्रति क्विंटल के कम रेट मिलते थे। चेयरमैन सर, एक-एक किल्ले में 5-5 हजार रुपये का नुकसान इनके समय में होता था जो आज ये तुलना कर रहे हैं। आज ये कह रहे हैं कि 25,000 रुपये की बिकनी चाहिए थी जबकि उस पर 18 हजार रुपये का खर्च हुआ है। ये बातें पिछली सरकार के वक्त में इनको क्यों याद नहीं आई। जहां तक पानी की बात है, आज ये लोगों से जाकर पूछें। इस सरकार ने लोगों के घरों में 5-5 और 6-6 हजार रुपये की पानी की टंकी लगवा दी है। इनके समय में तो एक पैसा भी इस काम के लिए खर्च नहीं किया गया था। इन्होंने तो मट्टी का दोना भी किसी को नहीं दिया था। यहां

[चौ० अरजन सिंह]

तक कि जो मटके रखे हुए थे वे भी इन्होंने फुड़वा दिए थे। कभी मटका फोड़, बंटा फोड़, कभी सड़क फोड़। मेरे कहने का मतलब है कि इन्होंने तोड़ने-फोड़ने का ही काम किया है। इन्होंने कभी भी जोड़ने का काम नहीं किया है। एक टाईम में पॉपुलर के रेट 550 रुपये से 600 रुपये क्विंटल तक चले गए थे और इनके समय में 150 रुपये क्विंटल तक लाकर किसानों की लुटाई हुई थी। लुटाई, किराए वाले के किराए को देकर, आढ़ती को देकर, काटने वाले को देकर और जो खूंटे पीछे लगाकर ट्राली वाला ले जाता था सिर्फ वही बचते थे इससे फालतू कुछ नहीं बचता था। आज मैं इस सरकार की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। आज वही पॉपुलर का रेट 800 रुपये क्विंटल तक जा रहा है। वही ट्राली जो पहले 12,000 में ली जाती थी वह ट्राली आज 80,000 से 90,000 की लोग बेच रहे हैं। इनके वक्त में 50-50 और 60-60 हजार रुपये एक-एक ट्राली में किसानों को नुकसान हुआ था। गन्ने के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि जो ट्राली आज 10,000 रुपये में जा रही है इनके वक्त में वही ट्राली 4000, 4500 और 4600 रुपये में जाती थी। सभापति महोदय, जहां तक आज ये नहरों की बात करते हैं आज इनको नहर याद आ रही है। इस सरकार के आने से पहले साढे पांच साल हरियाणा स्टेट में इनकी सरकार थी, उस वक्त इन्होंने नहरों के बारे में कुछ नहीं किया। तब क्या हरियाणा में पानी की जरूरत नहीं थी। तब चाहे पानी बादल ले जाए या धरती पी जाए। (विघ्न) मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ। मैं तो उस बात के बारे में कह रहा हूँ जो बात आपने कही थी। जहां तक बिजली की बात है, इस सरकार ने जब इलैक्शन लड़ा था तो इनके किसी भी आदमी ने इस बारे में कोई बात नहीं कही थी, कोई वायदा नहीं किया था। इन्दौरा जी, आपकी पार्टी की तरह नहीं जो आपने बिजली के नाम पर वोट बटोरने का काम किया था। आपकी पार्टी ने तो यह कहा था कि जब तक हमारी सरकार नहीं आएगी तब तक किसी ने भी बिजली के बिल नहीं भरने हैं। तब तक किसी के पैसे नहीं देने हैं। चेयरमैन सर, आज भी वही लोग धमकी देते हैं जिन्होंने किसी का ले कर देना नहीं है वर्ना और किसी में कोई आक्रोश नहीं है। पता नहीं ये किस का आक्रोश बता रहे हैं। आज एक-एक गांव में शान्ति है। ये कहते हैं कि आज सड़कों पर आक्रोश हो रहा है। आज ये सड़कों पर चलते हैं तो ये न तो किसी ट्रक वाले को न ही किसी ट्रैक्टर वाले को आगे निकलने देते हैं। इनकी वजह से उन लोगों में आक्रोश है जिनको दो किलोमीटर जाना है या उसकी बजाए 20-20 किलोमीटर दूर से घूम कर जाना पड़ रहा है। (विघ्न) सभापति महोदय, जहां तक बिजली की बात है, मुख्यमंत्री जी ने और इनकी सरकार ने सबसे पहले बिजली के ऊपर ध्यान दिया है। सभापति महोदय, वोट लेने के लिए सभी इलैक्शनों के समय में घोषणा करते हैं लेकिन इस सरकार ने ऐसी घोषणा नहीं की थी। इस मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले कुर्सी पर बैठते ही बिजली बनाने का काम शुरू किया। मैं इनको यह कहना चाहता हूँ कि जो बिजली बन रही है वह देने के लिए ही बन रही है। अगर किसी के घर में धुंआ नहीं उठ रहा हो तो उस घर से रोटी की क्या उम्मीद करेंगे। जिस घर से धुंआ उठ रहा हो उससे उम्मीद होती है कि आधे घंटे में, एक घंटे में नहीं तो दो घंटे में रोटी जरूर मिल जाएगी। आदमी सब्र तो करे। इनको तो वह सब्र भी नहीं है। बिजली बन रही है और वही लोगों को मिलेगी। (विघ्न) चेयरमैन सर, मैं ईमानदारी से एक बात सदन में कहना चाहता हूँ

कि आज लोग पॉपुलर लगा रहे हैं और पॉपुलर लगाने वालों में चर्चा हो रही है और वे उस बारे में जवाब भी दे रहे हैं। वे कहते हैं कि भई पॉपुलर तो लगाने लग रहे हैं, देख लो कहीं वो हट कर गा आ जाए। इसका जवाब लोग देते हैं कि हमने उसको वोट ही नहीं देने हैं तो वह कहां से आएगा। मतलब यह कि लोग पॉपुलर लगाते हैं लेकिन उनमें यह भय अब भी बना रहता है कि कहीं बाद में ये लोग लौटकर सत्ता में आ कर लूट खसौट करके न ले जाएं। (विघ्न) चेयरमैन सर, मैं तो यह कहूँगा कि जिस नियत से यह सरकार चल रही है उसको देखते हुए हम तो यह कहेंगे कि परमात्मा इन्हें और मजबूती दें, ताकत दें। (विघ्न) चेयरमैन सर, पिछली सरकार के समय में तो मेरे क्षेत्र से 50-60 टन का लोड गाड़ियों में भरकर ले जाते थे जिसकी वजह से वहां की सारी सड़कें टूट गयी। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि सड़कों की जहां तक बात है ओवर लोड की वजह से जो सड़कें वहां पर टूट रही हैं उनकी तरफ भी सरकार ध्यान दें। चेयरमैन सर, बाकी किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है राम राज्य है सब लोग खुश हैं क्योंकि यह बहुत बढ़िया सरकार है। मैं केवल आपके मुंह पर ही यह बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि जो सच्चाई है यह आपको बता रहा हूँ। लोग यह बात अपने अंदर से बोल रहे हैं। लोगों को पता है कि किस ने हमारे सिर पर लट्ठ मारा है। अगर किसी ने उनको कुछ दिया है तो वह उसको भी याद करते हैं। चेयरमैन सर, अब लोग सब बातें जानते हैं। हर आदमी अपना दिमाग रखता है और हर आदमी की अपनी सोच है। चेयरमैन सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का टाईम दिया।

श्री रामफल चिड़ाना (बरोदा, अनुसूचित जाति) : चेयरमैन सर, आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का जो मौका दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ा है उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो किसान हितैषी, मजदूर हितैषी हो या कुछ भी ऐसा किया गया हो जो सराहनीय हो। चेयरमैन सर, मैं बताना चाहूँगा कि पिछली जीरी का जब मौसम था तो भगवान की कृपा से बड़ी अच्छी फसल हुई थी लेकिन बीमारी बहुत ज्यादा लग जाने के कारण वह पकी पकायी फसल देखते-देखते ही खराब होती चली गयी। सरकार ने क्या किया उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक जीरी की फसल खराब हो गई उसको मुआवजा देना तो दूर की बात है, नुकसान का सर्वे तक नहीं करवाया गया, गिरदावरी तक नहीं करवायी गयी। चेयरमैन सर, एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम किसान हितैषी हैं और दूसरी तरफ मुआवजा स्कीम होने के बावजूद भी किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। पहले लोग कहते थे कि हुड्डा तेरे राज में जीरी गयी जहाज में और अब क्या हुआ, अब लोग कहते हैं कि हुड्डा तेरे राज में जीरी गयी ब्याज में। चेयरमैन सर, गोहना तहसील में भी किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी थी। यह रिकॉर्ड की बात है।

श्री फूलचन्द मुलाना : चेयरमैन सर, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। सर, नारा यह था कि चौटाला तेरे राज में जीरी गयी ब्याज में और पराली गयी लिहाज में। जबकि हमारी सरकार में यह नारा इस प्रकार है कि हुड्डा तेरे राज में जीरी गयी जहाज में; क्योंकि हमारी सरकार ने पैडी 1121 पूसा का एक्सपोर्ट खुलवा दिया था। सर, मैं इनकी बात को सही कर रहा हूँ।

श्री रणदीप सिंह सूरजेवाला : चेयरमैन सर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि इस बार जो जीरी का भाव था शायद किसान को इतना भाव कभी नहीं मिला है। कांग्रेस की हरियाणा की सरकार और चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की इंटरवैंशन के चलते देश की सरकार ने पैडी 1121 पूसा को भी बासमती डिक्लेयर किया। यह अपने आप में बहुत अनूठी बात है। चेयरमैन सर, फिर भी किसी सुस्त आदमी ने अगर अपनी यह वैरायटी न बेची हो तो अलग बात है। 3300 रुपये पर पैडी 1121 पूसा बिकी है जबकि 1200 रुपये पर बासमती इनके समय में बिकी थी। इसलिए यह फर्क है।

श्री रामफल चिड़ाना : चेयरमैन सर, सौभाग्य से मैं भी किसान हूँ और मैंने भी जीरी लगा रखी थी इसलिए मुझे पता है। होता यह है कि यदि किसी बड़े खरीददार ने एक ढेरी की बोली 2700 रुपये लगा दी तो अगले दिन उसकी कुछ और बोली लग जाती है। कोई नियम नहीं है कोई कायदा कानून नहीं है। यदि एक किल्ले की जीरी पांच जगह पर रख दी जाए तो पांचों ढेरियों के अलग-अलग रेट की बोली लगती हैं। बोली लगाने वालों को जीरी की कोई पहचान नहीं होती क्योंकि उनको पता नहीं कि किसान जीरी की फसल कैसे तैयार करता है। यदि एक किल्ले की जीरी की अलग-अलग पांच ढेरी बना दी जाए तो एक ही बीज से पैदा की उन पांचों ढेरियों के रेट अलग-अलग लगाए जाते हैं। एक दिन भाव कुछ होता है अगले दिन भाव कुछ और होता है। कई-कई दिन में किसान को अपनी जीरी बेचनी पड़ती है। आप कुछ कहेंगे, हम कुछ कहेंगे और सरकार कुछ भी कहें लेकिन सही बात तो लोग बताएंगे। लोगों ने सोचा कि जीरी रख लेते हैं मजबूरी थी। जो यह 1121 किस्म की बात करते हैं। 600 रुपये प्रति क्विंटल में भी उसका कोई खरीददार नहीं था। किसान की मजबूरी होती है। गेहूं भी साथ बीजना पड़ता है। जब भाव मिलने की बात थी तो 800 रुपये ऐक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी जिससे किसान को कम रेट मिले। किसान ने क्या कसूर कर दिया था कि अपने घर में जीरी रख दी। रखनी इसलिए पड़ी क्योंकि कोई खरीदने वाला नहीं था।

श्री रणदीप सिंह सूरजेवाला : चौधरी रामफल चिड़ाना जी, जिस ड्यूटी की बात आप कह रहे हैं भारत सरकार ने वह ड्यूटी वापस ले ली है।

श्री रामफल चिड़ाना : चेयरमैन सर, वह तो बहुत बाद में वापस ली गई है। दलित बिरादरी की बात करते हैं। मैं दलित बिरादरी से हूँ मुझे पता है कि क्या कुछ होता है। गरीब आदमियों के पास हम जाते हैं तो वे रोते हैं और हमारे प्रधान जी कह रहे थे कि पानी की टंकी दी हैं, टूंटी दी हैं। पानी की टंकी से क्या होगा अगर वह खाली पड़ी रहे। खाने को उनके पास कुछ है नहीं। यह ठीक है कि किसानों के लिए भाव बढ़ाया है लेकिन यह बताएं कि गरीब आदमी के लिए गेहूं का क्या प्रबन्ध किया है। क्या गरीब आदमी 11-12 रुपये किलो गेहूं खरीद कर खा सकता है। हम इस हक में हैं कि किसान को ठीक रेट मिलना चाहिए लेकिन सच्चाई तो यह है कि गरीब आदमी को कोई लाभ नहीं मिलता है। प्लाटों की बात कही गई है। (विघ्न)

श्री सभापति : चिड़ाना साहब, आप इधर देखिये और बोलिये।

श्री रामफल चिड़ाना : चेयरमैन सर, बी०पी०एल० कार्डों का 4-4 बार सर्वे हो रहा है और बहुत से लोगों के बी०पी०एल० कार्ड बने हुए थे लेकिन अब उनके नाम काट दिये गये हैं। इसके अलावा गरीब आदमी को अपमानित करने का और क्या साधन होगा कि उसके घर के बाहर दीवार पर लिख दिया गया है कि बी०पी०एल० परिवार। ऐसे में कोई व्यक्ति किसी के घर अपनी लड़की के रिश्ते के लिए जाएगा तो बाहर दरवाजे से देखकर ही लौट आएगा और कहेगा कि यह तो रजिस्टर्ड गरीब है, रजिस्टर्ड कंगाल है इसके घर कौन अपनी बेटी को ब्याहेगा। वैसे भी यह कार्ड बनाए जा सकते थे। चेयरमैन सर, अब मैं एक विशेष बात पर आता हूँ। भर्ती के मामले पर आता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी गोहाना में और सोनीपत में जाते हैं और कहते हैं कि गोहाना मेरा, सोनीपत मेरा और मैं गोहाना और सोनीपत का। सूचना के अधिकार के तहत हमने पता किया, हमारे एक वकील साथी ने पता किया। वह कागज मेरे पास है और आप चाहें तो यह कागज मैं सदन के पटल पर भी रख सकता हूँ। उन्होंने पता किया कि पुलिस के छह हजार जवानों की भर्ती हुई और उसमें सोनीपत जिले के ऐड्रस पर मात्र तीन आदमी ही भर्ती हुए।

चौ० जगबीर सिंह मलिक : सभापति महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। मेरे लायक दोस्त कह रहे हैं कि सिर्फ तीन आदमियों की सोनीपत से भर्ती हुई। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि मैंने 30 आदमियों की लिस्ट अखबार में जारी की थी। शायद इन्होंने अखबार नहीं पढ़ा होगा। 145 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी कैरेक्टर वैरीफिकेशन हुई है। यह रिकॉर्ड सिटी पुलिस स्टेशन में मौजूद है और माननीय सदस्य के वहां के पुलिस स्टेशन में भी यह रिकॉर्ड मौजूद है कि 150 लोगों की भर्ती हुई है जिसमें से 45 आदमी उसमें इनके सब डिवीजन के पुलिस में भर्ती हुए हैं।

श्री रामफल चिड़ाना : यह रिकॉर्ड की चीज है। मैं बगैर रिकॉर्ड के नहीं बोल रहा हूँ। इतने बड़े सोनीपत जिले से 3 आदमियों की भर्ती हो और मुख्यमंत्री कहते हैं कि गोहाना मेरा, सोनीपत मेरा और मैं गोहाना और सोनीपत का। मैं यहां का विकास नहीं कर सकता तो और कौन करेगा?

श्री सभापति : आप सुझाव दीजिए कि इसके लिए क्या करें?

चौ० जगबीर सिंह मलिक : सभापति महोदय, यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं भर्ती हुए लोगों के नाम दे देता हूँ।

श्री सभापति : मलिक साहब, इनको आप लिस्ट दे देना, ये वैरीफाई कर लेंगे।

श्री रामफल चिड़ाना : सभापति महोदय, यदि मलिक साहब के कहे मुताबिक बात हम मान लें तो उस हिसाब से भी किलोई हल्के में से और रोहतक हल्के के गांवों से 70-70 आदमी लगते हैं और हमारे सब डिवीजन से 30-35 आदमी लगते हैं तो यह कहां का न्याय है। कहां का गोहाना और कहां का सोनीपत मुख्यमंत्री जी का हुआ। मैं एक बात कहना चाहूँगा जो रिकॉर्ड की बात है। सभापति महोदय, हम बड़े खुश हुए थे जब यह घोषणा की गई थी कि खानपुर कलां गुरुकुल को यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है। बड़ी उम्मीद थी कि हमारे जिले सोनीपत के बहुत लड़के नौकरी लगेंगे। चेयरमैन साहब,

[श्री रामफल चिड़ाना]

सोनीपत जिला एजूकेशन के मामले में हमेशा से ही अग्रणी रहा है। यह रिकॉर्ड की बात है। इस बारे में सूचना के अधिकार के तहत पूछा गया कि खानपुर यूनिवर्सिटी बनने के बाद सोनीपत जिले के कितने बच्चे नौकरी लगाये गये हैं। उसके बारे में लैटर आया जिसमें यह बताया गया कि अब तक 27 लैक्चरर्ज की भर्ती की गई है जिनमें से सोनीपत जिले का एक और दस हरियाणा से बाहर के लैक्चरर्ज भर्ती किए गये हैं। हरियाणा में भी क्या इतने योग्य लड़के नहीं हैं कि बाहर से लगाने पड़े। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी बड़े जोर-शोर से कहते हैं कि हम हरियाणा के बच्चों को नौकरी पर लगायेंगे और फिर बाहर के बच्चों को नौकरी पर रखा जा रहा है।

श्री जगबीर सिंह मलिक : सभापति महोदय, इसके बारे में मैं जवाब देना चाहूँगा।

श्री सभापति : चौधरी साहब, आप नोट कर लो बाद में इकट्ठा जवाब दे देना।

श्री रामफल चिड़ाना : सभापति महोदय, वहां पर हमें हमारा हक मिलना चाहिए हमारे साथ क्यों ऐसा दोगला व्यवहार किया जा रहा है। जहां तक कानून-व्यवस्था की बात करते हैं, सभापति महोदय, 4 दिसम्बर, 2008 को सत्याराम नाम का ए०एस०आई० जो मेरे हल्के बड़ौदा का था। गांव पटवाड़ा में उसकी हत्या कर दी गई और उस बेचारे का परिवार दर-दर की ठोकरें खा रहा है लेकिन उसके हत्यारों का आज तक पता नहीं लगा है। उस ए०एस०आई० को गोली मार कर मार दिया गया। ये कानून-व्यवस्था की बात करते हैं और पुलिस के आदमियों को सरेआम मार दिया जाता है। एक ए०एस०आई० और उसकी घरवाली को गोलियां मारी गईं उन हत्यारों का आज तक पता नहीं लगा। कानून-व्यवस्था की डिटेल में जाता हूँ तो आप मुझे रोकते हैं। माननीय सदस्य जी बार-बार बोल रहे हैं मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा एक मामला उन्हीं के गाँव का है। सूबेदार मेजर जयकरण जिसको उसके कार्यों के लिए राष्ट्रपति जी ने प्रशस्ति-पत्र दिया था वे इतने योग्य आदमी थे उनका 31.8.2005 को इनके गाँव के पास ही कत्ल हुआ था। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कितने दलित हितैषी हैं क्योंकि वह दलित बिरादरी का आदमी था। वह कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी के पैट्रोल पम्प पर काम करता था इसलिए उस बात को दबा दिया गया। जिस आदमी को राष्ट्रपति ने अवार्ड दे रखा हो उसकी भी मौत का पता न लगे यह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

श्री सभापति : चिड़ाना साहब, कन्कल्यूड कीजिए क्योंकि हाउस का समय खत्म होने में केवल दो मिनट ही रह गये हैं।

श्री रामफल चिड़ाना : सभापति महोदय, मुझे पता था कि आप मुझे ऐसे समय में बोलने के लिए समय देंगे। मेरे पास मसाला ही इतना था। हमारे साथ आप ऐसा ही करते हैं। आप हमारे दलितों की बात सुनें। सरकार के समय में जो हुआ है मैं वही बात बता रहा हूँ।

श्री सभापति : चिड़ाना साहब, कन्कल्यूड कीजिए क्योंकि हाउस का समय खत्म होने में केवल दो मिनट ही रह गये हैं।

श्री रामफल चिड़ाना : सभापति महोदय, आप समय को एक्सटैंड भी कर सकते हैं। जब मेरी बात पूरी नहीं हुई है तो मैं कन्कल्यूड कैसे करूं। स्पीकर सर, जिस आदमी को राष्ट्रपति ने अवार्ड दे रखा हो और उस आदमी की हरियाणा में लेज धार हथियारों से हत्या कर दी जाए। इस बारे में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है लेकिन उसके हत्यारों का अता-पता नहीं चले यह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

श्री सभापति : चिड़ाना साहब, कन्कल्यूड कीजिए।

श्री रामफल चिड़ाना : सभापति महोदय, आप हमें बोलने से रोक सकते हैं लेकिन जनता जब बोलेगी उसको आप नहीं रोक सकेंगे। जनता सब कुछ हिलाकर रख देगी।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सभापति महोदय, हाउस का समय बढ़ा दीजिए। माननीय चिड़ाना जी अच्छा बोल रहे हैं चाहे गलत ही क्यों न बोल रहे हों।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Chairperson : Is it the sense of the House that the siting of the House be extended for 5 minutes ?

Voices : Yes, yes.

Mr. Chairperson : Hon'ble Members, the sitting of the House is extended for 5 minutes.

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री रामफल चिड़ाना : सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे भाई उदयभान जी ने भी अपनी बात कही। यहां कितने दलित सदस्य हैं। लेकिन कोई भी दलित की बात नहीं उठाता। सभापति महोदय, नौकरियों में रिजर्वेशन का बैकलॉग बहुत है। केवल पानी की टूंटी देने से, बी०पी०एल० कार्ड देने से हमारा भला नहीं होगा। हमें नौकरियां देने से हमारा भला होगा। मैं जब नौकरी पर था तो हमने कस्टोडियन की 14 एकड़ जमीन बोली पर खरीद ली थी। यदि हमारे भाइयों को नौकरियां न मिलें तो वे गंदी बस्तियों में 100-100 गज के प्लाट लेकर क्या करेंगे। वे अपने आप से मॉडल टाउन में और हुड्डा के सैक्टर्ज में प्लाट ले लेंगे। सभापति महोदय, ये हमें बहकाना चाहते हैं। जिस तरह अभी गैस्ट टीचर्स की बात यहां आई थी। हमारे प्रधान जी ने 20 हजार गैस्ट टीचर्स लगाए लेकिन उनमें रिजर्वेशन का नाम नहीं। सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है कि ये रैगुलर भर्ती कर सकें। स्टाफ सिलैक्शन कमीशन ने 4 साल से कोई भर्ती नहीं की। यह सरकार के लिए दुर्भाग्य की बात है। हमारे बच्चों के रोजगार का कितना नुकसान हुआ है। यह रोजगार का नुकसान सरकार ने किया है न कि किसी और ने। क्या हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं। सभापति महोदय, ये ग्रेस मार्क्स देकर शिक्षा की बात करते हैं। मैं तो कहूँगा कि ग्रेस मार्क्स देने से तो अच्छा है कि अगर सरकार स्कूलों में अध्यापक भर्ती नहीं कर सकती तो सरकार को वे स्कूल बन्द कर देने चाहिएं। हमारे बच्चे ग्रेस मार्क्स के

[श्री रामफल चिड़ाना]
भूखे नहीं हैं। उन्हें अच्छी एजूकेशन दो, अच्छे टीचर्स दो और उन्हें अच्छा माहौल दो ताकि वे अच्छे से अच्छा पढ़कर कम्पीटिशन में भाग ले सकें क्योंकि आज कम्पीटिशन का जमाना है। जो बच्चे कम्पीटिशन में भाग लेकर आगे बढ़ेंगे वही बच्चे तरक्की करेंगे। ग्रेस मार्क्स देने से कैसे कोई आगे बढ़ सकता है। ग्रेस मार्क्स देने से तो कोई एजूकेशन की दहलीज भी पार नहीं कर सकता। जब हमारा टाईम था तो कोई ग्रेस मार्क्स नहीं होते थे। स्कूलों में पूरे टीचर्स हुआ करते थे।

श्री सभापति : रामफल जी, आप कन्क्लयूड करें।

श्री रामफल चिड़ाना : सभापति महोदय, या तो मुझे बोलने के लिए टाईम मत दें और अगर टाईम दे रहे हो तो पूरा बोलने दो। सभापति महोदय, मैं दलितों की बात कर रहा हूँ। क्या दलितों की बात आपको अच्छी नहीं लगती। गैस्ट टीचर्स की मैंने यहां बात की। पब्लिक हैल्थ में कितने लोग लगाए गए, क्या उनमें कोई रिजर्वेशन दी गई, नहीं रिजर्वेशन का कोई नाम नहीं। सभापति महोदय, दलितों को 100-100 गज के प्लाट देने के बारे में इन्दौरा जी कह रहे थे कि हरियाणा न्यूज पर ये कहते हैं कि हमने दलितों के लिए यह कर दिया, वह कर दिया जबकि प्रैक्टिकली क्या किया है यह आप जाकर देख लें। जहां प्लाट दिए गए हैं उन बस्तियों में इतनी बदबू आती है कि आपमें से कोई वहां जा नहीं सकता। आपको वोट मिल जाते हैं। अबकी बार मंहगाई में आपको पता लगेगा कि दलित लोगों के वोट कैसे मिलते हैं। सभापति महोदय, यहां सड़कों की बात आई। हरियाणा में सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। सारे प्रश्नकाल में सड़कों के बुरे हाल के बारे में चर्चा चल रही थी और सभी माननीय सदस्य मान रहे थे कि सड़कों का बुरा हाल है। परिवहन मंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा और जानना भी चाहूँगा कि हमारे राज में डीलक्स बसें चलीं थीं। सभापति महोदय, मंत्री जी का तो बहुतेरा जुगाड़ है ये तो कारों में चलते हैं लेकिन मैं तकरीबन बसों में चलता हूँ। बसों का बहुत बुरा हाल है। मैं तो यह कहूँगा कि हरेक सरकार अपने मंत्रियों पर यह कंडीशन लगाए कि वे बसों में जाकर देखें कि बसों का क्या हाल है। पब्लिक को बसों में क्या-क्या कठिनाइयां होती हैं। हमारे टाईम में डीलक्स बसों में टी०वी० होते थे लेकिन आज वहां टी०वी० की जगह कागज भरे हुए हैं। क्या डीलक्स बसें इसलिए बनाई गई थीं कि उनमें टी०वी० की जगह कागज भरे जाएं। क्या सरकार के पास टी०वी० रिपेयर के लिए भी पैसे नहीं हैं। बसों की खिड़कियां टूटी हुई हैं तथा और भी कोई चीज ठीक नहीं है। परिवहन मंत्री जी, आप चल कर देख लें कि बसों का क्या हाल है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : रामफल जी, आप कन्क्लयूड करें तथा गवर्नर एड्रैस पर ही बोलें।

श्री रामफल चिड़ाना : सभापति महोदय, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि ये कहते थे कि गोहाना को हम अच्छा बना देंगे। गोहाना में सीवरेज की पाइपस बिछनी थी। माननीय सदस्य बैठे हैं, ठीक है कि इनको अपने मकान के आगे से चलने का स्थान मिल गया। ये 8 महीने से कह रहे थे कि 15 दिन में सड़क बनवा देंगे और सीवरेज के पाइप डलवा देंगे। अब ये एम०एल०ए० बन गए हैं, इनके मकान के आगे छोड़कर बाकि सारी

सड़क 8 महीनों से फटी पड़ी हुई है चाहे तो मैं कल इसका फोटो [illegible] ले आऊंगा।

श्री जगबीर सिंह मलिक : सभापति महोदय, ...

श्री सभापति : जगबीर सिंह जी क्या आपने जवाब [illegible] जी, आपका समय पूरा हो गया। (विघ्न)

श्री जगबीर सिंह मलिक : सभापति महोदय, मुझे पूरा जवाब [illegible] में आज सारी सड़कों पर काम चल रहे हैं। ये गोहाना से बाहर रहते हैं इनको गोहाना के बारे में पता नहीं है। गोहाना में करोड़ों रुपये की लागत से ड्रेनेज सिस्टम के काम चल रहे हैं।

Mr. Chairperson : The time is over. Now, the House is adjourned till 2.00 P.M. on Thursday, the 12th February, 2009.

*18.35 hrs.

(The Sabha then *adjourned till 2.00 P.M. on Thursday, the 12th February, 2009).

Haryana Vidhan Sabha Secretariat ★ LIBRARY ★ Chandigarh